नवम माला, खंड 14, अंक 7

मंगलवार, 5 मार्च, 1991
14 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खण्ड 14 में अंक 1 से 11 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद- विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 5 मार्च, 1991/14 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
24	नीचे से पंक्ति 4	"श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्लो रामचन्द्रन" पढ़िये ।
48	नीचे से पंक्ति 5	मंत्री जो के नाम के पश्चात "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।
51	9	मंत्री जो के नाम के पश्चात "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।

विषय सूची

नवम् माला, खंड 14, सातवां सत्र, 1991/ 912 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 5 मार्च, 1991/14 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-8
*तारांकित प्रश्न संख्या : 121	2
महासचिव द्वारा घोषणा	8-169
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 122 से 140	8-18
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1358 से 1419, 1421 से 1562 और 1564 से 1589	18-169
सभा पटल पर रखे गए पत्र	170-171
याचिका	
समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत नियुक्त आंगनवाड़ी सहित कर्मकारों की मांगों तथा शिकायतों के बारे में	171
पंजाब बजट—1991-92	171
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब)—1990-91	171
विवरण	
जम्मू-कश्मीर बजट—1991-92	172
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर)—1990-91	172
विवरण	
असम बजट—1991-92	172
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम)—1990-91	172
विवरण	
तमिलनाडु बजट—1991-92	173

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु)—1990-91	173
विवरण	
पांडिचेरी बजट—1991-92	173
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी)—1990-91	173
विवरण	
नियम 377 के अधीन मामले	174-175
(एक) विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत गांवों में कुएं खुदवाने और पाइप लाइन डलवाने हेतु बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की राशि बढ़ाए जाने की मांग	
श्री हरि शंकर महाले	174
(दो) राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर जिलों को सिंचाई के लिए भाखड़ा और गंग नहरों से पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग	
श्री शोपत सिंह मक्कासर	174
(तीन) 1981 में जारी किए गए वाहक बन्ध पत्रों की कालाबाजारी रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग	
श्री सनत कुमार मंडल	175
(चार) नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में जसपुर विकास खंड के मोगपुर और तुमडिया के ग्रामवासियों के नाम पर भूमि को नियमित किए जाने की मांग	
श्री एम०एस० पाल	175
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	175-182
श्री सूर्य नारायण यादव	176
श्री ए०एन० सिंह देव	177-178

लोक सभा

मंगलवार 5 मार्च, 1991/14 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है । ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपने इसका अनुमान कर लिया होगा कि ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुद्दा क्या है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे बताने दें। महोदय, कल आपने हमारे नेता, श्री राजीव गांधी के घर पर हुई जासूसी पर सदन की भावना का अनुमान कर लिया होगा, ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई मुद्दा नहीं है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह स्पष्ट है ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताएं कि मुद्दा क्या है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह स्पष्ट है कि किसी सक्षम राजनैतिक नेता की अनुमति के बिना यह नहीं हो सकता था और यहां हम केन्द्रीय सरकार और प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। कार्य करने का यह तरीका संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना और राजनैतिक दलों की स्वतंत्र कार्य-प्रणाली पर प्रहार करता है ···(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : किन्तु आप उसी का समर्थन कर रहे हैं ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें । यह प्रश्न काल है, श्री कुरियन ···

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, हम दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग करते हैं और जब तक ऐसी कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक हम सभा से बाहर जाने और सभा से अनुपस्थित रहने पर बाध्य हैं ।

इस समय प्रो० पी०जे० कुरियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री छेदी पासवान ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बंगलौर विमान दुर्घटना संबंधी न्यायिक समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

*121. **श्री छेदी पासवान** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1990 में बंगलौर में हुई विमान दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त न्यायिक समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उन लंबित सिफारिशों का ब्योरा क्या है जिन पर सरकार को अभी कार्यवाही करनी है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग). जांच न्यायालय ने 62 सिफारिशें की हैं। जांच न्यायालय की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों सहित यह रिपोर्ट संसद में 10-1-1991 को रख दी गई थी। सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० विप्लव दासगुप्त; यह प्रश्न काल है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, आज के इंडियन एक्सप्रैस में आया है ···(**व्यवधान**) मेरा पाइंट आफ आर्डर है। ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा का कार्य करें। श्री पटनायक, हम सभा के कार्य को आगे बढ़ाएं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री विप्लव बाबू और श्री शिवाजी पटनायक, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

डा० विप्लव बासगुप्त : महोदय, हम एक स्थगन प्रस्ताव रख रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं हाउस को सुचारु रूप से चलाने के लिए आडवाणी जी को बुला रहा हूं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये विरोधी दल के नेता हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : साधारणतया मैं प्रश्नोत्तर काल में कभी भी दूसरा विषय नहीं उठाता, आपसे यही निवेदन करता हूं कि प्रश्नोत्तर चलने दीजिए। किन्तु आज जो कुछ हुआ है वह बहुत गम्भीर है, अनप्रीसीडैन्टेड है और आखिर सदन में कोरम बनाए रखने की रिसपोंसीबिलिटी विपक्ष की नहीं है। यह रिसपोंसीबिलिटी या तो सरकारी पक्ष की है या सरकारी पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टी की है। इस विषय में कल चर्चा हो चुकी थी, पूरे सदन ने इस पर चिन्ता प्रकट की और प्रधानमंत्री जी ने जब यह कह दिया कि वे इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करके सदन को बताएंगे तो सबने मान लिया था कि वह परिच्छेद समाप्त हो गया है। आज उसी परिच्छेद को फिर से उठाकर कांग्रेस पार्टी ने बहाना बनाकर सदन का जो त्याग किया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी गैरजिम्मेदारी का प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह सरकारी पक्ष से है। क्या सरकारी पक्ष और समर्थक पक्ष का सम्बन्ध इसी प्रकार से बना रहेगा? उसके कारण संसद भी ठीक तरह से नहीं चल रही है, सरकार भी ठीक तरह से नहीं चल रही है और देश की दिशा भी ठीक नहीं हो रही है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सरकारी पक्ष को भी पुनर्विचार करना चाहिए और कम से कम यह जो सम्बन्ध है वह संसद के लिए उचित नहीं है। इसी कारण मैंने टिप्पणी की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री इंद्रजीत, आप बैठिए, मैं आपको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने अभी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है "कि यह सभा लोक सभा के सदस्य श्री राजीव गांधी के घर की निगरानी को रोकने में सरकार की अक्षमता की भर्त्सना करती है।" मेरी मांग है कि इस पर तुरंत चर्चा की जाए। महोदय, इस पर आपकी व्यवस्था क्या है। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इंद्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आपको ऐसा लगता है कि अभी जो आडवाणी जी ने कहा कि कल यहां प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन्क्वारी वगैरह करेंगे, इसके बावजूद जब कांग्रेस के मित्रों ने तय किया कि वे वाकआउट करेंगे इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि असल में वे चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को डिसमिस कर दीजिए। क्या गवर्नमैंट को इस बारे में कोई चिन्ता है? हरियाणा सरकार को डिसमिस कर दें तो यह लोग हाउस में वापिस आ जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप प्रश्न काल स्थगित करें और उस प्रस्ताव पर चर्चा करें जो मैंने प्रस्तुत किया है। **(व्यवधान)** आप प्रश्न काल को स्थगित कर इस प्रस्ताव पर विचार करें। अब देखते हैं कि सरकार की क्या स्थिति है। यह अत्यन्त गैरजिम्मेदाराना व्यवहार है। यह एक संकट है। इस संकट से निकलने का क्या उपाय है ? **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : महोदय, आप इसे हल्के तौर पर नहीं ले सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं। हम प्रश्न काल की कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : अध्यक्ष जी, आप हमें क्या रूल बता रहे हैं, सरकारी पार्टी को रूल बताना चाहिए। यहां कोरम को रखना उनकी जिम्मेदारी है। आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए उन्हें वार्निंग दीजिए और प्रताड़ना दीजिए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई बहस नहीं होगी।

[अनुवाद]

मुझे, अपने सहयोग से, प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने दें।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : महोदय, सदन इसको महत्वहीन नहीं समझ सकता। **(व्यवधान)** मुख्य समर्थक दल ने उस मुद्दे पर जिस पर आश्वासन दिया गया था सभा का बहिष्कार किया है। मैं जानता हूं कि अभी आपके सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। यह प्रश्नकाल है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुमत या अल्पमत का निर्णय अभी नहीं हो रहा। किन्तु, इससे यह भी संकेतित होता है कि अगर कांग्रेस (आई) अपना समर्थन नहीं देती तो सरकार का बहुमत नहीं रह जाता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है।

श्री चित्त बसु : इसे दर्शा कर स्पष्ट किया गया है। इस बात का क्या प्रमाण है कि इस सरकार को इस सभा में बहुमत प्राप्त है ? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, कृपया प्रश्न काल यहीं समाप्त कर के मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करें। यह सामान्य स्थिति नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। मैंने प्रश्नकाल को समाप्त करने का नोटिस दिया है। कृपया प्रश्नकाल को स्थगित करने के मेरे नोटिस पर विचार करें और फिर मैं सरकार की निंदा करने के अपने प्रस्ताव पर जोर डालूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल का स्थगन तत्काल ही नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

डा० बिप्लव दासगुप्त : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने दो प्रस्ताव रखे गए हैं; एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और एक अन्य प्रश्न काल के स्थगन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ गये हैं। राजीव गांधी जी के खिलाफ यह सर्वेलेंस कराया है या नहीं, उसके बारे में वह पोजिशन क्लीयर करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, प्रश्न काल के स्थगन के लिए मेरे प्रस्ताव पर कृपया अपना निर्णय दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सवाल जवाब के समय रूलिंग क्या ?

[अनुवाद]

मेरा निर्णय यह है हम प्रश्नकाल की कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

डा० बिप्लव दासगुप्त : महोदय, यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जब सरकार बहुमत में नहीं है; हम ऐसी स्थिति में हैं, जहां देश में कोई सरकार नहीं है; हम ऐसी स्थिति में हैं, जब इस सरकार को मुख्य समर्थक दल का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह एक असाधारण स्थिति है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल चलने दीजिए।

(व्यवधान)

डा० बिप्लव दासगुप्त : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)** हम स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सरकार की निन्दा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु आप प्रश्न काल समाप्त करने सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव पर सबसे पहले विचार कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार के प्रमुख समर्थकों ने सभा का बहिष्कार कर दिया है। तब केवल उसके कुछ ही सदस्य यहां पर क्यों बैठे हुए हैं ? उन्हें भी सभा से बाहर चले जाना चाहिए। क्या उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है ? क्या कांग्रेस (आई) ने अपना समर्थन वापस ले लिया है ?

अतएव हम यही चाहते हैं कि यह सरकार तुरन्त अपना इस्तीफा दे दे। इस सरकार के लिए अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। अतः सत्ता में बने रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

हमारी मांग यह है कि इस सरकार को सभापटल पर टेलीफोन टैपिंग से सम्बन्धित केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सरकार गणपूर्ति भी निश्चित नहीं कर सकती। हमारी मांग है कि सी०बी०आई० रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाए। अन्यथा हमें विवश होकर सभा का बहिष्कार करना होगा। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : आपने अपना निर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल चलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी मांग है कि सी०बी०आई० रिपोर्ट सभापटल पर प्रस्तुत की जाए। उससे श्री राजीव गांधी के खिलाफ एक और विशेषाधिकार सम्बन्धी मुद्दा खड़ा हो गया है। अतएव, जब तक सभापटल पर सी०बी०आई० की रिपोर्ट नहीं रखी जाती, तब तक समस्या का समाधान करना कठिन हो जाएगा। हमने पहले ही सी०बी०आई० रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दे दी है। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने पहले ही आपको एक अधिप्रमाणित प्रतिलिपि दे दी है। इस दौरान सभापटल पर उन्हें सी०बी०आई० की रिपोर्ट भी रखने दीजिए। उससे कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि वे सभापटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं, उस स्थिति में हमें विरोधस्वरूप सभा का बहिष्कार करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि इस सभा में सरकार पर क्या गुजरेगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक निगरानी के मुद्दे का सवाल है, यह सरकार उपहास का पात्र बन गई है। इससे पूरी सरकार के अस्तित्व का उपहास हो रहा है। मुद्दा निगरानी रखे जाने तथा फोन टैप किए जाने से सम्बन्धित है। परसों से विपक्ष यह मांग कर रहा है कि फोन टैपिंग से सम्बन्धित सी०बी०आई० की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए। कल निगरानी रखे जाने सम्बन्धी मामला उत्पन्न हुआ है। मेरे विचार से यह सभा उचित रूप से कार्य नहीं कर सकती। यह सरकार तब तक उचित रूप से कार्य नहीं कर सकती, जब तक कि सबसे पहले इस मामले पर विचार नहीं किया जाता तथा सरकार सी०बी०आई० की रिपोर्ट सभापटल पर रखने का विचार कर रही है। जब तक यह सरकार इस सभा को आश्वासन नहीं देगी, मैं समझता हूं कि विपक्ष का इस चर्चा में भाग लेने का कोई लाभ नहीं है।

[हिन्दी]

आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं और यह जो सारा सर्विलेंस का इश्यू है, उसके फोकस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, अगर वह स्पष्टीकरण दें तो बहुत अच्छा होगा ··· **(व्यवधान)**

डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब दें। ···**(व्यवधान)** ···या तो सरकार स्पष्टीकरण दे, अन्यथा हम वाक आउट करते हैं। ···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस सरकार को कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। इस सरकार की सभा के सभी वर्गों द्वारा निन्दा की जाती है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : आप प्रश्न काल समाप्त कर दें।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको स्पष्ट करना चाहिए। उप-प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। **(व्यवधान)**

हम इसके विरोध में सभा का बहिष्कार कर रहे हैं। सी०बी०आई० की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए।

डा० विप्लव दासगुप्त : सभा में गणपूर्ति नहीं है। हम गणपूर्ति चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कोई सरकार नहीं है। **(व्यवधान)**

डा० विप्लव दासगुप्त : सत्ता में बने रहने का इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार के एकमात्र समर्थक दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के मुद्दे को उठाने की एक उचित प्रक्रिया है। आप सभा से बहिष्कार कर रहे हैं अथवा क्या आप गणपूर्ति के मुद्दे को उठा रहे हैं ?

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के०सी० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है, बिजनैस कैसे होगा। पहले कोरम तो कराइए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का बहिष्कार कर रहे हैं अथवा क्या आप गणपूर्ति के प्रश्न को उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुन्डू जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तभी मैं आपको सुनूंगा। कुन्डू जी, आप अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं। आप अपने स्थान पर बैठें। तभी मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं एक अत्यधिक विवादास्पद प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल यही कह सकता हूं कि आप अपने स्थान पर जाएं तथा एक व्यवस्थित रूप में अपना व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के०सी० त्यागी : हाउस में कोरम नहीं है। आप पहले कोरम कराइए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए०के० राय : महोदय, क्या मैं यह बता सकता हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है ? मैं औपचारिक रूप से गणपूर्ति सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

अब सभा गणपूर्ति न होने के कारण 11.45 म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

11.26 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 11.45 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

11.55 म०पू०

लोक सभा 11.55 म०पू० पर पुनः समवेत हुई।

महासचिव द्वारा घोषणा

महासचिव : माननीय सदस्यगण, चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है। अतएव माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया है कि अब सभा 2.30 म०प० पर समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

*122. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्ष 1991-92 में रेल लाइनों का विद्युतीकरण आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोनीपत और पानीपत में रेल ऊपरी-पुल

[हिन्दी]

*123. **श्री कपिल देव शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अम्बाला रेल लाइन पर सोनीपत और पानीपत नगरों में रेल ऊपरी-पुलों का निर्माण करने के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग कितना खर्च होगा;

(ग) क्या सरकार को इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण आदि के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सोनीपत तथा पानीपत में ऊपरी सड़क पुलों पर खर्च की जाने वाली राशि इस प्रकार है :—

ऊपरी सड़क पुल का स्थान	रेलवे द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च	राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च (आंकड़े लाख रुपयों में)
सोनीपत	122.23	119.46
पानीपत (समपार संख्या 51ए के बदले)	148.11	134.98
पानीपत (समपार संख्या 53बी के बदले)	101.10	191.01

(ग) राज्य सरकार ने अभी तक सोनीपत तथा पानीपत (समपार सं० 53 बी के बदले) में ऊपरी सड़क पुलों के लिए पहुंच मार्गों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। पानीपत में (समपार सं० 51ए के बदले) अन्य ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु सड़क यातायात के लिए अस्थाई परिवर्तित मार्ग अभी चालू किया जाना है।

(घ) राज्य सरकार ने यह वचन दिया है कि सोनीपत तथा पानीपत में ऊपरी सड़क पुलों के संबंध में भूमि अधिग्रहण करने से सम्बन्धित पंचाट की शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी।

तमिलनाडु में रेल उपरि-पुल

[अनुवाद]

*124. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर कितने रेल उपरि-पुल निर्माणाधीन हैं; और

(ख) इस राज्य में निकट भविष्य में कितने उपरि-पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय 10 ऊपरी/निचले सड़क पुलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) 6 पुलों का निर्माण स्वीकृत हो चुका है जिस पर शीघ्र कार्य आरम्भ करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य पुलों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राशन प्रणाली लागू करना

*125. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर राशन प्रणाली लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

एयर इन्डिया के बोइंग 747 विमानों को क्षति

*126. **श्री आर० गुंडू राव** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया के दो 747 बोइंग विमान हाल ही में हंगरों में क्षतिग्रस्त हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और प्रत्येक विमान को कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के क्या उपाय किये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हर मोहन धवन) : (क) जी, हां। एयर इन्डिया का विमान वी०टी०-ई०पी० डब्ल्यू० 2-2-1991 और 5-2-1991 को मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था जबकि उसके विमान वी० टी०-ई० पी० ई० को 5-2-1991 को मामूली नुकसान हुआ था।

(ख) और (ग). यह संबंधित स्टाफ द्वारा गलत निर्णय लेने/उनमें संचार की कमी के कारण हुआ। एयर इन्डिया ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से पर्याप्त कदम उठाए हैं। उनको हुई हानि निम्न प्रकार है—

1. वी० टी०-ई० पी० डब्ल्यू.

पहली घटना	: 3,316 रुपए
दूसरी घटना	: 18,897 रुपए

2. वी० टी०-ई० पी० ई : 75,493 रुपए

कोयला कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी

*127. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

श्री सूर्य नारायण सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों में कार्यरत 50,000 कर्मचारियों की छटनी करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग का विश्व बैंक से लिए जाने वाले किसी ऋण से कोई संबंध है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग). निम्नलिखित चालू कोयला परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वयनाधीन हैं—

	क्षमता (मि० ट० प्रतिवर्ष)	ऋण राशि (अमेरिकी मिलियन डालर)
(1) ब्लाक-II	2.5	57.7
(2) दुधीचुआ	5.0	109.00
(3) गेवरा	10.0	65.2
(4) सोनीपुर बाजारी	3.0	114.8

जनवरी-फरवरी, 1991 के दौरान चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय विश्व बैंक दल भारत आया था। इस दल ने अपनी बठकों के दौरान (कोल इन्डिया लि० तथा कोयला विभाग में) कोयला परियोजनाओं से सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से एक था—कोयला क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन को सुधारने के तरीके/विचार-विमर्श के दौरान भंडारों की समाप्ति के कारण फालतू कामगारों के पुन: नियोजन के तौर-तरीकों पर तथा अनुत्पादक श्रमशक्ति में कमी किए जाने के उद्देश्य से भी विचार-विमर्श किया गया ताकि प्रतिपाली प्रति व्यक्ति उत्पादन में सुधार लाया जा सके।

सामान्य रूप से इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उक्त विचार-विमर्श में न तो फालतू श्रमिकों की कोई संख्या का उल्लेख किया गया और न ही विश्व बैंक से मांगे गए किसी ऋण में इसे शर्त के रूप में रखा गया। विश्व बैंक ने इस मामले में कोयला विभाग को कुछ नहीं लिखा है।

वायुदूत सेवा का गैर-सरकारीकरण

[हिन्दी]

*128. **श्री हर्षवर्धन :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायुदूत विमान सेवा का गैर-सरकारीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुदूत जिस वित्तीय संकट का सामना कर रही है उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हर मोहन धवन) : (क) से (ग). वायुदूत लिमिटेड के भावी ढांचे के बारे में सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड में सुरक्षा के उपाय

[अनुवाद]

*129. **श्री राम नाईक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री दिनांक 10 नवम्बर, 1990 के "इन्डियन एक्सप्रैस" (बम्बई संस्करण) में "गैलेन्ट्री अवार्ड्स फॉर सी० आई० एस० एफ० मैन मूटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को दी जाने वाली राहत राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे कि वह भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटड के कर्मचारियों को दी जाने वाली राहत राशि के बराबर हो जाये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है तथा उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तैयार किए गए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड द्वारा सुरक्षा के उपाय किए गए थे तथा चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). आईपीसीएल ने सीआईएसएफ के कार्मिकों सहित उन सब के निकट संबंधियों को, जिनकी नागोथाणे दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी दो। लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की पहले ही घोषणा कर दी है।

(ग) और (घ). दुर्घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई थी। एक सीआईएसएफ कर्मचारी का बम्बई में अभी भी उपचार किया जा रहा है। चिकित्सा खर्च आईपीसीएल द्वारा वहन किया जा रहा है। सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा रही है।

कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

*130. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की स्थिति ठीक है। तथापि, हाई स्पीड डीजल की कुछ कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग). इस समय समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच० एस० डी० की आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है जिस स्तर पर पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई थी। हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति पर इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कुछ कमी हुई है जिसमें कर्नाटक शामिल है। समूचे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की यथासंभव पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर सख्त नजर रखी जा रही है।

कर्नाटक में होसपेट में सुपर ताप बिजलीघर की स्थापना

*131. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में होसपेट में एक सुपर ताप बिजलीघर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी केन्द्रीय दल ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उसके कब चालू किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (घ). मैसर्ज कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि० (के० पी० सी० एल०) द्वारा होसपेट के समीप दो स्थलों का पता लगाया गया है। वृहत ताप विद्युत केन्द्रों हेतु स्थलों का चयन करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा गठित की गई स्थल चयन समिति के एक दल ने इन स्थलों का दौरा किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1990 में प्रस्तुत कर दी थी। ऐसा पाया गया है कि व्यासनकेरा और तोरनगाल्लू दो स्थलों के लिए अनेक निवेश सुनिश्चित किए जाने अपेक्षित हैं तथा मैसर्स के० पी० सी० एल० द्वारा और अन्वेषण संबंधी कार्य किए जाने अपेक्षित हैं। कर्नाटक के होसपेट में सुपर ताप विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट विचाराधीन नहीं है।

उत्तर-पूर्व में कच्चे तेल की सम्भावना

*132. **श्री मनोरंजन सुर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1991 के "स्टेट्समैन, (दिल्ली संस्करण) में "बिग क्रूड ऑयल पोटेन्शियल इन नार्थ-ईस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस मामले पर भारत सरकार पहले ही ध्यान दे रही है और इसने अब बहु-आयामी, बहु-संगठनात्मक कार्य दल का गठन किया है ताकि उन सभी संबंधित पहलुओं की जांच की जा सके, जिसमें भण्डारों का मूल्यांकन, तेल की निकासी के लिए सही प्रकार की चट्टानों/कोयले का निर्दिष्टकरण, जो इसके लिए सबसे अधिक लागत-प्रभावी संसाधन भी है, और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जिन क्षेत्रों में कोयला/तेल शैल मिलते हैं उन पर कोयले/शैल के खनन से पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना शामिल है।

खान-पान सेवाओं का स्तर

[हिन्दी]

*133. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली से पुरी और हावड़ा जाने वाली रेलगाड़ियों में खान-पान सेवाओं का स्तर घटिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रति व्यक्ति भोजन का मूल्य बढ़ाये जाने के बावजूद भोजन की गुणवत्ता नहीं सुधरी है; और

(घ) यदि हां, तो अनियमितताओं को रोकने और साथ ही खान-पान सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिये दिये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). मूल्य की ओर ध्यान दिए बिना ही गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। खान-पान सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं—

1. आधार रसोईघरों/अल्पाहार गृहों का आधुनिकीकरण।

2. कैसरोल सेवा शुरू करना।

3. कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना।

4. लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल बंद करना तथा तरल पेट्रोलियम गैस का उपयोग करना।

5. गहन निरीक्षण करना।

6. पर्यवेक्षण का स्तर सुदृढ़ करना।

7. व्यंजन सूची में संशोधन करना।

8. रसोईघर के लिए आधुनिक उपस्करों और उपकरणों की व्यवस्था।

9. चुनी हुई गाड़ियों में चाय पत्ती की थैली, अलग से दूध और चीनी सहित थर्मस फ्लास्कों में चाय सप्लाई करना।

10. गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मिलावट रोकने के उद्देश्य से, खाद्य सामग्री के अचानक नमूने लेना तथा उनका रासायनिक विश्लेषण करना।

इसके अलावा, रेलवे बोर्ड और रेलों के सतर्कता विभागों के विशेष दस्तों द्वारा अचानक जांच की जाती है और अनियमितताओं के साबित मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

एयर-इंडिया का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

*134. **श्री बसन्त साठे :**

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाड़ी संकट को देखते हुए एयर इंडिया की छवि सुधारने और उसकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हर मोहन धवन) : (क) से (घ). अनंतिम अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर, 1990 में) एयर इंडिया का शुद्ध लाभ 47.48 करोड़ रुपये रहा है जबकि 1989-90 की इसी अवधि में यह 38.40 करोड़ रुपये था और 1988-89 की इसी अवधि में यह 14.06 करोड़ रुपये था। खाड़ी संकट का एयर इंडिया सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय वाहकों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। एयर इंडिया ने अपने मार्ग ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और व्यय में किफायत करने के लिए कदम उठाये हैं।

गाजीपुर-जौनपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

*135. **श्री राम सागर** (सैदपुर) : क्या **रेल** मंत्री 7 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर-जौनपुर मीटर-गेज (बरास्ता औरिहार) सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : गाजीपुर-जौनपुर मीटर लाइन में से, अभी केवल औड़िहार-गाजीपुर-छपरा (171 कि०मी०) लाइन के बदलाव के लिए ही स्वीकृति दी गई है। यह काम प्राथमिकता के आधार पर चल रहा है और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

टिहरी बांध परियोजना को पूरा करना

[अनुवाद]

*136. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) इससे कितनी बिजली पैदा होने की आशा है; और

(ग) क्या जब परियोजना का कार्य चल रहा होगा तब बिजली चरणों में वितरण के लिए उपलब्ध होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) टिहरी बांध परियोजना (2400 मेगा०) पर 3465 करोड़ रुपए की लागत (मार्च, 1990 के मूल्य स्तर पर) आने का अनुमान है और इसे मार्च, 1997 तक चालू किए जाने की संभावना है।

(ख) एक वर्ष में 4238 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

रेलवे परियोजनाएं

*137. **श्री ए०के०ए० अब्दुल समद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कौन-कौन से बड़े रेलवे कार्य शुरू किये गये;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कौन-कौन से बड़े रेलवे कार्य पूरे किये गये;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कौन-कौन से बड़े रेलवे कार्य चल रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन बड़े रेलवे कार्यों को आरंभ करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ग). नई रेलवे परियोजनाओं तथा चालू परियोजनाओं का रेलवे-वार तथा योजना शीर्ष-वार ब्यौरा रेलों के 1990-91 के निर्माण, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम नामक पुस्तिका में दिया गया है जो 1990-91 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्यों को दिए गए बजट प्रलेखों का भाग है।

(ख) निम्नलिखित नई लाइन खंडों/परियोजनाओं तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं के 1990-91 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है :—

नई लाइनें

1. चित्तौड़गढ़-नीमच
2. सिंगापुरम रोड-केवटीगुड।

3. कोलारस-शिवपुरी

4. ग्वालियर-पनिहार

5. जमीरा-मैराबी

6. तालचेर-अंगुल

7. सम्बलपुर-मानेश्वर

8. दामनजोड़ी-लक्ष्मीपुर

आमान परिवर्तन

1. मऊ-वाराणसी

2. गुंटूर-माचेर्ला

(घ) जिन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाना है, वे विचाराधीन हैं तथा जिन्हें अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया जाएगा उन्हें 1991-92 के नियमित बजट में शामिल कर लिया जाएगा तथा इसके प्रस्तुत किये जाने के समय माननीय सदस्य को दे दिया जाएगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत शुल्क में वृद्धि पर पुनर्विचार

*138. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध दिल्ली के लोगों में व्यापक असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत शुल्क की दरों में प्रस्तावित वृद्धि पर पुनर्विचार करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ङ). दिल्ली में विद्युत टैरिफ में वृद्धि किए जाने संबंधी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के निर्णय के विरुद्ध जनता से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में बिजली के टैरिफ में संशोधन किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है क्योंकि पिछली बार, अप्रैल, 1985 में डेसू के टैरिफ में संशोधन किए जाने के बाद से इसके द्वारा विद्युत उत्पादन/विद्युत की खरीद संबंधी लागत में वृद्धि और विभिन्न निवेशों की लागत में कुल मिलाकर वृद्धि के परिणामस्वरूप डेसू को काफी अधिक मात्रा में प्रचालनात्मक हानियां हुई हैं। संशोधित टैरिफ से डेसू द्वारा न केवल अपनी प्रचालनात्मक हानियों की पूर्ति की जा सकेगी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जा सकेगा। डेसू द्वारा अपने टैरिफ में वृद्धि संबंधी मामले पर पुनर्विचार किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाना

*139. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केरल में कार्यान्वित की जा रही इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) केरल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और उपयोग संबंधित राज्य संगठनों के साथ मिलकर किया जा रहा है।

(ख) इन योजनाओं में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर आधारित प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना, ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में बायोमास का उपयोग, लघु/सूक्ष्म जल विद्युत योजनाओं का विकास करना शामिल है।

(ग) ये कार्यक्रम सतत प्रकृति के हैं और इन्हें योजनादर योजना तथा वर्ष-दर वर्ष के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

राजस्थान को विमान सेवाओं से जोड़ना

[हिन्दी]

*140. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नागर विमानन सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त योजना में राजस्थान के बड़े शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने तथा वर्तमान वायुपत्तन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) नागर विमानन क्षेत्र के लिये आठवीं योजना के परिव्यय को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग). राजस्थान में किसी नए शहर को हवाई सेना से जोड़ने की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में सुविधाओं में सुधार करने की योजनाएं हैं।

राजस्थान में "ओलेफिन" काम्पलैक्स की स्थापना

[अनुवाद]

1358. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से राजस्थान में गैस पर आधारित कैमिकल/अमोनिया बेस काम्पलैक्स के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या प्लास्टिक की वस्तुओं की मांग आशा से कहीं अधिक रही है। विभिन्न उत्पादों की मांग और आपूर्ति में अंतर खत्म करने तथा अन्य कारणों की वजह से राजस्थान में "ओलेफिन" काम्पलैक्स की पर्याप्त गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्पादों की सम्पूर्ण मांग और पूर्ति के अनुमानों, फीडस्टाक की उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कोई ओलीफिन काम्पलैक्स विचाराधीन नहीं है।

जैसलमेर में गैस का उपयोग

[हिन्दी]

1359. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर जिले में पाई गई गैस से 92 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है;

(ख) उसका पूर्ण दोहन किस समय तक उपलब्ध हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वहां पर गैस की उपलब्धता के आधार पर एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जैसलमेर जिले में खोजी गई गैस निम्न तापीय/कैलोरिफिक मूल्य वाली है चूंकि इसमें अक्रिय गैस अधिक मात्रा में है। इसलिए इस गैस से लिए जाने वाले शुल्क सरकार के जांचाधीन हैं। अतएव जैसलमेर जिले में प्राप्त गैस की बिक्री से संभावित आय के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग). 3 मेगावाट के रामगढ़ विद्युत स्टेशन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 50,000 घन मीटर प्रतिदिन गैस का आबंटन 1988 में किया गया था लेकिन विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं हुआ है और इस प्रकार इस बचनबद्धता का उपयोग नहीं किया जा सका। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग ने राजस्थान में प्राप्त अतिरिक्त गैस के उनके इष्टित उपयोग को बताने के संबंध में राज्य सरकार को भी लिखा है।

बिजली की मांग और उत्पादन

[अनुवाद]

1360. **श्री परसराम मारद्वाज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में बिजली की कुल कितनी मांग थी और इसका वास्तविक उत्पादन कितना था और;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में उत्पादन में कितनी मात्रा की और कितने प्रतिशत की कमी आयी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवनराव डाकणे) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं अप्रैल-जनवरी, 1991 के दौरान देश में ऊर्जा की कुल आवश्यकता एवं वास्तविक विद्युत उत्पादन (सकल) निम्नानुसार है—

वर्ष	आवश्यकता (निवल मि०यू०)	वास्तविक उत्पादन (मि०यू०)
1987-88	210993	201894
1988-89	223194	221125
1989-90	247762	245141
1990-91 (अप्रैल-जन. 91)	220876	218072

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं अप्रैल, 1990-जनवरी, 1991 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विद्युत उत्पादन एवं प्रतिशत कमी/अधिशेष संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुल विद्युत उत्पादन (गे०वा०आ०)

वर्ष	क्षेत्र	लक्ष्य	वास्तविक	(—) कमी/ (+) अधिशेष	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1987-88	केन्द्रीय क्षेत्र	53426	54241	(+) 815	101.5
	राज्य क्षेत्र	140779	136812	(—) 3967	97.2
	निजी क्षेत्र	10795	10841	(+) 46	100.4
	जोड़ :	205000	201894	(—) 3106	98.5
1988-89	केन्द्रीय क्षेत्र	65682	67581	(+) 1899	102.9
	निजी क्षेत्र	11296	10645	(—) 651	94.2
	राज्य क्षेत्र	149522	142899	(—) 6623	95.6
	जोड़ :	226500	221155	(—) 5375	97.6
1989-90	केन्द्रीय क्षेत्र	78021	77803	(—) 218	99.7

1	2	3	4	5	6
	राज्य क्षेत्र	162529	155489	(—) 7040	95.6
	निजी क्षेत्र	10750	11849	(+) 1099	110.2
	जोड़ :	251300	245141	(—) 6159	97.5
1990-91	केन्द्रीय क्षेत्र	75191	72289	(—) 2902	96.1
(अप्रैल, 90-	राज्य क्षेत्र	140527	134843	(—) 5684	95.9
जन० 91)	निजी क्षेत्र	9267	10940	(+) 1673	118.0
	जोड़ :	224985	218072	(—) 6913	96.9

राज्य बिजली बोर्डों की योजना सहायता में कटौती

1361. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को देय बकाया राशि को, राज्यों को दी जा रही योजना-सहायता राशि में से काट रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अब तक काटी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा देय बकाया धनराशि की वसूली के लिए भी कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) 31.5.1990 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया निर्विवाद राशि की 25% राशि को राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता से वसूल किए जाने को दर्शाने वाला सुसंगत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

(करोड़ रु० में)

राज्य	रातांविनि	राजविनि	नीपको	सीआईएल	जोड़
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	1.24	—	—	0.94	2.18
2. असम	—	1.55	11.23	—	12.78
3. बिहार	25.44	6.53	—	22.01	53.98

1	2	3	4	5	6
4. गोवा	0.10	—	—	—	0.10
5. गुजरात	10.10	—	—	21.97	32.07
6. हरियाणा	17.34	6.15	—	20.65	44.14
7. हिमाचल प्रदेश	1.60	—	—	—	1.60
8. जम्मू व कश्मीर	2.00	1.39	—	—	3.39
9. कर्नाटक	7.25	—	—	—	7.25
10. केरल	1.83	—	—	—	1.83
11. मध्य प्रदेश	35.58	—	—	15.37	50.95
12. महाराष्ट्र	11.07	—	—	23.70	34.77
13. मणिपुर	—	1.48	0.02	—	1.50
14. मेघालय	—	—	0.09	—	0.09
15. मिजोरम	—	—	0.08	—	0.08
16. उड़ीसा	4.15	1.53	—	3.57	9.25
17. पंजाब	0.48	3.08	—	7.48	11.04
18. राजस्थान	33.00	—	—	2.67	35.67
19. सिक्किम	0.20	0.08	—	—	0.28
20. तमिलनाडु	9.31	—	—	13.39	22.70
21. त्रिपुरा	—	—	0.34	—	0.34
22. उत्तर प्रदेश	84.25	—	—	133.67	217.92
23. प० बंगाल	10.21	1.43	—	7.94	19.58
कुल जोड़	255.15	23.22	11.76	273.36	563.49

दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

1362. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ग्रीष्म ऋतु आने के पूर्व दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर और अधिक सुविधाएं यथा बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, पंखे प्रदान करने के लिए एक नूतन सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं, दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं, बैठने की व्यवस्था और पंखे पहले ही से हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय अस्पताल, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में अस्पताल परिचारक

1363. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अस्पताल, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में अस्पताल परिचारकों के पद चयन के लिए हाल ही में आवेदन मांगे गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और कितने आवेदनकर्त्ताओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और कितनों को नियुक्त किया गया; और

(ग) केन्द्रीय अस्पताल, उत्तर रेलवे के श्रेणी (ग) और (घ) के रेल कर्मचारियों के बच्चों तथा नैमिक श्रमिक/बाहर से आये उम्मीदवारों में से भी अस्पताल परिचारकों को नियुक्त किया गया ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 4817 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 955 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और 25 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया तथा उन्हें सेन्ट्रल अस्पताल, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में अस्पताल परिचरों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) सेन्ट्रल अस्पताल, उत्तर रेलवे के ग्रुप ग और घ के रेल कर्मचारियों के बच्चों में से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 5 और नैमित्तिक श्रमिकों/बाहरी व्यक्तियों में से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 9 है।

कोल इंडिया लि० को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय बकाया राशि

1364. **डा० ए० के० पटेल** :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार से कोल इन्डिया लि० को देय बकाया-राशि को माफ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक के नाम कितनी धनराशि बकाया पड़ी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (घ). कोयला विभाग में कोयले की बिक्री के संबंध में कोल इंडिया लि० की राज्यों के विद्युत बोर्डों के पास देय बकाया राशि को समाप्त किए जाने से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

गैस नियंत्रण आदेश, 1988 के अंतर्गत मारे गए छापे

1365. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस नियंत्रण आदेश, 1988 के अंतर्गत खाना पकाने की गैस सप्लाई करने वाली तेल कम्पनियों द्वारा छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले रजिस्टर किए गए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों और उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या निरोधात्मक उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) एल० पी० जी० सिलिंडरों और उपस्करों के गलत उपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित निरोधक उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की पहचान।

(2) क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों और उपभोक्ताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण करना।

(3) गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को विभिन्न आकार के सिलिंडरों की आपूर्ति करना।

(4) डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग रजिस्टर रखना।

(5) कदाचार में लिप्त डिस्ट्रीब्यूटरों से क्रेताओं को अन्य वितरकों के यहां पुनः आबंटित करना।

(6) डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू और गैर-घरेलू रिफिलों के लिए अलग इन्डेंट रखना।

(7) विभिन्न स्तरों पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा जांच।

(8) सरकार द्वारा एल० पी० जी० (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 1986 को जारी किया जाना जो जहां अधिकृत प्रयोग किया जाता है वहां प्रवेश, जांच और जब्ति के लिए स्थापित अधिकारियों को शक्ति प्रदान करता है; और

(9) घरेलू गैस उपभोक्ता कार्डों को चरणों में शुरू करना।

(10) विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों और डीलरशिप समझौते के अनुरूप दोषी एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना।

औषधियों का वर्गीकरण और मूल्य निर्धारित करना

1366. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में विशेषज्ञों/विनिर्माताओं से कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों के मूल्य निर्धारण अथवा उनके मूल्यों में संशोधन करने के बारे में आपत्तियां उठाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औषधियों की मानव गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ . विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत औषधों को श्रेणीबद्ध करने सहित डी० पी० सी० ओ०, 1987 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा गठित स्थाई समिति को 3 विशेषज्ञ ग्रुपों द्वारा सहायता दी जा रही है । डी० पी० सी० ओ०, 1987 और औषध मूल्य समकरण खाते (डी० पी० ई० ए०) के अंतर्गत वसूलियों सहित भेषज उद्योगों से संबंधित विभिन्न मसलों पर औषध निर्माता कंपनियों के संघों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे । इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लेते समय इन संघों द्वारा बताई गयी सभी जायज समस्याओं पर विचार किया जाएगा ।

(ङ) अपेक्षित जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्डियन एयरलाइंस कर्मचारियों को वर्दी की आपूर्ति

1367. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री युसुफ बेग :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राय: यह देखा गया है कि इंडियन एयरलाइंस के यातायात कर्मचारी वर्दी की अनियमित आपूर्ति की वजह से सही वर्दी में नहीं होते हैं;

(ख) क्या इससे इंडियन एयरलाइंस के कार्यरत कर्मचारियों विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस वर्दियों पर काफी धनराशि खर्च करता रहा है परन्तु वर्दी प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इंडियन एयरलाइंस द्वारा विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान सर्दी और गर्मी की वर्दियों की कितनी खरीद की गई तथा कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आपूर्ति की तारीखों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, समय-समय पर कर्मचारियों/यूनियनों के विभिन्न हिस्सों से वर्दी की अतिरिक्त मदों और वर्दी की मात्रा/गुणवत्ता में सुधार की मांगों पर अलग-अलग अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) जी, नहीं । मात्रा और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वर्दी के खर्च पर उचित विचार किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नयी कोच फैक्टरियां

1368. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितनी रेल कोच फैक्टरियां स्थापित की गई हैं और आठवीं योजनावधि के दौरान इनमें से कितनी फैक्टरियों के विस्तार का विचार है;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त योजनावधि के दौरान कुछ नई रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित रेल कोच फैक्टरियों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे उत्पादन इकाइयों के लिए प्रत्येक वर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उन लक्ष्यों को किन सीमा तक प्राप्त किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में रेलों द्वारा केवल दो रेल सवारी डिब्बा कारखानों की स्थापना की गई है तथा उनमें से एक का इस अवधि के दौरान विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ). सवारी डिब्बों के लिए रेलवे की भावी आवश्यकता तथा मौजूदा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त रेल सवारी डिब्बा कारखाना खोलने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है इसलिए इसके स्थान के संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

(ङ) वर्ष	सवारी डिब्बा कारखाना		रेल सवारी डिब्बा कारखाना	
	लक्ष्य	निष्पादन	लक्ष्य	निष्पादन
1987-88	900	825	01	01
1988-89	900	900	120	120
1989-90	925	925	205	175

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सम्पत्ति की बिक्री

1369. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सम्पत्ति की बिक्री के कतिपय मामले प्रकाश में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इनमें यदि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तो उनकी संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में रसोई गैस की सुविधा

1370. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के उन शहरों और कस्बों का ब्यौरा क्या है, जहां लोगों को रसोई गैस की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा शेष शहरों और कस्बों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उनमें यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार एल० पी० जी० चरणबद्ध रूप में उन शहरों/नगरों में दी जा रही है जहां की जनसंख्या 20,000 और उससे अधिक (1981 की जनगणना के आधार पर) हो, बशर्ते कि वहां का बाजार आर्थिक क्षमता की दृष्टि से व्यवहार्य हो, और समग्र रूप से उत्पाद उपलब्ध हो। किसी भी एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने से पूर्व अनेक कार्यवाहियां आवश्यक होती है, अत: यह बताना कि शेष शहरों/नगरों में एल० पी० जी० की सुविधाएं कब तक दे दी जाएंगी संभव नहीं है।

विवरण

कर्नाटक राज्य के उन शहरों/नगरों के नाम जहां एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं

1	2	1	2
1.	अठानी	7.	बंगारपेट
2.	अलन्द	8.	बेलगाम
3.	अनेकल	9.	बेनतवल
4.	अर्सीकेरी	10.	बेलारी
5.	बगलकोट	11.	भटकल
6.	बंगलौर	12.	बेलहोंगल

1	2	1	2
13.	बासवा कल्याण	41.	होलेनारसीपुर
14.	भद्रावती	42.	होसकोटे
15.	बीदर	43.	होसपेट
16.	बीजापुर	44.	हुबली
17.	चन्नापतना	45.	हीरपुर
18.	चिकमंगलूर	46.	हाटी
19.	चमराजनगर	47.	हरपनाहाली
20.	कोडापुर	48.	हुनसुर
21.	चलाकेरी	49.	होनावर/कसरगोड
22.	चिकोडी	50.	हलियाल
23.	चिकबलारपुर	51.	हगारी, बोमानहाली
24.	चित्तापुर/वाडी टीपी/ वाडी एसीसी	52.	इलकाल
		53.	काटूर
25.	धारवाड़	54.	करकला
26.	दावंगीरी	55.	खानपुर
27.	डांडेली	56.	कोलार गोल्ड फील्डस
28.	डोनीमाली	57.	कोलेगल
29.	डोदाबालापुर	58.	कृष्णाराजानगर
30.	गंगावती	59.	कनकापुरा
31.	गौरीबिदनपुर	60.	कोपल
32.	घटाप्रभा	61.	करवार
33.	गडक	62.	कुमटा
34.	गुंदलूपेट	63.	कुरुकुन्टा
35.	गोकाक	64.	किट्टूर
36.	गोलेदगुड	65.	कुडाची/उगारखुर्द
37.	गुलबर्गा	66.	कुन्देरमुख
38.	हरीहर	67.	लक्ष्मेश्वर
39.	हसन	68.	मेरकरा
40.	हवेरी	69.	मलवाली

1	2	1	2
70.	मनग्या	91.	सूरतकल
71.	मनवी	92.	शिकारीपुर
72.	मंगलौर	93.	शाहबाद
73.	मनीपल	94.	सिनदनूर
74.	मुडहोल	95.	सम्बरा
75.	मोडबिदरी	96.	शाहपुर
76.	मैसूर	97.	शोरापुर
77.	ननजनगुड	98.	सौनूर
78.	नरगुंड	99.	सूरतकल/न्यू मंगलौर
79.	निपानी	100.	सिरुगुप्पा/टेकलकोटा
80.	पुत्तुर	101.	सिरसा
81.	रायचूर	102.	सिदलाघाटा
82.	रामदुर्ग	103.	तीर्थाकाली
83.	रामनगरम	104.	तुमकुर
84.	पबकवी बनहट्टी	105.	तिपतुर
85.	रानेबेनूर	106.	उदीपी
86.	सागर	107.	उल्लाल
87.	सन्दूर	108.	विजयपुरा
88.	सिमोगा	109.	यदगीर
89.	सिरसी	110.	ब्यादगी
90.	श्रीरंगापट्टनम		

कोचीन में हवाई अड्डा

1371. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन में एक नया हवाई अड्डा बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1372. **श्री वाई० रामकृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नयी रेल लाइनें बिछाने और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव भेजें हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

नान्देड़, महाराष्ट्र के लिए वायुदूत सेवा

1373. **डा० वेंकटेश काबड़े** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नान्देड नगर के लिए वायुदूत सेवा स्थगित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को पुन: कब शुरू कर दिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत का इस सेवा को पुन: शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

1374. **श्री युसुफ बेग** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की खामियों के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या यह पाया गया है कि बिजली उत्पादन क्षमता और बिजली के वास्तविक उत्पादन में भारी अन्तर है ;

(ग) क्या नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में प्रतीक्षारत है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति के लिए प्रतीक्षारत विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बिजली की मांग और बिजली की आपूर्ति के बीच का अंतर दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराव डाकणे) : (क) जी, नहीं।

(ख) अप्रैल, 90 से जनवरी, 91 की अवधि के लिए उ०प्र०रा०वि०बो० के विद्युत उत्पादन

में कमी, वास्तविक विद्युत उत्पादन, लक्ष्य का विवरण नीचे दिया गया है :—

(विद्युत उत्पादन मि०यू० में)

प्रकार	लक्ष्य	वास्तविक	कमी (—) अधिशेष (+)
ताप विद्युत	12740	11685	(—) 1055
जल विद्युत	4333	4427	(+) 94
जोड़	17073	16112	(—) 961

(ग) और (घ). राज्य क्षेत्र की स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किये गये विभिन्न उपायों में ये शामिल है : नई विद्युत क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्प निर्माणावधि की परियोजनाओं का क्रियान्वयन, संचरण एवं वितरण हानियों में कमी, मांग, प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना तथा अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण करना।

विवरण

उत्तर प्रदेश में राज्य क्षेत्र की स्कीमों की स्थिति

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	आई०डी०सी० को छोड़कर अनुमानित लागत (आई०डी०सी० सहित) (करोड़ रु०)	के०वि०प्रा० में प्राप्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बलघारा रोड़ (ता०वि०)	3×210=630	982.2 1015.4	12/89 (I) 5/90 (II)	उ०प्र०रा०वि०बो० ने 7/90 को के०वि०प्रा० को सूचित किया कि वे चरण-I के अन्तर्गत 3×250 मे०वा० क्षमता के साथ परियोजना रिपोर्ट को संशोधित कर रहे हैं। ईंधन लिंकेज, केन्द्र एवं राज्य से पर्यावरणीय स्वीकृति, नागर विमानन से स्वीकृति, केन्द्र से जल उपलब्धता, सम्बद्ध संचरण प्रणाली संबंधी स्वीकृतियां अभी सुनिश्चित की जानी हैं।
2.	जगदीशपुर जी०टी० संयुक्त साइकिल प्लांट (ता०वि०)	4×35 (जी०टी०) +2× 35 (एस०टी०) =210	235.0 261.5	5/89 (I) 8/90 (II)	फ्यूल लिंकेज सम्बद्ध सचरण प्रणाली अभी सुनिश्चित की जानी है। मूल्यांकनाधीन है।
3.	गोरीगंगा चरण I और II (ज०वि०)	3×20+3×40=180	479.0	10/90	पर्यावरण एवं मूल्यांकनाधीन वन संबंधी स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है।

1	2	3	4	5	6
4.	बसूली (ज०वि०)	5×0856=4.28	16.6	10/90	मूल्यांकनाधीन/पर्यावरण संबंधी पहलू, टिप्पणियां राज्यों को भेजी गयी है उनके उत्तर की प्रतीक्षा है पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है।
5.	तपोवन विष्णुघाद (ज०वि०)	3×120=360	242.0	7/86	जलविज्ञान संबंधी अध्ययनों में असंगतता के कारण एवं सिविल इलैक्ट्रिकल अभिकल्पीय पहलुओं में संशोधनों के लिए 10/88 को रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटायी गयी। स्कीम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी अस्वीकृत कर दी गयी है।
6.	कोटापाथर (ज०वि०)	2×9.5=19	19.0	1/82	संशोधित रिपोर्ट प्रतीक्षित (राज्य को वापस) पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है।
7.	पालामनेरी (ज०वि०) (संशोधित)	4×100=400	383.8	1/87	मई, 1988 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत (12/88 में राज्य को वापस)।
8.	लखवार व्यासी बहुउद्देशीय (ज०वि०)	3×100+2×60=420	276.0 (जोड़)	11/79	जल संसाधन मत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना पर विचार किया जा सकेगा। सिंचाई संबंधी पहलुओं के उत्तर अपर्याप्त पाये गये थे। और 4/89 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भी रिपोर्ट वापस कर दी गयी थी।
9.	कोटलीभेल डेम बहुउद्देशीय (ज०वि०)	4×250=1000	1186.0	9/83	विस्तृत जांच पड़ताल करने के बाद पुन: प्रस्तुत करने के लिए परियोजना 6/86 में राज्य को वापस।

1	2	3	4	5	6
10.	मिलामिनी (ज०वि०)	3×1=3	10.0	6/86	पिछले दो वर्षों से परियोजना प्राधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण स्कीम 6/88 को राज्य को लौटा दी गई है।
11.	पंचांद बहुउद्देशीय (ज०वि०)	6×15=90	559.0	7/83	स्कीम में मध्य प्रदेश/राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय पहलू निहित है और जलमग्नता, पुनर्वास एवं अन्य कई मुद्दों पर समझौता आवश्यक है।
12.	परिछा विस्तार (ता०वि०)	2×210=420	175.4 596.0 कोई कार्यवाही	6/79 (I) 4/89 (II) (संशोधित)	(I) 1989-90 से पहले कोयला लिंकेज की गैर-उपलब्धता एवं छठी योजना के दौरान निधियों की गैर-उपलब्धता के कारण स्कीम के०वि०प्रा० में नहीं की गयी थी। स्कीम 2/81 में राज्य को इस अनुरोध के साथ लौटा दी गयी कि इसे 1989-90 से परे लाभों के लिए प्रस्तुत किया जाये। (II) राज्य ने सूचित किया है कि स्कीम को अब 1994-95 के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है और यह कि संशोधित रिपोर्ट नियत अवधि में के० वि०प्रा० को प्रस्तुत की जायेगी। उ०प्र०रा०वि० बो० ने अप्रैल, 1989 में संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत कर दिये लेकिन तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए अपेक्षित विभिन्न निवेशों को शामिल करते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित है। उ०प्र०रा०वि०बो० ने दिनांक 27.9.89 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि विभिन्न स्वीकृतियां

1	2	3	4	5	6
					प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। उ०प्र०रा०बि०बो० से 6/90 में के०वि०प्रा० द्वारा 2×250 मे०वा० के लिए परियोजना रिपोर्ट संशोधित करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि तकनीकी आर्थिक लाभों के कारण 210 मे०वा० के स्थान पर भविष्य की परियोजनाओं के लिए यूनिटों का आकार 250 मे०वा० अपनाया जाना है। तथापि, संशोधित परियोजना प्रतीक्षित है।
13.	तुइनी प्लासू (ज०वि०)	3×16.67=50	06.0	5/89	जल विज्ञान एवं आयोजना संबंधी पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग/के०वि०प्रा० के साथ विचार-विमर्श करने के बाद पुन: प्रस्तुत किए जाने के लिए परियोजना 3/90 को वापस।
14.	कोसी जी०टी० (ता०वि०)	2×120=240	85.8	8/84	स्कीम पर्यावरण विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है क्योंकि यह स्थल आगरा-मथुरा क्षेत्र में डिमार्केटेड जोन के बहुत नजदीक है। राज्य को 4/86 में सूचित किया गया था।
15.	अनपारा "ग" जिला मिर्जापुर (ता०वि०)	3×500=1500 2×500=1000	565.1 1547.8	4/80 4/90	भारी सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के कारण कोयला लिंकेज 1989-90 तक सुनिश्चित नहीं किया गया था। 1989-90 से परे स्कीम को विचारार्थ पुनर्जीवित करने के लिए फरवरी, 1989 में उ०प्र० रा०बि०बो० को सूचित किया गया था। पहले

1	2	3	4	5	6
					प्रस्तावित 3×500 मेगा० यूनिटों की अपेक्षा 2×500 मेगा० की प्रतिष्ठापना के लिए 1547.80 करोड़ रु० के संशोधित लागत अनुमान उ०प्र०रा०बि०बो० ने अप्रैल, 1990 में प्रस्तुत कर दिए। के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, जोकि प्रतीक्षित है, के लिए अपेक्षित विभिन्न निवेशों को शामिल करते हुए 2×500 मेगा० के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उ०प्र०रा०बि०बो० से दिनांक 10.5.90 को अनुरोध किया गया था।
16.	जवाहरपुर (ता०वि०)	3×210=630	264.5	6/80	सिंगरौली कोयला क्षेत्रों पर भारी वचनबद्धता के कारण 1989-90 तक कोयला लिंकेज सुनिश्चित नहीं किया गया था। 1989-90 के बाद विचार हेतु इन स्कीमों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य को 2/81 में सूचित किया गया था। स्कीम राज्य को प्राप्त नहीं हुई है।
17.	रोसा (ता०वि०)	3×210=630	261.0	4/80	जल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके कारण एवं उ०प्र० में चालू परियोजनाओं के लिए सांसाधनिक बाधाओं के कारण परियोजना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, 3/83 में राज्य को सूचित किया गया था कि अन्य उपलब्ध विकल्पों के साथ-साथ लाभों के लिए इस पर फिर कभी विचार किया जा सकेगा।

1	2	3	4	5	6
18.	घौलीगंगा (मध्यवर्ती चरण) (ज०वि०)	4×50=200	415.0	8/90	विस्तृत तकनीकी आर्थिक विचार-विमर्श करके विकास की इष्टतम स्कीम को स्थापित करने के लिए अपेक्षित जांच पड़ताल पूरी करने के बाद रिपोर्ट पुन: प्रस्तुत किए जाने के लिए 12/90 को राज्य को लौटा दी गई है।
19.	नरौरा (ता०वि०)	3×210=630	360.1	3/82	परमाणु ऊर्जा विभाग ने सलाह दी थी कि इसके समीप परमाणु संयंत्र होने के कारण नरौरा में ताप विद्युत केन्द्र अवस्थित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को 6/82 में सूचित कर दिया गया था।
20.	प्रतापपुर (ता०वि०)	2×500=1000	898.3	1/84	स्कीम यू०पी०आर०वी०यू०एन० को 4/84 में यह कह कर वापिस की गई थी कि विस्तृत जांच-पड़ताल करें एवं मूल निवेश सुनिश्चित करें और परियोजना रिपोर्ट संशोधित करें जोकि प्रतीक्षित है।
21.	दादरी में गैस आधारित संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन संयंत्र (ता०वि०)	4×100 (जीटी) + 2×100 (एसटी) =600	586.4	11/88	दादरी में रा०ता०वि०नि० द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली 817 मेगा० क्षमता के प्रस्ताव को के०वि०प्रा० द्वारा पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। इसे मुद्देनजर रखते हुए, ऐसा महसूस होता है कि रा०ता०वि०नि० की स्कीमों के अलावा राज्य क्षेत्र में अन्य 600 मेगा० गैस टर्बाइन संयंत्र स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1	2	3	4	5	6
22.	दोहरीघाट (ता०वि०)	2×210=420	156.2	5/78	इस केन्द्र को स्थापित करने में इंदौर जंक्शन से दोहरीघाट के बीच मीटर गेज को ब्रोड गेज में बदलने का कार्य शामिल है और इस परिवर्तन के लिए रेलवे के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उपरोक्त स्थिति को एवं 1989-90 से पहले कोयला की गैर-लिंकेज को दृष्टिगत रखते हुए स्कीम पर के०वि०प्रा० में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उ०प्र०रा०बि०बो० को 2/81 में नियत अवधि में स्कीम को पुनर्जीवित करने की सलाह दी गई थी। उ०प्र०रा०बि०बो० ने 1/88 में सूचित किया कि दोहरीघाट में रेलवे लाइन की कठिनाई के कारण वैकल्पिक स्थल बेलथारा रोड (बलिया जिला) पर अवस्थित था। 12/88 में राज्य द्वारा बेलथारा रोड ता०वि०के० के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसकी जांच की जा रही है।
23.	किशाहू बहुउद्देशीय (ज०वि०)	4×150=600	460.0 678.0 (विद्युत)	2/78 (1) 2/88 (2)	हि०प्र० जो जलमग्नता के कारण हि०प्र० के साथ अंतर्राज्यीय पहलू निहित है और यमुना जल की हिस्सेदारी को अभी पुनः समाधान किया जाना है। लागत अनुमान सिंचाई एवं विद्युत की संयुक्त लागत को 1 : 1 में आवंटित करके तैयार किए गए हैं। (10/88 में राज्य को वापस)

1	2	3	4	5	6
24.	विष्णुप्रयाग (ज०वि०) (संशोधित)	4×120=480	345.0	10/87	प्रतिष्ठापित क्षमता के संबंध में जल विज्ञान एवं आयोजना संबंधी पहलुओं की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिए 12/86 में वापस ।
25.	बोवाला नन्द प्रयाग (ज०वि०)	3×44=132	179.0	1/89	केन्द्रीय जल आयोग के सुझाव के अनुसार जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों में संशोधन के बाद 6/89 में स्कीम/रिपोर्ट राज्य को वापस ।

दार्जिलिंग में हवाई पट्टी बनाना

1375. **श्री इन्द्रजीत** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में एक हवाई पट्टी की स्थापना के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 21.11.90 को दार्जिलिंग में भूमि का प्रारंभिक अध्ययन किया है।

(ख) और (ग). प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि टाइगर हिल पर लगभग 6500" × 150" की हवाई पट्टी का निर्माण किया जा सकता है किन्तु स्थल की आकृति संबंधी सीमाओं के कारण यह एक दिशिक धावनपथ ही बन सकेगा। मोटा अनुमान है कि भूमि की लागत के अतिरिक्त इस परियोजना की लागत 20 से 25 करोड़ रुपए होगी। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कहा गया है कि वह विस्तृत सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन करे। हवाई पट्टी का निर्माण, रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा परियोजना की स्वीकृति दिये जाने और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर करेगा।

दिल्ली के यमुना विहार में स्ट्रीट लाईट

[हिन्दी]

1376. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की यमुना विहार कालोनी में स्ट्रीट लाईट चालू हालत में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की है और मरम्मत कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). डेसू के अनुसार यमुना विहार में स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली कुल मिलाकर संतोषजनक है। डेसू ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटिंग के संबंध में शिकायतों पर कार्यवाही करने एवं स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली के रखरखाव के लिए समुचित प्रबंध किए हैं।

समस्तीपुर डिवीजन में हाल्टों का दर्जा बढ़ाया जाना

1377. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में कोरहिया, मुराय टेकयार और उद्यना हाल्ट कब से काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, इन हाल्टों से हुई आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन चार हाल्टों को एक पूर्ण स्टेशन के रूप में विकसित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन हाल्टों से होने वाली आय को वास्तविक आय की तुलना में कम दिखाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्यवर्ती औषधियों (ड्रग इंटरमीडिएट्स) के आयात पर लगने वाली सीमा-शुल्क की दरें

[अनुवाद]

1378. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मध्यवर्ती औषधियों के नाम क्या हैं जिनका देश में तो निर्माण नहीं होता परन्तु उसी बल्क ड्रग के निर्माण में उपयोग में लाए जाने के लिए आयात किए जाने पर उन पर सीमा-शुल्कों की अलग-अलग दरें लागू होती हैं;

(ख) क्या यह नीति औषध उद्योग के केवल कतिपय वर्गों के प्रति ही पक्षपातपूर्ण है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). मध्यवर्तियों की काफी संख्या ऐसी है जिनका देश में विनिर्माण नहीं होता है। अलग-अलग सूत्रयोगों पर सीमा शुल्क अलग-अलग प्रपुंज औषधों के उत्पादन की स्थिति और विनिर्माण की अवस्था के आधार पर लगाया जाता है। अंतर्ग्रस्त मध्यवर्तियों की संख्या काफी है और ब्यौरों को एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम उससे प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

राजस्थान में रेल-मार्गों को दोहरा करना

1379. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेल-लाइनों को दोहरा करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान में पड़ने वाले (i) हरिपुर और बर; (ii) बर और सेंदड़ा; और सरधना तथा दुरई के बीच दोहरी लाइन बिछाना स्वीकृत कार्य है।

(ख) 3 करोड़ रुपये।

(ग) 5 प्रतिशत।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के एककों द्वारा कोयले की राख का निपटान

[हिन्दी]

1380. **श्री दिलीप सिंह जू देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की राख के निपटान का कोई प्रबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केन्द्रों, विशेष रूप से कोरबा ताप विद्युत केन्द्र के कोयले की राख के निपटान और वैकल्पिक उपयोग का कोई प्रबंध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) राख को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है और एक राख कुंड में गारे के रूप में निस्सरित किया जाता है। राख नीचे बैठने के बाद निस्तारित पानी को विभिन्न पैरामीटर्स की उपयुक्त मानीटरिंग करने के बाद नजदीक की वाटर बाडी में छोड़ दिया जाता है।

(ग) से (ङ). उद्यमियों को ऐसे यूनिट स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें राख कुंड की राख का उपयोग करके राख आधारित उत्पाद बनाये जा सकें। वर्तमान में, राख आधारित निर्माण सामग्री निर्माताओं द्वारा कोरबा सुपर ताप विद्युत संयंत्र से थोड़ी मात्रा में राख ली जा रही है। यदि सम्भव हुआ तो कोरबा सुपर ताप विद्युत संयंत्र की मुख्य राख डाइक की ऊंचाई को विद्यमान राख कुण्ड में एकत्रित कोयला राख का उपयोग करके अधिक किया जायेगा। राख समुपयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा एक राख समुपयोजन प्रभाग स्थापित किया गया है।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल का आवंटन

[अनुवाद]

1381. **श्री अजीत कुमार पांजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को मास फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1991 के लिए आवंटित किये गये मिट्टी के तेल का कोटा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपर्युक्त महीनों के लिए मिट्टी के तेल का अतिरिक्त कोटा आवंटित किये जाने हेतु राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) पश्चिम बंगाल को फरवरी, 1991 में 64911 मी० टन एस०के०ओ० और मार्च, 1991 में 62044 मी० टन एस०के०ओ० का आवंटन किया गया है। अप्रैल, 1991 के लिए आवंटन अभी नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

रानीगंज कोयला क्षेत्र के कार्य माहौल में सुधार

1382. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के कार्य माहौल में सुधार करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितना पूंजी-परिव्यय होगा; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा और राज्य सरकार को इस मामले में क्या भूमिका दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) से (ग). कोयला क्षेत्र में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में काफी जानकारी तथा जागरूकता आ गई है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के संबंध में एक अग्रिम पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की गई है जो कि क्रमिक रूप में क्रियान्वित किए जाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगी। इस रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र में भूमि सुधार, पुनर्स्थापना, भूमि धंसाव, वायु तथा जल प्रदूषण आदि पर विचार किया गया है। इसके अलावा कोयला परियोजनाओं के लिए अलग-अलग पर्यावरणीय प्रबंधन योजना भी तैयार की जाती है जिनकी जांच पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। साथ ही निष्क्रिय पड़ी कोयला खानों में सुधार किए जाने के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक विशेष समिति गठित की थी जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा अन्य क्षेत्रों की निष्क्रिय पड़ी कोयला खानों में सुधार किए जाने के लिए कम लागत वाले प्रभावी उपायों के कुछ सुझाव दिए गए थे। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ई० को० लि० द्वारा लगभग 22.6 करोड़ रु० की राशि अपेक्षित होने का अनुमान है। उक्त सुझाव भी क्रमिक रूप से क्रियान्वित किए जाने हैं।

रानीगंज कोयला क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रश्न पर विगत में कुछ समय से पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। कोयला विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन, आदि के लिए एक संयुक्त प्राधिकरण स्थापित किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति की और संकेत किया है, जिसमें कोयला कंपनी, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि, पर्यावरणीय विशेषज्ञ, तथा जनता के प्रतिनिधि, आदि शामिल होंगे। कोयला विभाग इस उद्देश्य के लिए कोल इंडिया लि० के बजट से आरंभिक अंशदान के रूप में 5 करोड़ रु० की राशि दिए जाने के लिए भी सहमत हो गया है। उक्त प्राधिकरण की स्थापना के लिए राज्य सरकार से औपचारिक रूप में आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई

1383. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को उच्च प्राथमिकता देने के संबंध में केरल राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). केरल राज्य सरकार ने रेलों से कहा है कि केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सेला चावलों की ढुलाई करने के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार को मौजूदा नियमों के अनुसार उपर्युक्त यातायात को प्रायोजित करने के लिए कहा गया है ताकि रेलें आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

सौर ऊर्जा का दोहन

[हिन्दी]

1385. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान सौर ऊर्जा ग्रामों का विकास करने के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य नवीकरणीय एजेंसियों तथा विद्युत बोर्डों के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सौर जल तापन, सौर भभकें, सौर कुकर, प्रकाश-बोल्टीय, सड़क रोशनी व्यवस्था, घरेलू प्रकाश व्यवस्था और जल पंपन प्रणालियां जैसी सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना की जा रही है। इस कार्यक्रम को वर्ष 1991-92 के दौरान भी जारी रखने की संभावना है।

बिहार में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की एजेन्सियों का आबंटन

1386. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने व्यक्तियों को पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल की संयुक्त एजेन्सियां आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या इनके विरुद्ध अपमिश्रण, कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसी एक ही व्यक्ति को आबंटित करने संबंधी नीति में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) एक ही पार्टी को एक से अधिक डीलरशिप दिये जाने की प्रथा को 23 सितम्बर, 1977 से समाप्त कर दी गई है।

जालना में रेल उपरिपुल

[अनुवाद]

1387. **श्री पुंडलिक हरी दामधे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालना के नये प्रशासकीय परिसर में सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी अस्पताल के स्थानान्तरण को ध्यान में रखते हुए इस परिसर के निकट रेल पार पथ पर उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत् सहमति के साथ अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

जाली तेल कम्पनी

1388. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काम कर रही कोई जाली तेल कम्पनी पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की कम्पनियों के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ). मैसर्स हिन्दुस्तान आयल कम्पनी, गुरु रामदास भवन, रणजीत नगर, नई दिल्ली के विरुद्ध शाहदरा, दिल्ली के निवासी श्री वेद कुमार जसवाल द्वारा दिल्ली पुलिस (अपराध शाखा) के पास धोखाधड़ी की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, मैसर्स हिन्दुस्तान आयल कम्पनी ने उत्तर प्रदेश के समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन दिया था जिसमें एक ऐसे उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे जिसे मिट्टी के तेल के स्थान पर जलाने और रसोई बनाने के काम के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदकों के लिए कम्पनी के पक्ष में 200/- रुपये का मांग-ड्राफ्ट भेजना अपेक्षित था। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए साक्षात्कार के समय, आवेदकों द्वारा 10,000/- रुपए का मांग-ड्राफ्ट देना अपेक्षित था। शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने मैसर्स हिन्दुस्तान आयल कारपोरेशन के परिसर में छापा मारा और उनके रिकार्डों, कम्प्यूटर तथा प्लास्टिक केन को सील कर दिया जिसमें लगभग 0.75 लीटर "पावर तेल" था और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120 बी तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक चिह्न अधिनियम की धारा 78/79 के अधीन दिनांक 15.12.1990 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत एक मामला दर्ज किया। जांच करने पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के भाई भी थे। तथापि, दिनांक 22.12.1990 को न्यायालय ने इन तीनों व्यक्तियों की जमानत मन्जूर कर ली है। न्यायालय ने दिनांक 29.12.1990 के अपने आदेश के द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पुलिस से कहा है कि वह जब्त किए गए उत्पाद के रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त करें और वास्तविक पावर तेल से इसकी तुलना करें। यह मामला न्यायाधीन है।

सोवियत संघ द्वारा तेल की सप्लाई में कटौती

1389. **श्री बलवंत मणवर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण पिछले दो महीने के दौरान सोवियत संघ द्वारा भारत को तेल की सप्लाई में कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991 के प्रथम तीन महीनों में तेल की कितनी सप्लाई होने का अनुमान है और क्या सोवियत संघ अपने वायदे को पूरा कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ). कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए सोवियत रूस के साथ की गई संविदा कलेण्डर वर्ष के आधार पर है। चालू संविदा के लिए संविदा की अवधि दिसम्बर, 1991 तक है। इसलिए, प्रथम दो महीनों अर्थात् जनवरी और फरवरी, 1991 में आपूर्ति के आधार पर कमी का आकलन नहीं किया जा सकता। जनवरी-मार्च, 1990 के दौरान सोवियत रूस से कच्चे तेल और उत्पादों की अनुमानित आपूर्ति नीचे दी गई है :—

	मात्रा (हजार मीट्रिक टनों में)
कच्चा तेल	840
मिट्टी का तेल	108
एचएसडी	311

घाटे पर चलने वाले खान-पान एककों को बंद करना

1390. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे पर चल रही विभागीय खान-पान एककों को बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एककों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध करने का विचार है; और

(घ) नये विभागीय खान-पान एककों को खोलने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). कुछ ऐसी विभागीय यूनिटों का गैर-विभागीकरण करने का विनिश्चय किया गया है जिनमें घाटा हो रहा है। प्रारंभ में, क्षेत्रीय रेलों से कहा गया है कि वे प्रत्येक रेलवे पर गैर-विभागीकरण के लिए ऐसी तीन यूनिटों का चयन करें।

(ग) इन यूनिटों की प्रबन्ध-व्यवस्था उपयुक्त लाइसेंसधारियों द्वारा की जाएगी।

(घ) ऐसी कोई योजना नहीं है।

विवा-वसई रेल लाइन पर यात्री गाड़ी चलाना

1391. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या महाराष्ट्र के दिवा-वसई रेल लाइन पर यात्री सेवा प्रारम्भ करने की जोरदार मांग है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां, इस खंड में और अधिक गाड़ियां चलाने की मांग है। दीवा-बसई रोड के रास्ते चार जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां (साप्ताहिक) पहले ही चल रही हैं। दीवा-बसई रोड खंड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है चूंकि भिवंडी रोड पर केवल एक ही पार स्टेशन है और इस खंड पर माल यातायात का भारी संचलन होता है।

एअर इण्डिया के पास पुरावशेष

1392. **श्री सैफुउदीन चौधरी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इण्डिया के पास पुरावशेष हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी;

(ग) क्या ये पुरावशेष अभी भी एअर इण्डिया के पास हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). एयर इंडिया के पास 1197 पुरावशेष हैं जिनका बही मूल्य 13.17 लाख रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में रसोई गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

1393. **श्री केशरी लाल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1991 तक कानपुर में रसोई गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान कानपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कितने व्यक्तियों को रसोई गैस कनैक्शन दिए गए; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के शेष व्यक्तियों को कब तक रसोई गैस कनैक्शन दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). दिनांक 31 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार, कानपुर शहर में एल०पी०जी० के नए कनैक्शनों के लिए लगभग 0.9 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। वर्ष 1990 के दौरान कानपुर

शहर में 8,800 एल०पी०जी० कनैक्शन दिए गए। वर्तमान नीति के अनुसार, उन शहरों/कस्बों में चरणबद्ध तरीके से एल०पी०जी० की सुविधा दी जा रही है जहां की आबादी 20,000 और इससे अधिक है जहां डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता स्थापित हो जाती है बशर्ते कि उत्पाद समग्र रूप से उपलब्ध हो। इनमें पहाड़ी क्षेत्र तथा वे स्थान शामिल नहीं हैं जो वर्तमान बाजारों और उन ग्रामों के समीप हैं और साथ ही वे क्षेत्र भी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विस्तारित कार्य-क्षेत्र के अन्दर आते हैं।

(ग) चूंकि एल.पी.जी. ऐसा उत्पाद है जिसकी कमी है और उपभोक्ताओं का नामांकन सीमित होने के कारण यह बता पाना कठिन है कि प्रतीक्षा-सूची वाले सभी व्यक्तियों को कब तक कनैक्शन दिए जाएंगे।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सुविधाएं

[अनुवाद]

1394. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये आधारभूत संरचना और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विदेशों से त्रिवेन्द्रम को और उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने की सुविधाएं पहले से ही त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उपलब्ध हैं। अब चूंकि त्रिवेन्द्रम को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित कर दिया गया है अत: इन सुविधाओं का लगातार उन्नयन किया जाता रहेगा।

(ग) अब चूंकि 1 जनवरी, 1991 से त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है, अत: विदेशी एयर लाइनों द्वारा सीधे त्रिवेन्द्रम तक परिचालन किये जाने की संभावना हो गई है। किस हद तक ये परिचालन होंगे यह संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा करारों पर निर्भर करेगा।

महाबलीपुरम से मद्रास तक रेल लाइन

1395. **श्री बी० राज रवि वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाबलीपुरम और मद्रास के बीच रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

[हिन्दी]

1396. **श्री राघवजी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मध्य प्रदेश में उन नई रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण-कार्य आजकल प्रगति पर है; और

(ख) कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण-कार्य 31 मार्च, 1992 तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रस्तावित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है :—

(1) बिलासपुर-मुंगेली-मांडला-जबलपुर।

(2) ललितपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खजुराहो और रीवा-सीधी-सिंगरौली।

(3) झांसी-शिवपुरी-शिवपुर कलां-सवाई माधोपुर।

(4) नीमच-रतलाम

(5) भोपाल-रामगंज मंडी

(ख) निम्नलिखित नयी रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण का कार्य मार्च, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है :—

(1) बिलासपुर-मुंगेली-मांडला-जबलपुर

(2) ललितपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खजुराहो और रीवा-सीधी-सिंगरौली

(3) भोपाल-रामगंज मंडी।

बिजली उत्पादन की लागत

[अनुवाद]

1397. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या बिजली की उत्पादन-लागत में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग). अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों को हानियां हुई हैं जिनकी राशि 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार 3819.86 करोड़ रु० बैठती है। हानियां, विभिन्न घटकों यथा विद्युत उत्पादन का निम्नस्तर होने, पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा अधिक होने, संयंत्र रख-रखाव के घटिया स्तर होने, कृषि क्षेत्र को रियायती दर पर विद्युत सप्लाई किए जाने, टैरिफ का स्तर अलाभकारी होने, पूंजीगत ढांचा पूर्णतः ऋण पर आधारित होने, ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता की पूर्ति के लिए राज्यों के पास समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण होती हैं।

राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत उत्पादन और सप्लाई की औसत लागत जोकि 1984-85 में 65.07 पैसे प्रति किलोवाट आवर थी बढ़कर 1988-89 में 96.29 पैसे प्रति किलोवाट आवर हो गई। इसका कारण ईंधन की लागत, ब्याज संबंधी घटक की राशि, विद्युत क्रय मूल्य की लागत, ताप विद्युत घटक की अपेक्षा जल विद्युत घटक के अंशदान में वृद्धि होना है।

पेट्रोल में एल्कोहल का उपयोग

139°. **श्री ए०के० राय :**

श्री पी०आर० कुमारमंगलम :

श्रीमती सुभाषिनी अली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अल्कोहल का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या वर्तमान ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार का विचार पेट्रोल में एल्कोहल का उपयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1989-90 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान 928 मिलियन लिटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ था।

(ख) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल और डीजल की कमी

1399. **श्री बी०एन० रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आंध्र प्रदेश में मिट्टी के तेल और डीजल की भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन वस्तुओं की कमी को दूर करने हेतु कोटे में वृद्धि कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच०एस०डी० की आपूर्ति फिलहाल गत वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के समान स्तर पर की जा रही है।

कृषि क्षेत्र के लिए आन्ध्र प्रदेश को फरवरी, 1991 में सामान्य हक के अतिरिक्त 2100 मी० टन एच०एस०डी० का विशेष आबंटन किया है।

आन्ध्र प्रदेश के लिए 1989 और 1990 में किये गये एस०के०ओ० का आबंटन नीचे दिया गया है :—

	(टन)
जनवरी—दिसम्बर, 1989	550771
जनवरी—दिसम्बर, 1990	582564

पांसकुरा और हल्दिया के बीच हाल्ट स्टेशन

1400. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे पर पांसकुरा और हल्दिया के बीच एक नया यात्री हॉल्ट स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मधुपुर लोको शेड

[हिन्दी]

1401. **श्री जनार्दन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मधुपुर लोकोशेड को बंद करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). परिचालनिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप 1985-86 के दौरान इस शेड का इंजनों को खड़ा करने वाले शेड के रूप में उपयोग करना बन्द कर दिया गया था । बहरहाल, आउट स्टेशन इंजनों की देखभाल की सुविधा, जो अब भी मौजूद है, को उस समय बन्द कर दिया जायेगा जब आसपास के क्षेत्रों में गाड़ी सेवाओं के डीजलीकरण के लिए और अधिक डीजल इंजन उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि मितव्ययिता, कुशलता और परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए सन् 2000 ई० तक भाप कर्षण को डीजल तथा बिजली कर्षण से बदल देने की रेलों की वचनबद्धता है ।

मद्रास-दादर एक्सप्रेस को पुन: चालू करना

[अनुवाद]

1402. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-दादर एक्सप्रेस जिसे निरस्त कर दिया गया था, को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). 6511/6512 मद्रास-दादर एक्सप्रेस, जिसे 28.1.1991 से चलाना बन्द कर दिया गया था, को जनता की मांग पर 11.2.91 से पुन: चला दी गई है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे का विकास

1403. **श्री अमल दत्त** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, एअर इण्डिया की उड़ानों में क्षेत्र-वार, कितने यात्रियों ने यात्रा की तथा इसकी हानि एवं लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कलकत्ता हवाई अड्डे को अधिक से अधिक उड़ानों से जोड़ने के लिए विदेशी विमान कम्पनियों एवं एअर इण्डिया को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 1985 से सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ानों में लाये—ले जाये गए यात्रियों की संख्या और मार्गवार रोकड़ बचत/घाटा दर्शाता हुआ एयर इण्डिया का मार्गवार निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय एअर इंडिया कलकत्ता से होकर निम्नलिखित उड़ानें परिचालित करता है :

ए.आई. 306—बम्बई-कलकत्ता-बैंकाक

ए.आई. 1328—दिल्ली-कलकत्ता

ए.आई. 101—कलकत्ता-बम्बई-लंदन-न्यूयार्क

सभी द्विपक्षीय वार्ताओं में, विदेशी एयर लाइनों को रियायती शर्तों पर कलकत्ता से परिचालन करने की पेशकश की जाती है। तथापि, कलकता के लिए परिचालन करने का निर्णय-सम्बन्धित एयर लाइन के पास रहता है।

विवरण

मार्गवार रोकड़ लाभ (करोड़ रुपयों में,) और यात्री संख्या

मार्ग	1989-90		1988-89		1987-88	
	यात्री संख्या	रोकड़ बचत (घाटा)	यात्री संख्या	रोकड बचत (घाटा)	यात्री संख्या	रोकड़ बचत (घाटा)
भारत-अमरीका	318302	66.81	332033	67.92	358831	45.64
भारत-यू.के.	151721	26.37	170069	21.53	162674	7.06
भारत-महाद्वीप	301999	77.76	216297	38.89	185267	21.82
भारत-जापान	171155	51.59	161043	39.48	145308	23.79
भारत-आस्ट्रेलिया	69233	10.88	75159	10.88	66678	3.32
भारत-रूस	45350	15.68	38749	12.26	31859	7.65
भारत-सिंगापुर	118267	17.58	151189	14.48	171026	7.69
भारत-हांगकांग	57268	5.22	54941	4.51	57474	1.86
भारत-पूर्व अफ्रीका	42381	6.48	27475	4.03	22489	1.83
भारत-पश्चिम अफ्रीका	—	—	—	—	7259	0.57
भारत-खाड़ी	953599	219.85	883245	165.17	896187	140.97

आईडीपीएल द्वारा क्लोरोक्वीन फास्फेट की सप्लाई

1404. **डा० असीम बाला** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्लोरोक्वीन फास्फेट की सप्लाई के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को कोई ठेका दिया गया;

(ख) क्या आईडीपीएल ने मैसर्ज नील माधव कान्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को इन क्रयादेशों के लिए किसी प्रकार के कमीशन का भुगतान किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितना कमीशन दिया गया और इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) आईडीपीएल के विरुद्ध ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) क्लोरोक्विन फास्फेट की 200 मिलियन टिकियों की सप्लाई के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को 1989-90 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय (एनएमईपी) द्वारा एक क्रयादेश दिया गया था।

(ख) और (ग). आईडीपीएल और एजेन्ट के बीच संविदा के अनुसार मैसर्स नील माधव कंसल्टेंटस प्राइवेट लि० को 9.02 लाख रु० की राशि अदा की गई थी।

(घ) और (ङ). सरकार मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली में बैटरी चालित बसें

1405. **डा० सी. सिलवेरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में बैटरी चालित बसों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बसों को चलाने हेतु किन मार्गों का चयन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग). जी हां, दिल्ली प्रशासन का अपनी वर्तमान 101 बैटरी बसों के बेडे में 50 नई बैटरी बसें शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान बसों के बेडे का पूर्णरूपेण निष्पादन के बाद ही नई बसों का मार्ग निश्चित किया जाएगा।

लोकटक पन-बिजली परियोजना

1406. **श्री एन. तोम्बी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकटक पन-बिजली परियोजना के लिए अपेक्षित लोकटक झील में उच्च जल स्तर की वजह से हजारों एकड़ में धान के क्षेत्र पानी में डूब गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम दिल्ली में गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना

1407. **श्री जी.एस. बासवराज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में, विशेष रूप से तिलक नगर के 15 ब्लाक में गलियों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का पश्चिम दिल्ली तथा तिलक नगर के उद्यानों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ङ). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार ब्लॉक 15, तिलक नगर समेत पश्चिम दिल्ली में गलियों में प्रकाश सम्बन्धी कुछ सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं। दिल्ली नगर निगम के अनुरोध अथवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी अन्य किसी एजेंसी द्वारा भुगतान किए जाने के आधार पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान गलियों में प्रकाश सम्बन्धी सुविधा प्रदान करता है तथा इसकी व्यवस्था करता है। इसलिए उक्त क्षेत्र की गलियों में प्रकाश की विद्यमान प्रणाली में सुधार किए जाने के लिए अथवा पार्क के गलियारों में प्रकाश सम्बन्धी सुविधा का विस्तार किये जाने आदि से सम्बन्धित किसी भी नई स्कीम को दिल्ली नगर निगम/सम्बन्धित विकास एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना तथा वित्त पोषण किया जाना अपेक्षित है ।

देवस्थली, बलिया में विशेष हेलीपैड

1408. **श्रीमती उमा गजपति राजू** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवस्थली (बलिया) में प्रति विशिष्ठ व्यक्तियों के आने-जाने के लिए विशेष हेलीपैड बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) इन हेलीपैडों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अयोध्या जाने वाली गाड़ियों को उनके गंतव्य स्थान से पहले रोक लेना

1409. **कुमारी उमा भारती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर, दिसम्बर, 1990 के दौरान उन गाड़ियों को अपने गंतव्य स्थान पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया था जिनमें कार सेवक अयोध्या जाने के लिए यात्रा कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कार सेवकों को गाड़ियों के अपने गंतव्य स्थान तक न जाने तथा बीच में रोके जाने की सूचना उनके द्वारा टिकट खरीदे जाने से पहले दे दी गई थी;

(घ) उन गाड़ियों की संख्या कितनी है जिन्हें अपने गंतव्य स्थान से पहले रोका गया था;

(ङ) क्या यात्रा न की गई दूरी के पैसे कार सेवकों को लौटाए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो किन नियमों के अंतर्गत अदा करने से मना किया गया है;

(छ) क्या जब कार सेवक पैसे की वापसी के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे, तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया तथा उन्हें गलत सूचना दी गई; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कानून और व्यवस्था की जोखिम भरी स्थिति के कारण ।

(ग) जहां तक संभव था गाड़ियों को रद्द करने अथवा गंतव्य स्थान से कुछ पहले उन्हें समाप्त करने का कार्यक्रम बनाया जा सकता था और इसकी घोषणा की जा सकती थी, ऐसा ही किया भी गया । स्थिति को देखते हुए, गाड़ी सेवाओं को दिन-प्रतिदिन के आधार पर विनियमित करना पड़ा था ।

(घ) 84 जोड़ी ।

(ङ) जी हां ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) जी नहीं ।

(ज) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करना

1410. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के अंतिम मूल्य निर्धारण की वर्तमान प्रक्रिया के कारण अधिक मुनाफा होने लगा है तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हाथों आंतरिक संसाधनों को तेल उद्योग विकास बोर्ड को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस संबंध में तथ्यों एवं आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मुनाफे और आंतरिक संसाधन तेल उद्योग विकास बोर्ड को सौंपे जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रकार कितनी धन राशि सौंपी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). जी, नहीं । तेल एवं प्राकृतिक गैस की लाभोत्पादकता कच्चे तेल की उस निबल कीमत पर, जो उसे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की एवज में मिलती है, और उसके प्रचालन की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है । और न कि पेट्रोलियम उत्पादों की अंतिम कीमत पर आधारित होती हैं ।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-चंदौसी-मुरादाबाद और लखनऊ-दिल्ली सेक्शनों पर रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

1411. **श्री राजवीर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाया चनेहटी, "आंवला" चंदौसी और मुरादाबाद से होकर लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ पंजाब तक एक रेलगाड़ी शुरू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये रेल सेवाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

1412. **श्री शिव शरण वर्मा** :

प्रो० के०वी० थामस :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की गलत माप और बड़े पैमाने पर मिलावट की जालसाजी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (घ). दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की गलत माप और बड़े पैमाने पर मिलावट करने वाले गिरोह के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसे कदाचारों की जांच करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित, अचानक और संयुक्त रूप से निरीक्षण तेल कम्पनियों और दिल्ली प्रशासन द्वारा समय-समय पर किया जाता है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल पंपों की स्थापना

1413. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय स्थानों पर पेट्रोल और डीजल पंप लगाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी हां। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन स्थानों पर किये गये बाजार सर्वेक्षण से गाजीपुर जिले में बरूई, बलिया जिले में मांझीघार, जौनपुर जिले में हरिहरपुर, बहराइंच जिले में नानपाड़ा और लखीमपुर के बीच एक स्थान पर एक-एक खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने की व्यवहार्यता स्थापित हुई है। जब कि गोरखपुर जिले में राप्ती नगर, विकासनगर और लघुनगर तथा आजमगढ़ जिले में कप्तानगंज बाजार के संबंध में व्यवहार्यता स्थापित नहीं हुई है।

गुजरात में औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि

[अनुवाद]

1414. **श्री कमल नाथ** :

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के औद्योगिक गैस उपभोक्ताओं को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भारी धनराशि की अदायगी करनी पड़ती है;

(ख) उनके द्वारा देय राशि को इससे पूर्व वसूल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो उन औद्योगिक उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक से कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी है; और

(घ) इस धन राशि की शीघ्र वसूली करने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां। दोनों अर्थात् निजी तथा सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक गैस उपभोक्ताओं को पहले की गई गैस की आपूर्ति के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को काफी बड़ी राशि का भुगतान करना है।

(ख) उपभोक्ताओं और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच विभिन्न विवादों की वजह से वसूली नहीं की जा सकी। निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में, यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन भी था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में, यह मामला उच्चतम न्यायालय में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पक्ष में गया है और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उनसे प्राप्य बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, वसूली

करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग इस मामले को संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ उठा रहा है।

विवरण

पहले दी गई गैस की आपूर्ति के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की बकाया राशि

उपभोक्ता	राशि (करोड़ रुपए)
I. सार्वजनिक क्षेत्र उपभोक्ता	
1. जीईबी	70
2. जीएसएफसी	113
3. आईएफसीओ	217
4. बीएमसी	30
5. एचडब्लयूपी	55
6. अन्य जैसे जीएनएफसी, जीआईडीसी कादी और जीआईडीसी अहमदाबाद	1
	486
II. उच्चतम न्यायालय में पार्टियां	
1. दिनेश मिल	3.93
2. अम्बीका मिल	2.21
3. न्यू इण्डिया इण्डस	2.57
4. प्रियलक्मी मिल	7.88
5. पंजाब स्टील रोलिंग मिल	2.39
6. साराभाई कामन सर्विस	19.90
7. अलैम्बीक ग्लास	30.67
8. अलैम्बीक कैमिकल्स	8.97
9. चन्दन मैटल उत्पाद	0.13
10. जैयन्त पेपर मिल	2.52
11. गुजरात ग्लास लि०	3.50
12. मेलाबूड एण्ड इंजी० वर्कस	0.70
13. मेलामाइन फाइबर बोर्ड	0.72
14. महेन्द्रा मिल	8.86

15. भारत विजय मिल	6.89
16. केलिको मिल, कलोल	4.80
17. नवजीवन मिल	6.95
18. केलिको मिल अहमदाबाद	20.96
19. केलिको डाइंग एण्ड प्रिंटिंग	0.04
	134.59

III. खादी उपभोक्ता

1. गोविन्द विलर्ड एण्ड वायरड ग्लास	1.22
2. मधुसूदन वैज० प्रोडक्ट	0.27
3. सोनिया सेराभिक्स	0.10
4. अमोल डिकोलाइट	0.08
5. वीसी इण्डस्ट्रीज	0.04
6. जय भवानी ग्लास	0.12
7. गुजरात क्रोमियम लि०	0.55
8. क्ले प्रोडक्टस	0.14
9. सोमानी फिल्किटन लि०	0.21
10. स्वास्तिक स्नेटरी वेयरस	0.08
11. इन्टरक्लीन	0.08
	2.89

IV. डब्ल्यू आरबीसी में अन्य औद्योगिक उपभोक्ता

1. वैस्टर्न इण्डिया सेरामिक्स	2.68
2. प्रगति ग्लास वर्कस	2.66
3. साईनाइडस एण्ड कैमिकल्स	1.09
4. दूध सागर डेरी	1.40
5. साबरकान्ता डेरी	1.69
6. केसरिया इन्वैस्टमैंट	0.01
7. रिलाइंस इण्डस्ट्रीज	5.06
	14.59

कावेरी, बम्बई हाई और पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज

1415. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय कावेरी तट और बम्बई तक पश्चिम बंगाल तटों पर तेल की खोज में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में तेल की खोज सोवियत कम्पनी के सहयोग से की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस ठेके की शर्तें क्या हैं; और

(घ) खाड़ी संकट के बाद तेल की खोज की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कावेरी बेसिन के तटीय क्षेत्र के कुछ कुंओं में तेल के भण्डार होने के हल्के संकेत मिले हैं। पश्चिम बंगाल बेसिन में हाइड्रोकार्बन के कोई वाणिज्यिक भण्डार नहीं मिले हैं। जहां तक बम्बई बेसिन का प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने, दिनांक 1.1.1990 की स्थिति के अनुसार, बम्बई अपतटीय बेसिन में 609.9 मिलियन टन तेल तथा 498.6 बिलियन घन मीटर गैस पहले ही स्थापित किया है।

(ख) कावेरी और पश्चिम बंगाल बेसिनों में, सोवियत रूस और भारत के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के करार के अनुसार "गहन समेकित अन्वेषण कार्यक्रम" के अधीन अन्वेषण-कार्य किया जा रहा है। बम्बई बेसिन में, अकेले तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) करार की मुख्य शर्तों के अनुसार, सोवियत पक्ष को कावेरी और पश्चिम बंगाल बेसिनों की आपसी सहमति प्राप्त क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों के "गहन समेकित अन्वेषण" के लक्ष्य के साथ अन्वेषी ड्रिलिंग कार्य करने के लिए भू-कंपयी सर्वेक्षण, भू-कंपयी आंकड़ों का संसाधन और खनन-योग्य पूर्वेक्षण के सृजन की विवृति का काम करना है।

(घ) राज्य तेल कम्पनियों के गहन अन्वेषी कार्यक्रम के अलावा, बोली के चौथे दौर में भारत में तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों को आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य

[हिन्दी]

1416. **श्री लरंग साय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल की कुल उत्पादन क्षमता, बम्बई हाई में हाल ही में मिले तेल को शामिल कर, कितनी है; और

(ख) वर्ष 2000 ई० तक तेल उत्पादन का क्या लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) भारत

में 5.7 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन के भू-गर्भीय भंडार स्थापित हुए हैं। इनमें से 1.9 बिलियन टन भंडार खनन-योग्य भंडार हैं। पिछले कुछ वर्षों में शेष खनन योग्य भंडारों के कच्चे तेल के वार्षिक उत्पादन का प्रतिशत 4.4 से 5.32 के बीच रहा है जो आज की स्थिति के अनुसार, देश की कुल तेल उत्पादन क्षमता है।

(ख) सन् 2000 ई० के लिए तेल उत्पादन का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

बिहार में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

1417. **श्री राम दास सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). एचएसडी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए बिहार सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। नवम्बर, 1990 में बिहार के लिए 5000 मी० टन एच एस डी का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। फरवरी, 1991 में कृषि के कामों के लिए बिहार के लिए 1,800 मी० टन एच एस डी का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया है।

पेट्रोल/डीजल पम्प तथा रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

1418. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों के दौरान कितनी पेट्रोल/डीजल तथा रसोई गैस एजेंसियां प्राथमिकता के आधार पर बिना बारी के आबंटित की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : पिछले तीन महीनों के दौरान कोई एल.पी.जी. वितरण केन्द्र और खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) बारी से पहले नहीं दिए गए हैं।

क्लटर बक गंज में स्लीपर संयंत्र

1419. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन क्लटर बक गंज बरेली स्थित स्लीपर संयंत्र बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसे किसी गैर सरकारी संगठन को अन्तरित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) साफ्ट लकड़ी के स्लीपरों का कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मुआवजा सम्बन्धी दावों के कारण होने वाला घाटा

[अनुवाद]

1421. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को गत एक वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त माल के मूल्य के तौर पर मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ा;

(ख) ऐसे घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) दावा करने तथा दावेदारों को अन्तिम रूप से की गई अदायगी के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1989-90 के दौरान रेलों द्वारा ढुलाई के लिए बुक किए गए माल के नुकसान/क्षति के लिए, क्षतिपूर्ति हेतु 30.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था ।

(ख) रेलें ढुलाई के लिए सुपुर्द किए गए माल की संरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही हैं ताकि रेलों को प्राप्त परेषण अपने गंतव्य को बिना चोरी या क्षति के पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न निवारक उपाय किए गए हैं जिसमें परेषणों की उपयुक्त पैकिंग, चिह्नित करना और लेबल लगाना, ब्रेकयानों तथा सामानयानों की उपयुक्त पेड लार्किंग, वाणिज्य दृष्टि से उपयुक्त माल-डिब्बों का इस्तेमाल, अति संवेदनशील क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल द्वारा मालगाड़ियों की सुरक्षा, आकस्मिक जांच तथा रेल सुरक्षा बल और राज्य रेलवे पुलिस के बीच गहन संपर्क तथा समन्वयन करना आदि शामिल हैं । ब्लाक रेकों द्वारा माल का तत्काल प्रेषण किया जाता है ताकि पारवहन में नुकसान और क्षति से बचा जा सके ।

(ग) रेलों को दावों का निपटान करने के लिए शीघ्र जांच और कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

तमिलनाडु में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करना

1422. **श्री एन. डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत केन्द्र के प्रस्तावित स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). तमिलनाडु राज्य में

राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किये जाने का कार्यक्रम है :—

परियोजना का नाम और क्षमता		चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम
(1) तूतीकोरिन चरण-3 (2×210 मे०वा०), जिला वी.ओ. चिदम्बरानार	यूनिट-5	1990-91
	यूनिट-4	1991-92
(2) नार्थ मद्रास ता०वि० केन्द्र (3×210 मे०वा०) जिला चिंग्लापेट	यूनिट-1	1993-94
	यूनिट-2	1993-94
	यूनिट-3	1994-95
(3) गैस टर्बाइन संयंत्र बेसिन ब्रिज (मद्रास) (4×30 मे०वा०)	यूनिट-1	1991-92
	यूनिट-2	1991-92
	यूनिट-3	1992-93
	यूनिट-4	1992-93
(4) नरीमनम गैस टर्बाइन (जिला तंजानूर) (2×5 मे०वा०)	यूनिट-1	1991-92
	यूनिट-2	1991-92

पटना शहर में रेल पुल

[हिन्दी]

1423. **प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना शहर में चिरायाटंड रेल पुल को चौड़ा करने, नवीकरण करने तथा इसकी मरम्मत करने संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल को चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। स्थल की तंगी के कारण वर्तमान पुल को चौड़ा करना व्यावहारिक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश की पन-विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

1424. **श्री महेश्वर सिंह** :

श्री के०डी० सुल्तानपुरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सर्वेक्षणाधीन पन-विद्युत परियोजनाओं के लिए वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). वर्ष 1990-91 के दौरान, हिमाचल प्रदेश में जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का परियोजनावार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1.	पार्वती	25.00
2.	अलियां	15.00
3.	हिबरा	30.00
4.	सावरा कुड्डु	30.00

औरंगाबाद हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाएं

[अनुवाद]

1425. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाएं विद्यमान होने के बावजूद औरंगाबाद से इंडियन एयरलाइंस की रात्रि में नियत उड़ानों में प्राय: विलंब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) इंडियन एयरलाइंस की रात्रि में औरंगाबाद से कोई अनुसूचित उड़ान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि

1426. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रेणी-I और श्रेणी-II औषधों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). श्रेणी I और II प्रपुंज औषधों की कीमतों में वृद्धि करने का कोई आम या खास प्रस्ताव नहीं है । डी०पी०सी०ओ०, 1987 के उपबन्धों के अन्तर्गत समय-समय पर गुणावगुण के आधार पर मूल्यों में संशोधन करने पर विचार किया जाता है।

भारतीय तथा विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा तेल की खोज तथा उत्पादन

1427. **श्री डी०एम० पुट्टे गौड़ा** :

श्री लरंग साय :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलग-अलग कच्चे तेल के उत्पादन तथा खोज की गति को तीव्र करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में तेल भंडार की संभावना वाले कुछ ब्लाकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां। यह निर्दिष्ट करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं कि क्या चौथे दौर में तेल के अन्वेषण के लिए तेल कम्पनियों को कुछ ब्लाक आफर किए जा सकते हैं। तथापि इस संबंध में अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-मेरठ रेलवे लाइन को दोहरा किया जाना

1428. **श्री हरीश पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मेरठ के बीच रेलवे लाइन को विकसित और दोहरा किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दिल्ली और मुरादनगर के बीच दोहरी लाइन मौजूद है। फिलहाल मुरादनगर से आगे दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुस्तक स्टालों का आवंटन

1429. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर पुस्तक स्टालों की आवंटन नीति से संबंधित मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या इस नीति की समीक्षा करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार, नए बुक स्टाल के सभी ठेके बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारिताओं, भागीदारों, एसोसिएशनों और वास्तविक कार्यकर्त्ताओं और वेंडरों की सहकारी समितियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

1430. **श्री आर०एन० राकेश :**

श्री चिन्ता मोहन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में किये गए लक्ष्य की तुलना में कम हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी कम थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति के बीच कुल कितना अन्तर था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 251300 मिलियन यूनिट था । सातवीं योजना के प्रथम वर्ष (अर्थात् 1985-86) के दौरान 170037 मिलियन यूनिट वास्तविक विद्युत उत्पादन की अपेक्षा 1989-90 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 245141 मिलियन यूनिट था जोकि 44.17 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है ।

1989-90 के दौरान 247762 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता की अपेक्षा वास्तव में 228151 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी जोकि 7.9 प्रतिशत कमी का द्योतक है ।

नई रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

1431. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई और रद्द की गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में और रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

विवरण

(क) I. **चलाई गई गाड़ियां**

1. 6687/6688 जम्मू तवी-मंगलोर/तिरुचिरापल्ली नवयुग एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) ।
2. 4245/4246 सूरत-वाराणसी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) ।
3. 8631/8632 हटिया-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) ।
4. 5651/5652 जम्मू तवी-गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार) ।
5. 1147/1148 दादर-मुजफ्फरपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार) ।

6. 5049/5050 गोरखपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)।
7. 5303/5304 गोंडा-गोरखपुर एक्सप्रेस (मीटर लाइन)।
8. 5719/5720 कटिहार-सिलिगुडी इंटरसिटी एक्सप्रेस।
9. 269/270 पैसेंजर गुंटूर और माचेरला के बीच।
10. 263/264 पैसेंजर गुंटूर और माचेरला के बीच।
11. 279/280 पैसेंजर गुंटूर और सत्तनपल्ली के बीच।
12. 267/268 पैसेंजर गुंटूर और सत्तनपल्ली के बीच।
13. 253/254 पैसेंजर माचेरला और नडिकुडे के बीच।
14. 3303/3304 धनबाद-चोपन एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)।
15. 19 जेबी/20 जेबी जसीडीह-वैद्यनाथधाम पैसेंजर।
16. 431/432 रामपुरहाट-साहिबगंज पैसेंजर।
17. 360/361 बिलासपुर-गेवेरा रोड पैसेंजर।
18-19. 2701/2702-2703/2704 निजामुद्दीन-वास्को-डि-गामा गोवा एक्सप्रेस (व०ला० एवं मी०ला०)
20. 2401/2402 नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस।
21. 2403/2404 कानपुर-वाराणसी श्रमिक एक्सप्रेस।
22. 5003/5004 गोरखपुर-इलाहाबाद चौरी-चौरा एक्सप्रेस।
23. 229/230 गांधी धाम-न्यू भुज-नलिया पैसेंजर।
24. 315ए/316ए हवड़ा-बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर।

II. रद्द की गई गाड़ियां

1. 357/362 कोरबा-चांपा पैसेंजर।
2. 510 मचिलीपत्तनम्-गुडिवाडा पैसेंजर।
3. 511/512 मचिलीपत्तनम्-विजयवाडा पैसेंजर।
4. 517 विजयवाड़ा-मचिलीपत्तनम् पैसेंजर।
5. एच०डी०-3/डी०एच०-8 हुबली-धारवाड पैसेंजर।
6. 705/706 तिरुच्चि-मणप्पारै पैसेंजर (सप्ताह में एक बार)।
7. 141/142 शाहजांपुर-केरुगज पैसेंजर।
8. 453-454/सहरसा-सुपौल पैसेंजर।
9. 1633/1634 बडनेरा-अमरावती पैसेंजर।
10. 1643/1644 बडनेरा-अमरावती पैसेंजर।

11. 1647/1648 बडनेरा-अमरावती पैसेंजर।

12. 1529/1530 ऐट-कोंच पैसेंजर।

13. 539/540 कटिहार-सिलिगुडी पैसेंजर।

14. 333/336 एर्णाकुलम-अल्लेप्पी पैसेंजर।

15. 6271/6272 मंगलोर-अरसीकेरे पैसेंजर।

(ग) **चलाई जाने वाली प्रस्तावित गाड़ियां**

1. बम्बई-वाराणसी एक्सप्रेस।

2. तिरुपति-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस (नडिकुडे होकर)।

3. बम्बई सेन्ट्रल-अहमदाबाद इंटर सिटी, एक्सप्रेस।

4. रांची-राऊरकेला लिंक एक्सप्रेस सेवा जिसे बम्बई-हवड़ा एक्सप्रेस से जोड़ा जाना है।

5. बेंगलूरु-तिरुपति इंटर सिटी एक्सप्रेस।

6. इलाहाबाद-आगरा कैंट एक्सप्रेस।

7. इलाहाबाद सिटी-छपरा एक्सप्रेस (मी०ला०)।

8. फिरोजपुर कैंट-जम्मू तवी एक्सप्रेस।

9. विशाखपट्नम-नयी दिल्ली एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चलने वाली।

10. पुरी-तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस।

11. पोरबन्दर-बांस जालिया पैसेंजर।

12. रायगडा-सम्बलपुर एक्सप्रेस।

मलकापुर स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ियों हेतु आरक्षण कोटे में वृद्धि का प्रस्ताव

1432. **श्री सुखदेव नन्दाजी काले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मलकापुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली सभी रेलगाड़ियों हेतु आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, इस स्टेशन पर 26.3.1991 से 1057 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस द्वारा भुसावल से अमृतसर तक दूसरे दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा आबंटित किया जा रहा है।

(ग) स्थान की सीमित उपलब्धता और मौजूदा कोटा वाले स्टेशनों पर कोटे का पूर्ण उपयोग होने के कारण इस स्टेशन पर कोटा बढ़ाने की दृष्टि से कोई समायोजन करना व्यावहारिक नहीं है।

दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को नियमित करना

1433. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में क्षेत्र-वार, कितने दैनिक वेतनभोगी श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1.10.90 को रेलों पर कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों की क्षेत्र-वार संख्या इस प्रकार है :—

मध्य	29106
पूर्व	12368 (1.4.90 को)
उत्तर	31947
पूर्वोत्तर	12395
पूर्वोत्तर सीमा	8655
दक्षिण	10663
दक्षिण मध्य	12648
दक्षिण पूर्व	12773
पश्चिम	15694

(**टिप्पणी** : यद्यपि इन श्रमिकों को नैमित्तिक श्रमिक कहा जाता है फिर भी इनमें से अधिकांश को मासिक वेतन का भुगतान किया जाता है।)

(ख) कतिपय अपवादों को छोड़कर, इस समय ग्रुप "घ" में सभी रिक्तियां वस्तुतः स्क्रीनिंग करने के बाद नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों का समाहन करके भरी जा रही हैं। लेकिन नियमित नियोजन में नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों का समाहन रिक्तियों और पात्रता की उपलब्धता तथा नियमित नियोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता जैसे कारकों के अनुसार की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 50000 पदों को सृजित किया गया है ताकि नियमित नियोजन में नैमित्तिक श्रमिकों का आगे और समाहन किया जा सके।

कोयले पर रायल्टी

[अनुवाद]

1434. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कोयले पर रायल्टी की दरें क्या हैं और इनमें पिछली बार संशोधन कौन-कौन सी तारीख को किया गया था;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में एक ही किस्म के कोयले पर रायल्टी की दरों में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों में दरों में फिर कब संशोधन करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) सभी कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा शामिल हैं, विभिन्न ग्रेड के कोयले पर रायल्टी की दरें 2.50 रु० से 7.00 रु० प्रति टन के बीच है। ये दरें 13-2-1981 से लागू हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन किए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के जांचाधीन है।

जेंटामाइसिन की मांग

1435. **श्री खेमचन्दभाई सोम भाई चावड़ा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जैंटामाइसिन की वर्ष-वार मांग क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जेंटामाइसिन का वर्ष-वार उत्पादन क्या था;

(ग) क्या मांग व पूर्ति के मध्य कमी को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है;

(घ) यदि उसे अनारक्षित करके उसका लाइसेंस मेसर्स आन्ध्र सिथेटिक्स एण्ड एंटिबायोटिक्स लिमिटेड को दे दिया जाये तो क्या संयुक्त क्षेत्र की आन्ध्र सिथेटिक्स एण्ड एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (ए०एस०ए०एल०), देश में जेंटामाइसिन की संपूर्ण मांग को पूरा करने की स्थिति में है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) 1987-88 में 2010 कि०ग्रा० 1988-89 में 2310 कि०ग्रा० और 1989-90 में 2660 कि०ग्रा० जैंटामाइसिन की मांग होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) उपलब्ध ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष		उत्पादन (कि०ग्रा०)
1987-88	—	347
1988-89	—	946
1989-90	—	1527

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). वर्तमान औषध नीति के अनुसार जैंटामाइसिन पूर्णत: सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित है। इस प्रकार मे० आन्ध्रा सिथेटिक्स और एंटिबायोटिक्स जैंटामाइसिन के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिए पात्र नहीं है। तथापि, अनारक्षण के प्रश्न पर औषध नीति की पुनरीक्षा के समय विचार किया जायेगा।

इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया के कर्मचारियों को मानार्थ और रियायती दरों पर टिकटें

1436. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के प्रत्येक कर्मचारी को कितने निःशुल्क पास और कितने रियायती दरों पर टिकट दिये गये हैं;

(ख) इनमें प्रतिवर्ष सरकार की कितनी लागत लगती है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क मानार्थ और रियायती दर की टिकटों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के संबंध में सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा निःशुल्क पासों के उपयोग में कोई खर्चा नहीं हुआ है। सीटो की उपलब्धता के आधार पर ही निःशुल्क/रियायती टिकटों द्वारा यात्रा की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विश्व में सभी मुख्य विमान कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क/रियायती पासों की सुविधा दी जाती है।

विवरण

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स में मंजूर किए गए निःशुल्क/रियायती पासों की संख्या निम्नानुसार है :—

एयर इंडिया

सेवा पूरी करने के बाद					अंतर्राष्ट्रीय दिये गये पास रियायत की दर (प्रतिशत)			
एक वर्ष	एक	100%	एक	60%	एक	10%	—	
दो वर्ष	एक	100%	एक	80%	एक	30%	एक	10%
तीन वर्ष	दो	100%	एक	50%	एक	30%		
चार वर्ष	दो	100%	एक	70%	एक	50%		
पांच वर्ष	दो	100%	एक	90%	एक	70%		
छः वर्ष से आगे	दो	100%	एक	90%	एक	90%		

					भारत के भीतर	
एक वर्ष	एक	100%	तीन	75%		
दो वर्ष	एक	100%	एक	80%	तीन	75%
तीन वर्ष	दो	100%	तीन	75%		
चार वर्ष	दो	100%	तीन	75%		
पांच वर्ष	दो	100%	एक	90%	दो	75%
छः वर्ष से आगे	दो	100%	एक	90%	दो	75%

इंडियन एयरलाइन्स

सेवा पूरी करने के बाद	मूल्य में छूट		
	मुफ्त 100%	90%	75%
5 वर्ष से नीचे	2	—	3
5 वर्ष या अधिक	2	1	2
7 वर्ष या अधिक	2	2	1
10 वर्ष या अधिक	2	3	—
20 वर्ष या अधिक	2	4	—
25 वर्ष या अधिक	2	5	—

तेल का उत्पादन और खपत

[हिन्दी]

1437. **श्री शोपत सिंह मवकासर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है और इस समय इसकी कुल खपत कितनी है; और

(ख) इस समय तेल और गैस की खोज में कितनी भारतीय और कितनी विदेशी कम्पनियां लगी हुई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन 51.94 मिलियन टन की खपत के प्रति 34.09 मिलियन टन था।

(ख) फिलहाल, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० दो राष्ट्रीय तेल कम्पनियां तेल के अन्वेषण में लगी है। इसके अतिरिक्त इस समय तीन विदेशी तेल कंपनिया अर्थात् मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन, मैसर्स अमोको इंडिया पेट्रोलियम और मैसर्स शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवेलपमेंट, तीसरे दौर की बोली के दौरान उनको दिए गए तीन ब्लाकों में तेल के अन्वेषण में लगी हैं।

मुम्बई में रेलवे स्टेशनों पर वाणिज्यिक परिसर

1438. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में रेलवे स्टेशन पर वाणिज्यिक परिसर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इससे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग केवल मुम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है और इसके क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) न्यू बम्बई में मानखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन पर स्टेशन भवनों के ऊपर वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के शहर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए प्रस्ताव का रेलों ने अनुमोदन किया है। शहर एवं औद्योगिक विकास निगम ने योजना के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई की सूचना नहीं दी है।

यात्री सुविधाएं

[अनुवाद]

1439. **श्री पी०एम० सईद** :

श्री प्रतापराव बी० भोसले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 1990 के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1991 के दौरान वर्तमान सुविधाओं में और वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 1990-91 के दौरान पेयजल, प्रसाधन/स्नानघर, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफार्मों पर सायबान, प्लेटफार्मों की व्यवस्था/उनका विस्तार/ऊंचा करना/चौड़ा करना, प्रतीक्षाकक्ष, बुकिंग व्यवस्था, पंखे, जल शीतक, बिजली बत्ती, जलपान स्टाल, विश्रामगृह, प्रतीक्षालय, दूसरे दर्जे के डिब्बों में गद्दीदार सीट, यात्री आरक्षण प्रणाली का संगणकीकरण, यात्री डिब्बों में पेयजल की व्यवस्था आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 72.95 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ). धन की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान इसी तरह के कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

विमान यात्रा के संबंध में चर्चा सह-खुला मंच अधिवेशन

1440. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 1990 को मद्रास में "भारत में विमान यात्रा: समस्याए और समाधान" के संबंध में एक पैनल चर्चा सह-खुला मंच अधिवेशन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विशेष रूप से किन मसलों को उठाया गया तथा क्या टिप्पणियां और सुझाव प्रस्तुत किए गए; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार थे :—

(1) अंतर्देशीय क्षेत्र में विमान क्षमता की कमी ;

(2) विमान में प्रवेश के समय जांच और उड़ान सूचना के लिए इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को सुविधाएं;

(3) खाड़ी संकट और एयर इंडिया पर इसका प्रभाव ;

(4) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुधरी हुई सुविधाएं ;

(ग) 3 दिसम्बर, 1990 से ए-320 विमानों को चरणबद्ध तरीके से अंतर्देशीय क्षेत्र में पुन: सेवा में लगा लिया गया है । इससे अंतर्देशीय क्षेत्र में विमान क्षमता की कमी में राहत मिलेगी । इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के लिए विमान में प्रवेश के समय जांच और उड़ान सूचना की सुविधाओं में निरन्तर सुधार किया जा रहा है । हवाई अड्डों पर अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी निरन्तर उन्नयन किया जा रहा है ।

प्राथमिकता वाउचर जारी करना

[हिन्दी]

1441. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्षेत्रवार रसोई गैस के उन वितरकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के प्राथमिकता वाउचर जारी किये हैं, और इन वाउचरों को जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसी प्रत्येक एजेंसी द्वारा कितने वाउचर जारी किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को नये एल०पी०जी० कनेक्शन देने के लिए प्राथमिकता वाउचर जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाड़ी युद्ध के कारण रेल कंपनियों को घाटा

1442. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के कारण रेलवे और उसकी विभिन्न सम्बद्ध कंपनियों को वित्तीय घाटा होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और इसके परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों को अपने रोजगार से वंचित होना पड़ा है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रम "इरकान" और "राइट्स" जो खाड़ी युद्ध छिड़ने के समय इराक में कार्यरत थे, का प्रशासनिक नियंत्रण इस मंत्रालय के अधीन है। इस समय, युद्ध छिड़ने के कारण हुई हानि या अन्यथा का सही-सही आकलन कर पाना संभव नहीं है।

युद्ध छिड़ने के समय इराक में लगे संयंत्र और उपस्कर तथा अन्य परिसंपतियों का अनुमानित मूल्य इस प्रकार था :—

(क)	(I) इरकान	—	1 करोड़ रुपये
	(II) राइट्स	—	1.3 करोड़ रुपये

इस युद्ध के परिणामस्वरूप इराक में इरकान और राइट्स द्वारा नियोजित किसी भी भारतीय नागरिक को रोजगार से वंचित नहीं किया गया है।

शिमला रेलवे स्टेशन

1443. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिमला रेलवे स्टेशन को एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) शिमला रेलवे स्टेशन, को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का काम 40.91 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत से शुरू किया गया है। योजना में वर्तमान स्टेशन इमारत का विस्तार, पार्सल कार्यालय का पुनर्निर्माण, पर्यटन कार्यालय की व्यवस्था, कोटा पत्थर की फर्श की व्यवस्था करके प्लेटफार्म की मरम्मत, प्रतीक्षालय, विश्रामकक्ष, अल्पाहार गृह में फर्नीचर का बदलाव, टिकट कार्यालय और प्रतीक्षाकक्ष का पुनर्निर्माण, वर्तमान विश्रामकक्ष का विस्तार और प्लेटफार्म सायवान की व्यवस्था करने का काम शामिल है। 11.37 लाख रु० की लागत का काम पहले पूरा हो चुका है और शेष कार्य 1991-92 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पंजाब में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां

[अनुवाद]

1444. **श्री कमल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में प्रत्येक जिले में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस की एजेंसियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या ये राज्य की मांग को पूर्णरूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या भावी योजनाएं बनायी गयी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पंजाब में और अधिक पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेंसियां आवंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक आवंटित किया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (च). डीजल/पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । ये खुदरा बिक्री केन्द्र और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप पंजाब में चालू मांग को पूरा कर रहे हैं । पंजाब के विभिन्न जिलों में योजना किए गए नये खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विवरण भी संलग्न विवरण में दिया गया है । इन्हें विभिन्न चरणों में स्थापित किया जाएगा । तथापि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को स्थापित करने के पूर्व विभिन्न उपायों को ध्यान में रखते हुए यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं होगा कि उन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ।

विवरण

जिला	खुदरा बिक्री केन्द्र		एल०पी०जी० वितरण केन्द्र	
	वर्तमान	योजनागत	वर्तमान	योजनागत
1. जालन्धर	104	2	22	4
2. कपूरथला	34	0	8	1
3. होशियारपुर	44	2	7	0
4. पटियाला	126	2	20	2
5. संगरूर	89	0	8	0
6. रोपड़	30	2	6	1
7. लुधियाना	121	3	22	6
8. भटिण्डा	70	2	11	3
9. फिरोजपुर	88	2	8	4
10. फरीदकोट	104	5	10	3
11. गुरुदासपुर	54	0	12	3
12. अमृतसर	93	0	23	0
13. रूपनगर	4	0	2	1

बालासोर स्टेशन का आधुनिकीकरण

1445. **श्री समरेन्द्र कुन्डू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी यातायात और बालासोर स्टेशन पर अपर्याप्त सुविधाओं के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या इसका आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस स्टेशन पर विद्यमान सुविधाएं यहां सम्हाले जाने वाले यातायात के अनुरूप हैं जो मध्यम है, विगत में जल आपूर्ति की कुछ कठिनाई थी जो नए नलकूप की व्यवस्था करके अब दूर कर दी गई है।

(ख) और (ग). इस स्टेशन का आधुनिकीकरण करने के बारे में उस समय विचार किया जाएगा जब कभी यातायात की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसा करना अपेक्षित समझा जाएगा लेकिन यह धन की उपलब्धता और अन्य स्टेशनों की सापेक्ष जरूरतों पर निर्भर करेगा, बहरहाल, एक अतिरिक्त नलकूप और प्लेटफार्म सायबान की एक अतिरिक्त खाड़ी की व्यवस्था से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

एअर इंडिया को घाटा

1446. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी संकट के कारण मध्य पूर्व और विश्व के अन्य भागों के लिए इस क्षेत्र से होकर जाने वाली एअर इंडिया की नियमित विमान सेवाओं को या तो बंद कर दिया गया था अथवा उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे एअर इंडिया की आय में अनुमानत: कितना घाटा होने की संभावना है; और

(घ) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (घ). खाड़ी युद्ध के कारण खाड़ी देशों को परिचालित की जा रही प्रति सप्ताह 46 उड़ानों को 16 जनवरी, 1991 से बन्द कर दिया गया था। इनमें से आबू-धाबी, मस्कट और दुबई के लिये विमान सेवाएं आंशिक रूप से 22 जनवरी, 1991 से पुन: शुरू कर दी गई थी। 16 जनवरी, 1991 से 28 फरवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान इन उड़ानों के रद्द होने के कारण एयर इंडिया को लगभग 17 करोड़ रुपए की शुद्ध रोकड़ हानि होने का अनुमान है। एयर इंडिया ने स्थिति का सामना करने के लिए मार्ग को युक्तिसंगत बनाने और व्यय में किफायत करने का कार्य हाथ में लिया था। अब जब कि खाड़ी युद्ध समाप्त हो गया है, अत: एयर इंडिया खाड़ी देशों को अपने परिचालन पुन: शुरू करेगा।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की पैराफिन परियोजना

1447. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की पैराफिन का उत्पादन करने संबंधी परियोजना बन्द कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). सरकार ने, एन० पैराफिन के उत्पादन के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की परियोजना पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

पश्चिम रेलवे के अंतर्गत रेल दुर्घटनाएं

1448. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर गुजरात राज्य में जनवरी, 1990 से 10 फरवरी, 1991 तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक पीड़ित को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) जांच-रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च). गाड़ी दुर्घटनाओं और उनसे संबंधित सूचना के आंकड़े रेलवे क्षेत्र-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार।

ईंधन का विकल्प

[हिन्दी]

1449. **श्री मित्रसेन यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अपेक्षित ईंधन मांग को पूरा करने के लिए क्या-क्या वैकल्पिक उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ताकि खाड़ी संकट को देखते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके; और

(ख) तेल संकट पर काबू पाने तथा देश को इस दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक शोध के माध्यम से अब तक पता लगाए गए स्रोतों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). देश की ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए विशेषकर वर्तमान खाड़ी संकट के मद्दे

नजर विभिन्न उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं/मौद्रिक उपायों के अतिरिक्त इनमें निम्न-लिखित शामिल हैं :—

(1) विदेश के वैकल्पिक स्रोतों से संभव सीमा तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात।

(2) विभिन्न उपभोक्ताओं को उपलब्ध उत्पादों का प्रदाय/आपूर्ति का विनियमन।

(3) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा सरकारी वाहनों में पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करना।

(4) पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक कुशलतापूर्वक इस्तेमाल और उसका संरक्षण।

मध्यम और लम्बी अवधि के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपायों की परिकल्पना की गई है :—

(क) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात बिल में हो रही वृद्धि को सीमित करने के लिए कार्य योजना के निर्माण पर नियुक्त अन्तर-मंत्रालयी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में किफायत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सिफारिशें सरकार के विचारार्थ और कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत की हैं।

(ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों यथा कोयला, बायोगैस, बायो मास, सौर ऊर्जा आदि को प्रोत्साहित करना जिसके लिए प्रयास पहले ही चल रहे हैं।

(ग) अन्तर ईंधन प्रतिस्थापना की सम्भावना का पता लगाना, जिसमें परिवहन क्षेत्रों में अल्कोहल (इथनोल/मिथनोल) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी०एन०जी०) और एल०पी०जी० तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है।

(घ) कच्चे तेल और गैस का देशी स्रोतों से अन्वेषण और उत्पादन तेज करना।

(ङ) देश में शोधन क्षमता में वृद्धि करना।

मद्रास में परिक्रमा रेल

[अनुवाद]

1450. **श्री अन्वारासू इरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास शहर में परिक्रमा रेल परियोजना के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है;

(ख) इस परियोजना के लिये अभी तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) रेलों के पास ऐसी कोई अनुमोदित परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में अनुसूचित/जाति अनुसूचित जनजाति के महाप्रबन्धक और उपमहाप्रबन्धक

[हिन्दी]

1451. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग में महाप्रबन्धक और उपमहाप्रबन्धक के कुल कितने पद हैं और इन पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति तैनात हैं;

(ख) विभाग प्रमुख और सर्किल रेलवे प्रबन्धक के कुल कितने पद हैं और इनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से कोई पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पदों को भरे जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). रेलों पर महाप्रबंधक और उनके समकक्ष पदों की कुल संख्या 19 है और इस समय इनमें से एक पद पर अनुसूचित जाति का एक अधिकारी है। शेष सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). नियमानुसार इन पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

चित्रकूटधाम करवी स्टेशन का आधुनिकीकरण

1452. **श्री राम सजीवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अन्तर्गत झांसी डिवीजन के बांदा खंड में चित्रकूटधाम करवी के निकट रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और नवीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसमें एक नये गोदाम, पैदल ऊपरिपुल तथा नये प्लेटफार्म और स्वच्छ और ताजा पेय जल एवं विद्युत सप्लाई जैसी सुविधाएं देने की योजना शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

हाथी आयोग की सिफारिशें

[अनुवाद]

1453. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधि निर्माण और विपणन के सम्बन्ध में हाथी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान गलत नीति को देखते हुए सम्पूर्ण पहलुओं की समीक्षा करके कोई अन्य आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). 1978 की औषध नीति और दिसम्बर, 1986 में घोषित "भारत में भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और वृद्धि के लिए उपाय" भी हाथी समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। अन्य आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) औषधों और भेषजों के मूल्य डीपीसीओ, 1987 में दिये गये मानदण्डों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। कुछ वृत्तियां अपरिहार्य हैं और अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप अवश्य होती हैं।

ढिलवां (कपूरथला) पर रेल पुल

1454. **श्री कृपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला जिले में ढिलवां ग्राम के निकट रेलवे उपरिपुल क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब क्षतिग्रस्त हुआ;

(ग) क्या इस उपरिपुल को फिर से बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो पुनर्निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ होगा;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां, भारी बाढ़ के कारण सितम्बर, 1988 के दौरान पुल क्षतिग्रस्त हुआ था।

(ग) और (घ). जी हां, काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(ङ) काम को शीघ्र पूरा करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) काम शुरू कर दिया गया है और अप्रैल, 1992 तक इसे पूरा कर दिये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

दिल्ली-भुवनेश्वर मार्ग पर सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाना

1455. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच इस मार्ग पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत संयंत्र

1456. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र में विद्युत उत्पादन केन्द्र की लागत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : एन०टी०पी०सी० के प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र में अनुमोदित मानकों के आधार पर उत्पादन की लागत निम्नानुसार है :—

केन्द्र का नाम	क्षमता	लागत प्रति यूनिट
सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना	2000 मेगावाट	48.22 पैसे
कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना	2100 मेगावाट	54.06 पैसे
रामगुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना	2100 मेगावाट	62.32 पैसे
फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना	600 मेगावाट	77.25 पैसे
विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना	1260 मेगावाट	76.36 पैसे
रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना	1000 मेगावाट	93.96 पैसे
अंता गैस आधारित विद्युत परियोजना	413 मेगावाट	101.38 पैसे
औरैया गैस आधारित विद्युत परियोजना	652 मेगावाट	103.42 पैसे

इस लागत में ईंधन कीमत समायोजन शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश के नैनीताल में विमान सेवा

[हिन्दी]

1457. **श्री एम०एस० पाल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में कोई विमान सेवा उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). वायुदूत द्वारा नैनीताल जिले को इस समय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने की कोई गुंजाइश नहीं है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किया गया अनुपूरक करार

[अनुवाद]

1458. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1986 से जून, 1990 की अवधि के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के माइन्स-1 के सी०एम०ई० डिवीजन की वित्तीय खान विस्तार के ओवरहाल करने हेतु कितने अनुपूरक करार किए गए; और

(ख) माइन्स-1 बकेटव्हील एक्सकेवेटर और अन्य मुख्य उपकरणों के ओवरहाल पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) द्वितीय खान विस्तार के उपकरण केवल चालू चरण के अधीन हैं। अत: उनका ओवरहाल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक खान-1 के सी०एम०ई० प्रभाग का सम्बन्ध है, सी०एम०ई० के चयनकृत ओवरहाल के लिए अप्रैल, 1986 से जून, 1990 की अवधि के दौरान 14 संविदा किए गए।

(ख) अप्रैल, 1986 से सितम्बर, 1990 की अवधि में खान-1 के एस०एम०ई० उपकरणों के ओवरहाल के लिए लगभग कुल 11.82 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई।

महाराष्ट्र में रेलवे का विस्तार

1459. **श्री सुबास देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे नेटवर्क का आगामी पांच वर्षों में विस्तार करने की योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने हेतु उसके साथ अक्तूबर, 1990 के अथवा उसके आसपास कोई समझौता किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सहित नई रेलवे लाइनों पर काम शुरू करने का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). विश्व बैंक का एक शिष्टमण्डल नवम्बर, 1990 में यहां आया था लेकिन रेल क्षेत्र में रेलवे के नेटवर्क के विस्तार अथवा रेल विभाग को किसी अन्य परियोजना के लिए किसी प्रकार के ऋण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

आवास समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1460. **श्री सूबेदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने अपने 21 जून, 1971 और 27 सितम्बर, 1983 के पत्रों के माध्यम से जोनल रेलवेज को ऐसे अनुदेश जारी किए हैं जहां पर 50 या इससे अधिक क्वार्टर हैं वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को आवास समिति और आवास सुविधाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए;

(ख) क्या इन अनुदेशों को भारतीय रेलवे के निर्माण प्रतिष्ठानों में भी लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो आवास समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार का पतरातू ताप विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

1461. **प्रो० यदुनाथ पांडेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुछ इकाइयां पिछले कई महीनों से बन्द पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से और क्या सरकार ने पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की सभी दस इकाइयों को चालू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या पतरातू ताप विद्युत संयंत्र के कारण विस्थापित हुए सभी व्यक्तियों का पुनर्वास कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग). पतरातू ताप विद्युत केन्द्र की इस समय बन्द पड़ी यूनिटों का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	यूनिट सं०	क्षमता (मेगा०)	बन्दी की अवधि		बन्द होने के कारण
			से (चालू होने की सम्भावित तिथि)	तक	
1.	4	40	18.07.90	07.03.91	जनरेटर रोटर क्षतिग्रस्त होना एवं पूंजीगत रखरखाव
2.	5	90	01.05.89	30.06.91	एल०पी० रोटर ब्लेड्स का फेल होना एवं पूंजीगत रखरखाव
3.	7	105	17.09.90	30.04.91	जनरेटर स्टेटर क्षतिग्रस्त होना एवं पूंजीगत रखरखाव
4.	8	105	21.02.90	30.06.91	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य तथा पूंजीगत रखरखाव

पतरातू ताप विद्युत केन्द्र की बन्द पड़ी सभी यूनिटों को शीघ्र चालू करने के लिए उठाए कदमों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिकारियों ने पतरातू ताप विद्युत केन्द्र का दौरा किया है तथा बन्द पड़े यूनिटों को शीघ्र चालू करने के लिए विभिन्न आवश्यक उपायों के बारे में विद्युत केन्द्र के इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श भी किया है।

(2) केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसमें उपरोक्त क्रम सं० 1, 3 व 4 पर दर्शाए गए यूनिटों सनेत पतरातू ताप विद्युत केन्द्र के 8 यूनिटों को शामिल किया गया है, वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन है।

(3) विभिन्न उपस्कर तथा अतिरिक्त पुर्जे शीघ्र सप्लाई किये जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भेल के साथ नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं तथा भेल को सौंपे गए कार्यों को समयानुसार कार्यान्वित किए जाने के लिए विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों द्वारा भी भेल के साथ नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं।

(4) अपेक्षित गुणवत्ता वाले तथा पर्याप्त मात्रा में कोयले का तथा विद्युत केन्द्र के कार्मिको को प्रशिक्षण देने आदि का प्रबन्ध करने के लिए भी बिहार राज्य बिजली बोर्ड की सहायता की जाती है।

(घ) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेलगांव हवाई अड्डे का विस्तार

1462. **श्री जी० देवराय नाईक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोइंग विमानों को बेलगांव हवाई अड्डे पर उतरने के लिए वहां की हवाई पट्टी का विस्तार करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो हवाई अड्डे का सुधार करने हेतु भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों और इसके साथ ही ऐसे निवेशों से प्राप्त राजस्व अधिक न होने के कारण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आठवीं योजना अवधि के दौरान हवाई अड्डों में सुधार के लिए कोई बड़ा निवेश करने की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

सम्बलपुर संभाग

1463. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर संभाग के लिये वर्ष 1990-91 के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) क्या सरकार का सम्बलपुर संभाग को एक परिपूर्ण संभाग में परिवर्तित करने के लिये और अधिक धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 123.39 लाख रुपये।

(ख) जी हां।

रेल दुर्घटनाएं

1464. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से आज तक यात्री रेलगाड़ियों की कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने यात्री मारे गये और उनके निकट सम्बन्धियों को मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी और किस दर पर की गयी तथा सभी मामलों में मुआवजे का भुगतान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के आंकड़े इससे पहले के तीन वर्षों के दौरान की इसी अवधि की तुलना में कितने कम या अधिक हैं;

(घ) रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा इनमें से कितनी दुर्घटनाओं की जांच की गयी थी और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) मानवीय त्रुटियों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेवाड़ी-भटिंडा रेल लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

1465. **श्री प्रताप राव जी० भोसले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेवाड़ी और भटिंडा के बीच संकरी सेक्शन है;

(ख) क्या सरकार ने इस सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अब तक इस मामले में कोई प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। यह मीटर लाइन से जुड़ा हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वित्तीय तंगियों और भारी वचनबद्धताओं के कारण।

भरूच, गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का न्यास

[हिन्दी]

1466. **श्री चन्द्रभाई देशमुख** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के भरूच जिले में, जहां तेल और प्राकृतिक गैस पाये गए हैं, लोगों की सुविधा के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का एक न्यास स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यास के माध्यम से लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस वर्ष इस न्यास को और अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) न तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने, न इस सरकार ने ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया है । तथापि गुजरात सरकार ने 1986 में जिलाधीश और कलक्टर की अध्यक्षता में ऐसा एक ट्रस्ट का गठन किया है जिसके शासकीय निकाय में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का एक अधिकारी एक सदस्य होता है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे विज्ञापन

[अनुवाद]

1467. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विज्ञापन समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं तथा ये विज्ञापन ध्वनि तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा न दिए जाकर गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दिए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ये विज्ञापन गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). रेलों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से अपने विज्ञापन देने की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है, लेकिन, रेलें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा यथा-निर्दिष्ट भारत सरकार की विज्ञापन नीति का अनुसरण कर रही हैं और उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार विज्ञापन जारी करती हैं, सरकारी नीतिं को ध्यान में रखते हुये, रेल प्रशासन सामान्यत: विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्धारित दरों पर सीधे ही विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के अनुमोदित प्रकाशनों को विज्ञापन देती हैं। रेल प्रशासन अभिकल्प कार्य हेतु तथा इस कार्य के लिए अपेक्षित विज्ञापनों का कला सम्बन्धी कार्य करने और इन्हें विभिन्न प्रकाशनों को देने के लिये भी विनिर्दिष्ट शर्तों पर विज्ञापन एजेंसियों का पैनल बनाने के लिये भी प्राधिकृत हैं । इन मामलों में भी विज्ञापन सामान्यत: विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्धारित दरों पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के अनुमोदित प्रकाशनों को दिए जाते हैं ।

दिल्ली से विशाखापत्तनम् के लिए विमान सेवा

1468. **डा० विश्वनाथम्** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशाखापत्तन को दिल्ली से जोड़ने के लिये रायपुर अथवा भुवनेश्वर से होकर एक दैनिक सीधी उड़ान आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली और किसी अन्य स्टेशन के बीच सीधी विमान सेवा को उपलब्धता, ऐसे हवाई मार्गों पर अन्य सम्पर्कों की तुलना में यातायात की सम्भावना तथा ऐसे हवाई सम्पर्कों को कायम रखने के लिये विमानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । इस समय दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने की पेट्रो-रसायन फैक्टरी

1469. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने की सहायक एकक के रूप में कोई नयी पेट्रो-रसायन फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). 18.46 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत पर कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड से प्राप्त फीड स्टॉक का उपयोग करके 5000 टन प्रति वर्ष पाली-ब्यूटेनों का उत्पादन करने के लिये एक परियोजना फिलहाल क्रियान्वयनाधीन है।

धौली एक्सप्रेस को ब्रहमपुर तक चलाने का प्रस्ताव

1470. **श्री ए०एन० सिंह देव**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा जाने के लिए दक्षिण उड़ीसा के यात्रियों को स्थान मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या धौली एक्सप्रेस को ब्रहमपुर तक चलाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दक्षिण उड़ीसा में रहने वाले यात्रियों को हावड़ा जाने के लिए कई गाड़ियां उपलब्ध हैं, कुछ स्टेशनों पर कभी-कभी यात्री प्रतीक्षा सूची में रह भी जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जांच की गई है, लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

कालका-परवानू (हि०प्र०) और जगाधरी-पोन्टासाहिब के बीच रेल लाइन

[हिन्दी]

1471. **प्रो० प्रेम कुमार धुमाल** :

श्री के०डी० सुल्तानपुरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कालका और परवानू के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर लिए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जगाधरी से पोंटासाहिब तक रेल लाइन बिछाने की भी कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वित्तीय तंगी, लाइन की अलाभप्रदता और चालू परियोजनाओं के लिए भारी वचन-बद्धताओं के कारण।

गोवा एक्सप्रेस में पेंट्री-कार की व्यवस्था न होना

[अनुवाद]

1472. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेंट्री-कार की व्यवस्था न होने के कारण गोवा एक्सप्रेस के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) गोवा एक्सप्रेस में पेन्ट्री कार सेवा शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।

उत्तर प्रदेश में चूल्हे का सुधरा रूप

1473. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और जिला मथुरा के लिए सुधरे चूल्हे और गोबर गैस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य है और 1991-92 के लिए क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) क्या गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश, खासकर मथुरा जिले में चूल्हे और गोबर गैस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 2,75,000 उन्नत चूल्हों और 15,000 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। मथुरा जिले के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य प्राधिकारियों द्वारा 2,915 उन्नत चूल्हे और 100 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी हां। अपेक्षाकृत अधिक जन-जागृति इन दो कार्यक्रमों का एक अविभाज्य अंग है।

उत्तर प्रदेश में बायो गैस संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

1474. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी जिलों में बायोगैस के विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत कितने संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) वर्ष 1991-92 की योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर तथा झांसी जिलों में अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान 4.2 लाख तथा 3.78 लाख रुपये की अनुमानित लागत से क्रमशः 60 तथा 54 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं।

(ग) 64 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से 1.47 लाख बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लक्ष्य को लेकर बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना को 1991-92 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

भ्रष्टाचार मामले में शामिल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारी

[अनुवाद]

1475. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या ऊर्जा मंत्री भ्रष्टाचार मामले में शामिल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारी के बारे में 4.9.1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सम्बन्धित दो अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाहियां पूरी हो गई हैं तथा माडर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थगित कर दिए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई दण्डात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और माडर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ व्यापारिक संबंध कौन-सी तारीख से स्थगित किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). मेजर पेनलटी प्रोसीडिंग्स अभी पूरी नहीं हुई हैं। जनवरी, 1990 से मैसर्स माडर्न इंसुलेटर्स के साथ व्यापारिक संबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दिये गये हैं।

उदयपुर से सूरत, मुम्बई और पुणे को जाने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा

[हिन्दी]

1476. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर से वाया अहमदाबाद, सूरत, मुम्बई और पुणे जाने वाली रेलगाड़ियों में व्यापारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यात्रियों को उपलब्ध आरक्षण कोटा पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) आरक्षण कोटा कुल मिलाकर पर्याप्त है।

(ख) बम्बई की ओर जाने वाली 9012 अहमदाबाद-बम्बई गुजरात एक्सप्रेस एवं 9006 ओखा-बम्बई सौराष्ट्र मेल, प्रत्येक द्वारा दूसरे दर्जे की 10 सीटों/शायिकाओं तथा पुणे के रास्ते 2603 राजकोट-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस द्वारा दूसरे दर्जे की 5 शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है।

(ग) और (घ). इन गाड़ियों द्वारा स्थान की सीमित उपलब्धता एवं मौजूदा कोटे वाले स्टेशनों पर कोटे के पूर्ण उपयोग के कारण इन कोटों को बढ़ाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

उदयपुर हवाई अड्डे का विकास

1477. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उदयपुर हवाई अड्डे के विकास पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितना व्यय किया गया ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उदयपुर हवाई अड्डे पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये)
1988-89	60.20
1989-90	20.70
1990-91	29.68

उदयपुर में यात्रियों द्वारा टिकटों की खरीद

1478. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर में उन यात्रियों का माह-वार ब्योरा क्या है जो जनवरी, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान टिकट खरीदने के बावजूद सीटें उपलब्ध न होने के कारण विमान में यात्रा नहीं कर सके;

(ख) क्या दिल्ली और मुम्बई से उययपुर जाने वाले अथवा उदयपुर से दिल्ली और मुम्बई जाने वाले यात्रियों को पुष्टिजन्य टिकटें नहीं दी जाती हैं;

(ग) उदयपुर से आने-जाने वाले यात्रियों से जनवरी, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान कुल कितनी आय हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उदयपुर में यात्रियों की मांग को देखते हुए उदयपुर को कुछ अतिरिक्त उड़ानों, विशेषकर मद्रास और बंगलौर से जोड़ने का है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जनवरी, 1990 से जनवरी, 1991 तक उदयपुर में इण्डियन एयरलाइन्स से टिकट खरीदने वाले यात्रियों की संख्या 18992 है। वायुदूत के मामले में यह संख्या 941 है। वायुदूत ने उदयपुर के लिए अपने प्रचालन दिसम्बर, 1990 में ही शुरू किए थे। दोनों ही एयरलाइनें ऐसे यात्रियों की प्रतीक्षा सूचियों का रिकार्ड नहीं रखती जिन्हें पुष्टिकृत सीटें उपलब्ध नहीं हो पाती।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जनवरी, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान उदयपुर में विमान से उतरने और विमान में सवार होने वाले यात्रियों से इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अर्जित कुल आय लगभग 1085.58 लाख रुपये है। इस संबंध में दिसम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान वायुदूत द्वारा अर्जित आय 12.80 लाख रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

उदयपुर कमलीघाट रेल लाइन पर प्लेटफार्म

1479. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर-कमलीघाट रेल लाइन पर प्लेटफार्मों का निर्माण कब किया गया था और बाद में इन प्लेटफार्मों का नवीकरण कब किया गया था तथा गत तीन वर्षों में इन पर कुल कितनी धन-राशि व्यय की गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि देवगढ़ स्टेशन पर प्लेटफार्म बहुत नीचा है जिससे गाड़ियों में चढ़ने व उतरने में बड़ी कठिनाई होती है और यदि हां, तो इस कठिनाई को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) उदयपुर-कमलीघाट खंड के स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का निर्माण इह लाइन को चालू करते ससय 1936 और इससे पूर्व की अवधि के दौरान किया गया था। चूंकि प्लेटफार्म अच्छी हालत में हैं इसलिए विगत में नवीनीकरण का कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

(ख) देवगढ़ स्टेशन पर पटरी सतह का प्लेटफार्म है और चूंकि इस स्टेशन पर कम संख्या में यात्री आते-जाते हैं इसलिए इसे पर्याप्त समझा जाता है। बहरहाल, विगत में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की इकाइयों में चेतावनी सिस्टम लगाना

[अनुवाद]

1480. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 14 नवम्बर, 1990 के टाइम्स आफ इंडिया (बम्बई संस्करण) में "आई०पी०सी०एल० टु इन्सटोल वार्निंग सिस्टम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड से इसके संयंत्र के पास के गांव वालों को दुर्घटना की सूचना से सचेत करने के लिए एक चेतावनी सिस्टम लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चेतावनी सिस्टम लगाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 5 नवम्बर, 1990 को नागोथाने संयंत्र में हुए विस्फोट को देखते हुए सरकार इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन से एक प्रदूषण संबंधी नवीन आकलन कराने का निदेश देने पर विचार करेगी;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय इंजीनियरी दल की नियुक्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दल की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). अपने आसपास में लोगों को चेतावनी देने के लिए आई०पी०सी०एल० एक पद्धति की योजना बना रहा है और इस प्रयोजनार्थ समयबद्ध तरीके से लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे ।

(ग) से (ङ). दुर्घटना के कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी किसी घटना से बचने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने डा० आर०ए० मशेलकर, निदेशक राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार जांच समिति गठित की है । इस मामले में और आगे की जाने वाली कार्रवाई उनकी सिफारिशों पर आधारित होगी ।

इन्द्रायणी और दक्कन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के किराये में भारी परिवर्तन

1481. **श्री राम नाईक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1990 के बम्बई से प्रकाशित "लोकसत्ता" में "आर्डर्स आफ कन्ज्यूमर्स कमीशन फ्लाउटेड बाई सेन्ट्रल रेलवे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या इन्द्रायणी और दक्कन एक्सप्रेस की वातानुकूलित चेयर कार डिब्बों के लिए प्रथम श्रेणी रेल किराये के वसूल किये जाने से तत्सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति को ठीक करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

मुम्बई में रक्त दान शिविर

1482. **श्री राम नाईक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 24 नवम्बर, 1990 के दैनिक "मुम्बई सकल" में "वैस्टर्न रेलवे एड-मिनिस्ट्रेटर ओपोजेज ब्लड डोनेशन ड्राइव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे प्रशासन ने पश्चिम रेलवे की कार्यशाला के परिसरों में रक्त दान शिविर आयोजित करने का विरोध किया था;

(ग) क्या ऐसा ही एक शिविर चर्च गेट रेलवे स्टेशन में लगाया गया था; और

(घ) रेलवे प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (घ). जी हां। बम्बई सेन्ट्रल में ई०एम०यू० कार शेड के परिसरों में रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति देने के लिए पश्चिम रेलवे स्थानीय लोकाधिकार समिति की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था । लेकिन अनुरोध व्यावहारिक न पाये जाने के कारण, इसकी अनुमति नहीं दी गयी थी। रेलें अपेक्षित होने पर स्वयं

ही रेलवेज यूनियन जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों के सहयोग से रक्तदान अभियान आयोजित करती हैं।

हैदराबाद और बेगमपेट के बीच दोहरी रेल-लाइन

1483. **श्री बे. चोक्का राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद (नामपल्ली) और बेगमपेट स्टेशनों के बीच दोहरी लाइन बिछाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और इसके अन्तर्गत आने वाले मार्ग की लम्बाई कितनी है और अब तक इस पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या यह कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग). खैरताबाद-बेगमपेट (1.98 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया और इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। खैरताबाद प्रधान डाकघर के पास निरंकारी पुल के लगभग 50 मीटर के टुकड़े को छोड़कर हैदराबाद-खैरताबाद (1.52 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यातायात के लिए परिवर्तित मार्ग का काम पूरा कर दिए जाने तथा निरंकारी पुल को तोड़ दिए जाने के बाद इस टुकड़े पर दोहरीकरण का काम शुरू किया जा सकता है।

इसकी अनुमानित लागत 3.05 करोड़ रुपये है, इस भाग की कुल दूरी 3.5 कि०मी० है और अब तक इस पर 2.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

पलवल से रोहतक तक रेल लाइन

1484. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पलवल से रोहतक तक बरास्ता सोहना, रेवाड़ी, इत्यादि एक नया रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को घन उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां। खुर्जा-पलवल-सोहना-रेवाड़ी रोहतक के बीच नयी "दिल्ली" परिहार लाइन (बड़ी लाइन) के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) इस पूरी लाइन का विवरण इस प्रकार है :

लम्बाई : 210 कि०मी०

लागत : 385 करोड़ रुपए।

(ग) और (घ). आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आठवीं योजना के दौरान इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है ।

रेलवे स्टाफ क्वार्टर

1485. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टाफ क्वाटरों हेतु वर्ष 1990-91 के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 में रेलवे स्टाफ क्वार्टरों हेतु धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दक्षिण रेलवे की पालघाट डिवीजन द्वारा धनराशि का कितना प्रतिशत खर्च किया गया और इस डिवीजन में 1990-91 के दौरान कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए "कर्मचारी क्वार्टर" योजना शीर्ष के अन्तर्गत कुल 3823.24 लाख रुपए आबंटित किये गए हैं ।

(ख) 1990-91 के दौरान लगभग 5000 क्वार्टरों के निर्माण किये जाने की संभावना है ।

(ग) 1990-91 के दौरान 3823.24 लाख रुपये की पूर्ण आबंटित राशि का उपयोग होने की संभावना है ।

(घ) और (ङ). जी नहीं, संसाधनों की तंगी के कारण वर्ष 1991-92 के लिए "कर्मचारी क्वार्टर" योजना शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित आबंटन 3501.31 लाख रुपए तक सीमित रखा गया है ।

(च) पालक्काट मण्डल में 1990-91 के दौरान "कर्मचारी क्वार्टर" योजना शीर्ष के अन्तर्गत किये गए कुल आबंटन का लगभग 1.9% कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण पर खर्च होने की संभावना है और वर्ष के दौरान टाइप-II के 21 यूनिटों का निर्माण किया गया है ।

पालघाट डिवीजन में रेल लाइनों को दोहरा बनाया जाना

1486. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के पालघाट और त्रिवेन्द्रम डिवीजनों में कुछ रेल लाइनों को दोहरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). स्थिति इस प्रकार है :

(i) **पालघाट मंडल**

दक्षिण रेलवे के शोरूवणूर-मंगलोर खंड पर दोहरीकरण की आवश्यकता/व्यावहारिकता

की जांच करने के लिए 1990-91 के दौरान एक प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को स्वीकृति दी गयी है।

(ii) **तिरुवनन्तपुरम मंडल**

अल्लेपी के रास्ते एर्णाकुलम-कायनकुलम खंड पर एक वैकल्पिक बड़ी लाइन का प्रस्ताव है। पूर्ण हो जाने के बाद इससे एर्णाकुलम-कायनकुलम के बीच दो इकहरी लाइनों की व्यवस्था हो जाएगी, एक कोट्टायम के रास्ते जो कि वर्तमान लाइन है तथा दूसरी अल्लेपी के रास्ते। कायनकुलम-कोल्लम के दोहरीकरण के कार्य को 1989-90 के बजट में अनुमोदित किया गया था तथा कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम के दोहरीकरण को 1990-91 के बजट में अनुमोदित किया गया है।

केरल में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1487. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट, तेल्लिचेरी या कन्नानोर और बडगरा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने/इन स्टेशनों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और यातायात की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो। इस संबंध में, कालीकट, तेलीचेरी और कण्णोर में निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं—

	(लागत लाख रुपयों में)
कालीकट-प्लेटफार्म के तल को ऊंचा करना	6.35
तेल्लीचेरी—स्टेशन भवन में सुधार करना	8.48
तेल्लीचेरी—द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था	2.32
कण्णोर—प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था करना	6.62

बडगरा में मौजूदा सुविधाएं यहां होने वाले यातायात के अनुरूप हैं। जब कभी इस स्टेशन पर यातायात में वृद्धि के कारण अपेक्षित होगा तो अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो और अन्य स्टेशनों की तुलना में इस स्टेशन पर ऐसा करना आवश्यक हो।

त्रिचूर-गुरवायूर रेल लाइन

1488. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचूर में गुरवायूर रेल लाइन बिछाने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कार्य निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम से पीछे चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 31.1.1991 को 43 प्रतिशत।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले का आयात

[हिन्दी]

1489. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के बिजली बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार से कोयले का आयात करने की स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा में कोयले का आयात किए जाने की संभावना है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख). जी, हां । तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, तमिलनाडु बिजली बोर्डों के विद्युत संयंत्रों पर कोयले का स्टाक किए जाने के लिए एक बार में नि:शुल्क 5 लाख टन कोयले का आयात किए जाने के लिए संपर्क किया था। कोयला विभाग, रेलवे, भू-तल परिवहन मंत्रालय तथा अन्य अभिकरणों के समन्वित प्रयासों के जरिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड के विद्युत संयंत्रों को कोयले का प्रेषण किए जाने में वृद्धि की गई। तमिलनाडु बिजली बोर्डों के विद्युत गृहों पर कोयले की स्टाक की स्थिति में हुए काफी सुधार को तथा भुगतान शेष की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए कोयले के आयात किए जाने संबंधी प्रस्ताव से सहमति नहीं हो सकी ।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड का कैप्रोलेक्टम संयंत्र

1490. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड को कैप्रोलेक्टम संयंत्र की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र के लिए स्विट्जरलैंड, पौलेंड और जर्मनी से सहयोग लेने के प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी और यह कब से कार्य करना आरंभ कर देगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड को कैप्रोलेक्टम के निर्माण के लिए उनकी विद्यमान क्षमता का प्रतिवर्ष 100,000 टन तक विस्तार करने के लिए 1987 में एक आशय पत्र जारी किया गया है। विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों के बाद आमतौर पर ऐसी बड़ी परियोजनाओं को लागू करने में 5 से 7 वर्ष लगते हैं ।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि० राज्य सरकार का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और इसलिए किसी खास परियोजना की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी को कोई राशि प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । फिर भी, पोलैंड और जर्मनी की कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग की स्वीकृति दी गई है ।

गुजरात में बिजली की कमी

[अनुवाद]

1491. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली उत्पादन में सुधार लाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). वर्ष 1990-91 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 271250 मि०यू० नियत किया गया है जोकि 1989-90 के दौरान प्राप्त 245141 मि०यू० वास्तविक उत्पादन से 10.65% वृद्धि का सूचक है । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1990-91 के लिए ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/प्रणाली/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लक्ष्य (मि०यू०)
1	2
बी०बी०एम०बी०	11160
दिल्ली	6440
जम्मू व कश्मीर	3118
हिमाचल प्रदेश	1921
हरियाणा	3510
राजस्थान	7709
पंजाब	10118
उत्तर प्रदेश	41193
गुजरात	19720
महाराष्ट्र	36884
मध्य प्रदेश	31045
आन्ध्र प्रदेश	27524
कर्नाटक	11085
केरल	5205
तमिलनाडु	22805
बिहार	4438

1	2
उड़ीसा	4883
पश्चिम बंगाल	12505
डी०वी०सी०	6700
सिक्किम	48
असम	1540
मेघालय	1094
त्रिपुरा	195
मणिपुर	410
अखिल भारत	271250

गुजरात में रेल प्रणाली

1492. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उस राज्य में रेल प्रणाली में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार को विभिन्न योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन्हें स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च होगी और इसके प्रथम चरण में किन-किन परियोजनाओं का काम शुरू किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

वापसी यात्रा आरक्षण के लिए संदेश भेजना

1493. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या रेल मंत्री 20 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वापसी यात्रा आरक्षण आदि संबंधी संदेशों की प्रतियां संबंधित यात्रियों और संसद सदस्यों को नहीं दी जाती हैं, जो संदेश के प्राप्त न होने की स्थिति में अधिकारियों को उस प्रति को दिखा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संदेशों की प्रतियां संबंधित यात्रियों और संसद सदस्यों को प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग). आरक्षण संबंधी संदेश

पर केवल तभी कार्रवाई की जाती है जब यह सरकारी रूप में प्राप्त हुआ हो। किसी व्यक्ति द्वारा आरक्षण प्राधिकारियों के समक्ष आरक्षण संदेश की प्रति प्रस्तुत करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

नई दिल्ली और पुरी के बीच चलने वाली गाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान लगाना

1494. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से पुरी और पुरी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली प्रत्येक गाड़ी में कम से कम दो वातानुकूलित कुर्सीयान लगाने की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन गाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान कब तक लगाये जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वातानुकूल कुर्सीयानों की कमी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

"नीलाचल एक्सप्रेस" में मूलभूत सुविधाएं

1495. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नीलाचल एक्सप्रेस और नयी दिल्ली-पुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इनकी वापसी ट्रेनों में, विशेषकर दूसरे दर्जे के डिब्बों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) नीलाचल एक्सप्रेस और पुरी एक्सप्रेस गाड़ियों में मौजूदा मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में गैस पर आधारित ऊर्जा-संयंत्र

[हिन्दी]

1496. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जैसलमेर में उपलब्ध गैस से ऊर्जा उत्पन्न करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) जैसलमेर जिले में रामगढ़ के समीप 3 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित किये जाने हेतु स्कीम को 3.94 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1984 में स्वीकृत किया गया था। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने गैस टर्बाइन के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० को आर्डर दिए हैं। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एक संयुक्त साइकिल गैस-आधारित परियोजना को भी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जोकि ऑयल इण्डिया लि० के

तनोत तेल कुओं से गैस की उपलब्धता पर निर्भर है। इस संबंध में के०वि०प्रा० में कोई परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अजमेर, राजस्थान में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

1497. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अजमेर जिले में प्रत्येक एजेन्सी के पास खाना पकाने की गैस के कस्बावार कितने कनेक्शन हैं तथा प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) अजमेर जिले में कार्यरत एजेन्सियों के नाम क्या हैं और वे कितने हैं,

(घ) क्या इन एजेन्सियों में से किसी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). 1 जनवरी, 1991 के अनुसार राजस्थान के अजमेर जिले में वर्तमान 13 डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत नये एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों और एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या निम्न प्रकार से थी :

क्रमांक	वितरक का नाम	स्थल	उपभोक्ताओं की संख्या	(1.1.91 को) प्रतीक्षा सूची में
1.	मै० ए०एस०यू०डब्ल्यू०बी० लि०	अजमेर	22,600	—
2.	मै० श्री चन्दरायन गैस	अजमेर	2,800	8,200
3.	मै० कूक-एन-कूक	अजमेर	2,100	6,400
4.	मै० अवन्तीका एन्ट०	अजमेर	2,850	6,530
5.	मै० उदाय गैस	अजमेर	1,120	—
6.	मै० ख्वाजा गैस एजेंसी	अजमेर	2,039	3,400
7.	मै० मटराच्य गैस	अजमेर	2,207	2,817
8.	मै० ओम गैस	अजमेर	1,503	3,308
9.	मै० भगवती गैस	अजमेर	2,690	2,476
10.	मै० बीवार गैस सर्विस	बीवार	4,010	4,930
11.	मै० गोयल गैस	बीवार	3,482	4,750
12.	मै० एएससी	नसीराबाद	700	1,140
13.	मै० किशनगढ़ गैस	किशनगढ़	3,580	6,253

चूंकि एलपीजी एक कमी वाला उत्पाद है और क्रेताओं के नए नामांकन सीमित हैं इसलिए यह निर्दिष्ट करना कठिन है कि कब तक उन सभी को कनेक्शन दे दिया जायेगा जो प्रतीक्षा सूची में हैं।

(घ) और (ङ). अगस्त, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान अजमेर जिले में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध करीब 71 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी शिकायतों की जांच की गई तथा 4 शिकायतें अब तक साबित की हुई जिनके खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और डीलरशिप समझौते के अनुसार समुचित कार्रवाई की गई है।

राजस्थान में तेल की खोज के नए कार्यक्रम

1498. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इण्डिया लिमिटेड से किशनगढ़ शैल्फ, शाहगढ़ सांकर-बाडमेर और बीकानेर-नागौर जैसे क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य आरम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1956 से और ऑयल इण्डिया लिमिटेड 1986-87 से इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों की खोज कर रहा है।

जयपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलना

1499. **श्री कैलाश मेघवाल** :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से (I) मुम्बई-सूरत-सिरोही-भीलवाड़ा-जयपुर-अहमदाबाद; (II) दिल्ली-झुन्झुनु-बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर; (III) दिल्ली-जयपुर-अजमेर और (IV) उदयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर विमानपत्तनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने और जयपुर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वायुदूत को हुए अत्यधिक घाटे के कारण वह नए स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। देश में हवाई सेवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आठवीं योजना अवधि के दौरान जयपुर,

उदयपुर, और जोधपुर में धावनपथों और टर्मिनल भवनों सहित सुविधाओं में सुधार करने की योजना है। जयपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है।

आपरेशन स्काइज-नीति

[अनुवाद]

1500. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आपरेशन स्काइज" नीति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) किन-किन गैर-सरकारी कम्पनियों को—अनापत्ति प्रमाण-पत्र" दिये गये;

(ग) इन कम्पनियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का वर्तमान तेल संकट को ध्यान में रखते हुए इस योजना को स्थगित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ङ). "ओपन स्काई पोलिसी" के अन्तर्गत भारत के लिए और भारत से बिना किसी प्रतिबंध के गैर-अनुसूचित कार्गो चार्टरों के परिचालन की अनुमति दिए जाने की व्यवस्था है। इसे किसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि इस नीति का उद्देश्य निर्यात कार्गो की तुरन्त निकासी करना है अतः ऐसे कार्गो चार्टरों द्वारा ईंधन भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस योजना को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशाखापत्तनम में नेप्था क्रेकर काम्पलैक्स

1501. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में नेप्था क्रेकर काम्पलैक्स और अन्य "डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्टस" के लिए अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसको किस तारीख तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). विशाखापत्तनम में प्रतिवर्ष 300,000 टन इथाइलीन क्षमता का नेफथा क्रेकर स्थापित करने के लिए 13 अक्टूबर, 1989 को एक आशय पत्र जारी किया गया है। इस क्रेकर के डाउनस्ट्रीम एकक स्थापित करने के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई हो रही है।

आन्ध्र प्रदेश को बिजलीघरों के लिए प्राकृतिक गैस का आवंटन

1502. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 400 मेगावाट के दो और बिजलीघरों के लिए कृष्णा-

गोदावरी तट से प्राकृतिक गैस के आवंटन के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया अथवा लेने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के क्रमश: राजमुन्द्री और काकीनाड़ा में आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली गैस पर आधारित 400 मेगावाट के दो विद्युत संयंत्रों के लिए 1.5 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस का आवंटन किया गया है ।

आठवीं योजना में ज्वारीय और जल विद्युत परियोजनायें

1503. **श्री गोपी नाथ गजपति :**

श्री जे० चोक्का राव :

श्री के०वी० थामस :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना में ज्वारीय और जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान देश में प्रतिष्ठापित जल-विद्युत क्षमता को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। तथापि, आठवीं योजना में ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए योजना के दौरान प्रतिष्ठापित जल विद्युत क्षमता संवर्धन के लक्ष्य अथवा इसके सम्बन्ध में विवरण को इंगित कर पाना सम्भव नहीं है ।

प्लास्टिक उद्योग में संकट

1504. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग संकट के दौर में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक के उत्पाद शुल्क में दी जाने वाली रियायत में वृद्धि करने का है; और

(घ) उद्योग में उपयोग हेतु प्लास्टिक के किन-किन उपयुक्त विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :

(क), (ख) और (घ). खाड़ी संकट से प्लास्टिक उत्पादों की कीमतों और उनकी उपलब्धता (जो स्वयं परम्परागत दुर्लभ सामग्रियों का विकल्प है) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि प्लास्टिक के कच्चे माल की आवश्यकताओं के लगभग 50% का आयात किया जाता है। उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और सीमित सम्भरणों से स्वदेशी बाजार की सप्लाई में प्रभाव पड़ा है।

प्लास्टिक उत्पादों के प्रमुख उपयोगकर्ता संघों और स्वदेशी उत्पादकों के साथ लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि यथासंभव सीमा तक उक्त स्थिति से उत्पन्न दिक्कतों से निबटा जा सके। खाड़ी संकट समाप्त होने पर और अंततोगत्वा जिन नए काम्पलैक्सों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके चालू किए जाने से पेट्रो-रसायनों की अतिरिक्त मात्राएं उपलब्ध होने पर स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ग) ऐसे मामलों में निर्णय गुणावगुण के आधार पर उचित समय पर लिए जाते हैं।

रसोई गैस के नकली सिलेण्डरों की बिक्री

[हिन्दी]

1505. **श्री छेदी पासवान** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रसोई गैस के नकली सिलेण्डरों की बिक्री के संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). जनवरी, 1991 के दौरान दिल्ली पुलिस ने एल०पी०जी० सिलिंडरों के एक अनाधिकृत गोदाम पर छापा मारा था और 54 सिलेंडरों को जब्त किया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। जांच के पश्चात् जब्त किए गए सिलिंडरों को नकली घोषित कर दिया गया।

एअर बस ए-320 सौदे में कथित दलाली की जांच-पड़ताल

1506. **श्री छेदी पासवान** :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सरकार ने एअर बस ए-320 के सौदे में कथित दलाली के मामले की जांच में सहायता मांगी है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में सहायता करने से मना कर दिया है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके कारण क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

के जांच अधिकारी द्वारा दायर किये गए आवेदन पत्र के आधार पर दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने यू०के० और अमेरिका की न्यायिक अदालतों को प्रार्थना पत्र भेजे हैं जिनमें इस जांच के संबंध में उनकी सहायता मांगी गई है ।

(ख) किसी भी देश ने मदद देने से इन्कार नहीं किया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा को डीजल का आवंटन

[अनुवाद]

1507. **श्री कपिल देव शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमतौर से हरियाणा में और विशेषकर गोहाना को डीजल का आवंटन कम मात्रा में करने के कारण क्या हैं; और

(ख) गोहाना और हरियाणा के अन्य भागों में डीजल और पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से एच०एस०डी० की सप्लाई उन्हें पिछले वर्ष की उसी अवधि में की गई सप्लाई के उसी स्तर पर की जाती है । पेट्रोल की सप्लाई पिछले वर्ष की उसी अवधि में की गई सप्लाई पर 4 प्रतिशत की वृद्धि देकर की जा रही है । हरियाणा को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति इसी नीति के मद्देनजर की जाती है ।

हसन-अरसीकेरे रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1508. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हसन-अरसीकेरे मीटरगेट लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम बहुत दिनों से लम्बित है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 1991-92 के दौरान शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर-चित्रदुर्ग रेलवे लाइन को दोहरा किया जाना

1509. **श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा** :

श्री बी० कृष्ण राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर-बंगलौर-तुमकुर-चित्रदुर्ग को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को दोहरा किये जाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) दोहरा किये जाने के इस काम के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) उसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर-गुलबर्ग-शोलापुर रेलवे लाइन को दोहरा करना

1510. **श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बंगलौर और गुलबर्ग के बीच तथा महाराष्ट्र में शोलापुर तक रेलवे लाइन को दोहरा करने का कार्य काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक आरंभ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा इकहरी लाइन खंडों का दोहरीकरण किया जाता है जिनमें उन खंडों को प्राथमिकता दी जाती है जो संतृप्त हो जाते हैं। वाडी-गुन्तकल खण्ड में तीन स्थानों पर कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य पहले से ही प्रगति पर है। परिचालनिक दृष्टिकोण से अपेक्षित होने पर शेष खण्ड के दोहरीकरण का काम शुरू किया जाएगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

बंगलौर-मद्रास मार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ी

1511. **श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मद्रास मार्ग पर एक अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

बंगलौर-जोलारपेट रेल लाइन का विद्युतीकरण

1512. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-जोलारपेट सेक्शन पर विद्युतीकरण का कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) इस परियोजना का कार्य इस समय किस चरण में है; और

(घ) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) दिसम्बर, 1988।

(ख) आरंभ से जनवरी, 91 तक 24.39 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ). विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च, 1992 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आरक्षित डिब्बों में गैर कानूनी रूप से यात्रा करना

1513. **श्री मनोरंजन सुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा-दिल्ली कालका मेल और हावड़ा-नई दिल्ली ए०सी० एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के आरक्षित थ्री टियर कम्पार्टमेंटों में कई यात्री बिना आरक्षण के यात्रा करते हैं जिससे आरक्षण वाले यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) इस प्रकार के कुछ मामले ध्यान में आये हैं।

(ख) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत प्रविष्टि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) राजकीय रेल पुलिस की सहायता से समय-समय पर आकस्मिक जांच और अभियान चलाये जाते हैं और आरक्षित सवारी-डिब्बों में यात्रा करते पाये गये अनधिकृत यात्रियों को पकड़ा जाता है तथा रेल अधिनियम के उपबन्ध के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है। जब कभी आरक्षित सवारी-डिब्बों में यात्रियों की अनधिकृत प्रविष्टि की समस्या अधिक हो जाती है तब राजकीय रेलवे पुलिस से समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि उनकी मदद से ऐसी प्रविष्टि को रोकने में उनकी सहायता ली जा सके।

(ii) ड्यूटी के प्रति लापरवाही के लिये जिम्मेदार पाये गये संवाहकों/टिकट चल परीक्षकों/कोच परिचरों को दण्ड दिया जाता है।

(iii) नये रेल अधिनियम, 1989 में कानूनी प्रावधान को अधिक कड़ा कर दिया गया है जिसके अनुसार पिछले अधिनियम में 20/-रुपये जुर्माने की तुलना में 500/-रुपये तक जुर्माना कर दिया गया है।

रेलवे का विस्तार

1514. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारतीय रेलवे के विस्तार सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी;

(ख) क्या इस समिति ने कोई दीर्घावधि उपाय करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो संभावित पूंजी-निवेश सहित इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग). जी हां। योजना आयोग ने 2000 ई० तक रेल नेटवर्क के विस्तार के लिये एक संदर्श योजना बनाने के वास्ते जुलाई 1987

में एक समिति गठित की थी । इस समिति ने शताब्दी के अन्त तक संभावित यातायात को सम्हालने के लिए रेल नेटवर्क को सक्षम बनाने के लिये कुल 4403 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नई लाइनों के 2902 कि०मी० एवं आमान परिवर्तन के 2306 कि०मी० की पहचान की है । उनके द्वारा सुझाये गये लाइनों/आमान परिवर्तनों को तकनीकी व्यावहारिकता, आवश्यकता एवं वित्तीय दायिताओं की पुष्टि करने के लिये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है ।

वास्तविक लाइनें जिन्हें शुरू किया जाएगा, समय-समय पर आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

कोल इंडिया लि० की राज्य बिजली बोर्डों के पास बकाया राशि

1515. **श्री बसंत साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों से बकाया धनराशि वसूल करने के बारे में स्थिति गत तीन वर्षों के दौरान खराब हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सहायक कम्पनी-वार और वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) राज्य बिजली बोर्डों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिये अब क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : (क) और (ख). विगत चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कोल इंडिया लि० को देय बकाया राशि सम्बन्धी ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 (जनवरी, 91 तक)
ई०को०लि०	111.87	171.39	176.10	212.80
मा०को०को०लि०	217.39	298.10	416.64	430.03
से०को०लि०	269.16	506.76	612.64	506.37
ना०को०लि०	207.47	321.52	272.91	295.25
सा०ई०को०लि०	134.71	165.78	265.61	261.57
वे०को०लि०	92.36	100.81	129.70	138.45
जोड़ को०ई०लि०	1032.96	1564.36	1873.60	1844.47

(ग) उक्त देय बकाया राशि की वसूली किए जाने के सम्बन्ध में किये गये कुछ प्रयास नीचे दिए गए हैं :—

(1) विभिन्न विद्युत बोर्डों/विद्युत गृहों से बकाया राशि की वसूली किये जाने के लिए कोयला कम्पनियों तथा कोल इंडिया लि० द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(2) राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि का भुगतान करने तथा आगामी आपूर्तियों के लिए "रिवालविंग-लेटर-आफ क्रेडिट" जारी किये जाने के लिए तैयार करने/सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

(3) भारत सरकार ने दिनांक 31-5-1990 को विवाद रहित बकाया देय राशि को राज्यों की योजनागत सहायता वर्ष 1990-91 से राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता से समायोजित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 में कोल इंडिया लि० द्वारा 273.36 करोड़ रु० की राशि प्राप्त की गई।

(4) 1-4-1990 से दो महीने के बिल के बराबर बकाया देय राशि वाले राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा क्रमिक रूप से अग्रिम भुगतान किये जाने के लिये एक संयोजन आपूर्ति प्रणाली शुरू की गई है। उक्त व्यवस्था का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में कोयला कम्पनियां विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति में कमी करने अथवा आपूर्ति बन्द करने जैसे कठोर कदम उठा सकती हैं।

(5) दिनांक 1-4-1989 के बाद चालू की गई सभी यूनिटों को कोयले की आपूर्ति अग्रिम भुगतान अथवा लेटर-आफ क्रेडिट के एवज में की जाएगी।

(6) उपर्युक्त बिक्री नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् दिनांक 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत गृहों द्वारा देय बकाया राशि 1844.45 करोड़ रु० के स्तर पर आ गई है जबकि इसकी तुलना में दिनांक 1-4-1990 को यह राशि 1876.60 करोड़ रु० थी।

(घ) बकाया राशि की वसूली तथा विवादग्रस्त देय राशि को कम किए जाने की दृष्टि से कोयला विभाग द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं :—

(1) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बकाया देय राशि को निपटाए जाने का अनुवीक्षण कार्य प्रति सप्ताह केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक एजेंसी द्वारा किया जाए।

(2) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कोयला कम्पनियों को 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। उक्त ब्याज की दर वही है जो कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा दोषी व्यक्तियों से ली जाती है।

(3) राज्य विद्युत बोर्डों तथा कोयला कम्पनियों के मध्य सारे विवादों को मध्यस्थता के लिए एक तीन सदस्यीय समिति को प्रेषित किया जाएगा जिसमें कोयला नियंत्रक तथा कोयला विभाग और विद्युत विभाग का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा। विवाद एक महीने के अन्दर सुलझा दिया जाएगा।

(4) संयुक्त नमूना जांच केवल कोलियरी में ही की जाए तथा इसके परिणाम दोनों पक्षों पर बाध्य होंगे।

(5) दोषी राज्य विद्युत बोर्डों की कोयले की आपूर्ति पर रोक लगाई जा सकती है ।

सेन्टोर होटल को बेचना

1516. **श्री वसंत साठे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टोर ग्रुप के होटलों को बेचने और विदेशों में तैनात एअर इंडिया के कर्मचारियों को वापस बुलाने तथा वहां पर बिक्री एजेंटों को नियुक्त करने जैसे मितव्ययता के अनेक उपाय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और वायुदूत के संचालन की समीक्षा करने के पश्चात् क्या उपाय प्रस्तावित अनुमोदित हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). एयर इंडिया बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भारतीय होटल निगम, किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त होटल श्रृंखला से इक्विटी का सहयोग प्राप्त करें जो भारतीय होटल निगम के विपणन और प्रबन्ध का कार्य अपने हाथ में लेने को इच्छुक हो । यह भारतीय होटल निगम द्वारा उठाई गई अत्यधिक हानि और बाजार में उसके द्वारा प्रभावी ढंग से होड़ न कर पाने के कारण आवश्यक हो गया है । एयर इंडिया पर खाड़ी संकट के कारण प्रतिकूल असर पड़ा है । खाड़ी संकट और पश्चिम की आर्थिक स्थिति में मन्दी के दौर के कारण यात्रियों की संख्या और साथ ही कार्गो में भी कमी आई है । एयर इंडिया ने अपने मार्ग के ढांचे को युक्ति-संगत बनाने तथा व्यय में किफायत करने के लिए कदम उठाये हैं ।

वायुदूत और इंडियन एयरलाइंस ने अपने मार्ग के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, अलाभकारी परिचालनों में कटौती करने और फालतू व्यय से बचने के लिए कदम उठाये हैं ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय पन बिजली निगम की राज्य बिजली बोर्डों के नाम बकाया राशि

1517. **श्री वसंत साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय पन बिजली निगम को राज्य बिजली बोर्डों से होने वाली वसूली में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). गत दो वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की वसूली की राशि में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है । तथापि गत दो वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की वसूली की राशि की स्थिति में गिरावट आई है । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय बकाया राशियों का गत तीन वर्ष का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय बकाया राशियों का सोपानबद्ध रूप से भुगतान करें। वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय बकाया राशियों की वसूली के लिए केन्द्रीय सरकार ने भी केन्द्रीय योजना सहायता के विनियोग से राशि वसूल करना आरंभ कर दिया है।

विवरण

एन०टीपी०सी० की बकाया राशियों की वसूली

वित्तीय वर्ष 1988-89 से राज्य बिजली बोर्डवार स्थिति

(लाख रुपये)

एस०टी०पी०एस०/ राज्य बिजली बोर्ड	1988-89				
	बिल राशि	वसूली			बकाया
		प्रत्यक्ष	केन्द्रीय विनियोजन	जोड़	
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	22638	14039	8750	22789	9847
राजस्थान	11576	10822		10822	4926
दिल्ली	7712	8271		8271	4175
पंजाब	5943	4915		4915	644
हरियाणा	5691	2450	2463	4913	3561
हिमाचल प्रदेश	817	786		786	615
जम्मू एवं कश्मीर	358	77		77	279
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	611	425		425	186
डी०वी०सी०	85	85		85	0
मध्य प्रदेश	17087	13442		13442	4865
महाराष्ट्र	9096	8525		825	2069
गुजरात	7458	6846		6846	1140
गोवा	987	1001		1001	0
दादर एवं नगर हवेली	0	0		0	0
दमन एवं दीव	0	0		0	0
आन्ध्र प्रदेश	7455	7060	1979	9039	497
कर्नाटक	6073	6781		6781	1383
तमिलनाडु	6801	548	2440	2988	3975

(लाख रुपये)

1989-90					1990-91 (जनवरी, 91 तक)				
बिल राशि	वसूली			बकाया	बिल राशि	वसूली			बकाया
	प्रत्यक्ष	केन्द्रीय विनियोजन	जोड़			प्रत्यक्ष	केन्द्रीय विनियोजन	जोड़	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42221	22297	22297	29772		42874	25317	8425	33742	38904
17681	11662	11662	10865		17915	11062	3300	14362	14418
12792	12800	12800	4277		11455	12170	—	12170	3562
6117	6668	6668	93		6466	5990	48	6038	521
10440	6940	6940	7061		9217	5966	1734	7700	8578
654	710	710	559		500	189	160	349	710
1197	601	601	875		2549	558	200	758	2666
1191	1323	1323	54		765	713	—	713	106
0	0	0	0		0	0	0	0	0
24729	18822	18822	10772		27270	21040	3558	24598	13444
17691	16611	16611	3149		17955	13843	1187	14950	6155
11472	9950	9950	2662		13476	8292	1010	9302	6836
1334	1334	1334	0		1259	1249	10	1259	0
355	355	355	0		592	592	0	592	0
174	174	174	0		252	252	0	252	0
13061	13064	13064	494		7312	6553	124	6677	1129
9294	8009	8009	2588		9960	7596	725	8321	4227
14018	13653	13653	4340		16318	12894	931	13825	6833

विवरण

एन०टी०पी०सी० की बकाया राशियों की वसूली

वित्तीय वर्ष 1988-89 से राज्य बिजली बोर्डवार स्थिति

(लाख रुपये)

एस०टी०पी०एस०/ राज्य बिजली बोर्ड	1988-89				
	बिल राशि	वसूली			बकाया
		प्रत्यक्ष	केन्द्रीय विनियोजन	जोड़	
1	2	3	4	5	6
केरल	2587	2862		2862	265
गोवा	1111	1111		1111	0
प० बंगाल	2443	1243		1243	1223
बिहार	4128	2052		2052	2965
उड़ीसा	1821	1411		1411	1751
डी०वी०सी०	2796	2799		2799	164
सिक्किम	25	10		10	25
जोड़	125299	97561	15632	113193	44475

(लाख रुपये)

1989-90					1990-91 (जनवरी, 91 तक)				
बिल राशि	वसूली			बकाया	बिल राशि	वसूली			बकाया
	प्रत्यक्ष	केन्द्रीय विनियोजन	जोड़			प्रत्यक्ष	केन्द्रीय विनियोजन	जोड़	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4226	3779		3779	712	4197	2825	183	3008	1901
813	813		813	0	1086	1086	0	1086	0
4244	2251		2251	3216	4385	2271	1021	3292	4309
9989	3273		3273	9601	11740	6540	2544	9084	12257
1617	1602		1602	1766	563	977	415	1392	937
3493	2225		2225	1432	5473	2260	0	2260	4645
64	32		32	57	46	60	20	80	23
208818	158948	0	158948	94345	213825	150295	25515	175810	132160

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का गैर-सरकारीकरण किए जाने का प्रस्ताव

1518. **श्री बसंत साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के आंशिक रूप से गैर-सरकारीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की मंजूर की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र गैस क्रैकर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). आई०पी०सी०एल० ने अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के लिए वित्त प्रबन्ध हेतु विभिन्न विकल्पों की जांच की है और सुझाव दिये हैं और अन्य संभावनाओं में उन्होंने सार्वजनिक अंशदान के लिए शेयर जारी करने का सुझाव दिया है।

(ग) गुजरात राज्य में बड़ौदा और गांधार में एडवान्स्ड इंजीनियरिंग प्लास्टिक एण्ड कम्पोजिटस के विनिर्माण के लिए 13.1.1991 को आई०पी०सी०एल० को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

(घ) 5 नवम्बर, 1990 को नागोथाणे काम्पलैक्स के गैस क्रैकर प्लान्ट की आउटसाइड बैटरी लिमिट (ओ०एस०बी०एल०) यूनिट में विस्फोट के बाद आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र बन्द कर दिया गया है। संयंत्र को जल्दी से जल्दी दोबारा चालू करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

तेल का उत्पादन

1519. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी 1991 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "बेटर मैनेजमेंट नीडेड ऐट ओ०एन०जी०सी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह समाचार रिपोर्ट, तकनीकी रूप से भली भांति सूचित रिपोर्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी भी तेल क्षेत्र में उसके पूरे जीवन-काल के लिए तेल का स्थायी वार्षिक उत्पादन नहीं हो सकता। किसी तेल क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया, विशेषकर बम्बई हाई जैसे विशाल और जटिल तेल क्षेत्र की एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके अधीन उत्पादन में वृद्धि करने के

लिए अतिरिक्त उत्पादन-सामग्री का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही, जब तक अन्वेषी ड्रिलिंग स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह भी नहीं कहा जा सकता कि तलछटी बेसिन में तेल नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जब तक अन्वेषी ड्रिलिंग नहीं की जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इन क्षेत्रों में तेल नहीं है। इसके अतिरिक्त तेल, एवं गैस का पता लगाने की प्रक्रिया वही है और यह नहीं कहा जा सकता कि त्रिपुरा में ड्रिलिंग का काम केवल तेल प्राप्त करने के लिए ही किया गया था। तथापि, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य के कार्यक्रम की सरकार द्वारा तथा स्वयं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है, अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं।

अलेप्पी-कायमकुलम रेलवे लाइन

1520. **श्री एस० कृष्ण कुमार :**

प्रो० के०वी० थामस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तटवर्ती रेलवे के अल्लेप्पी-कायमकुलम सेक्शन का निर्माण कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके कब तक पूरा होने की आशा है और उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग), अलेप्पी और कायनकुलम के बीच 3907.08 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 43 कि०मी० लम्बी नई बड़ी लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के 1991-92 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

पालघाट-एर्णाकुलम और एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम सेक्शनों का विद्युतीकरण

1521. **श्री एस० कृष्ण कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट-एर्णाकुलम और एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम सेक्शनों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में वायुदूत-सेवा

1522. **श्री एस० कृष्ण कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितने शहरों में वायुदूत सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या राज्य में कुछ और क्षेत्रों में इस सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) वायुदूत कोचीन और त्रिवेन्द्रम को अनुसूचित उड़ानों का परिचालन कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कायमकुलम ताप बिजली संयंत्र

1523. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कायमकुलम ताप बिजली संयंत्र परियोजना का निर्माण-कार्य इस समय किस चरण में है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग). कायमकुलम सु०ता० वि० परियोजना (चरण-1) (2×210 मेगावाट) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट के०वि०प्रा० द्वारा जनवरी, 1989 में निवेश संबंधी अनुमोदन हेतु तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकित की गई थी। परियोजना के लिए औपचारिक पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1990 में स्वीकृति दिए जाने के बाद परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही पहले ही प्रारंभ कर दी गई है।

परियोजना के निवेश संबंधी अनुमोदन लंबित होने पर रा०ता०वि०नि० प्रत्यायोजित शक्तियों, के अनुसार, नयी परियोजना के लिए 5 करोड़ रु० तक अग्रिम व्यय वहन कर सकता है। इसलिए निवेश संबंधी अनुमोदन के बाद ही कार्य पूर्ण वेग से प्रारंभ हो सकेगा।

(घ) परियोजना की पहली 210 मेगावाट यूनिट के सप्लाई कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 48 महीने के भीतर एवं दूसरी यूनिट के उसके 6 माह बाद चालू होने की आशा है।

अजमेर में हवाई अड्डा

[हिन्दी]

1524. **प्रो० रासासिंह रावत** :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजमेर में एक हवाई अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके सर्वेक्षण, अनुमानित लागत और स्थल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अजमेर में हवाई अड्डा कब तक बन जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल पम्प और खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

1525. **श्री राजबीर सिंह :**

श्री एम०एस० पाल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कहां-कहां पर कितने पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित किए जाने के लिए मंजूर हुए हैं और इनमें से कितने पम्पों ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ पेट्रोल/डीजल पम्पों का बेरोजगार युवकों के लिए आरक्षित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए अब तक 465 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं जिसमें से 316 चालू कर दिये गये हैं । जिलावार उन स्थानों के संबंध में ब्यौरे, अर्थात् किन जगहों के लिए पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं और किन स्थानों पर उन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है, एकत्र करने में निहित प्रयास वांछित उद्देश्य प्राप्ति के अनुरूप नहीं होंगे ।

(ख) और (ग). मौजूदा नीति के अनुसार बेरोजगार युवकों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है । तथापि, यदि अन्य बातें समान हों तो बेरोजगार स्नातकों/बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों को, खुली श्रेणी के अन्तर्गत सहयोग समितियों के बाद वरीयता दी जाती है ।

उत्तर प्रदेश के फरीदपुर में वायुदूत सेवाओं के लिए हवाई पट्टी

1526. **श्री राजबीर सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के फरीदपुर में वायुदूत सेवाओं के लिए एक हवाई पट्टी बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की कमी

1527. **श्री राज बीर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा इस कमी को कब तक पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). थोक एल०पी०जी० की उपलब्धता में अड़चनों, परिवहन समस्याओं और छिटपुट कानून और व्यवस्था की समस्याओं को वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से एल०पी०जी० के रिफिलों की आपूर्ति में अस्थायी कमी होने की सूचना प्राप्त हुई थी । देशी उत्पादन तथा आयात में वृद्धि करके, बाटलिंग को बढ़ाकर, आवागमन में तीव्रता लाकर और रिफिलों के प्रदाय में तेजी लाकर एल०पी०जी० की उपलब्धता को त्वरित करने की कार्यवाही की गई है । इन उपायों से बहुत हद तक स्थिति में सुधार हुआ है।

बंगलौर आने-जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

1528. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर आने जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें गत तीन महीनों से समय-सारणी के अनुसार नहीं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान देरी से चलने वाली उड़ानों का ब्यौरा क्या है और समय-सारणी का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइन्स के अनुसार नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान बंगलौर से और बंगलौर के लिए 2419 उड़ानें की गईं। इनमें से 78.54% उड़ानें समय पर परिचालित की गई थी। 496 उड़ानों में विलम्ब और शेष 23 उड़ानों को रद्द करने का मुख्य कारण अन्य स्टेशनों से उन्हीं विमानों के परिचालन में विलम्ब होने तथा उसके परिणामस्वरूप बंगलौर में उनके आगमन में विलम्ब होना था।

समय पर उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

— सर्विसिंग में विलम्ब की संभावना के मामले में बेस स्टेशन के मुख्य इंजीनियर प्रबन्धक संबंधित एग्जीक्यूटिव के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए स्थिति पर विचार-विमर्श करते हैं।

— महत्वपूर्ण विलम्बों के कारणों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय निदेशक परिचालन से संबंधी विभागीय अध्यक्षों के साथ दैनिक बैठकें करते हैं।

— यह सुनिश्चित करने के लिये कि विमानों और कर्मीदल पर अधिक दबाव न पड़े, समय-सारणी में पर्याप्त अंतराल रखा जाता है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में वायुदूत सेवा

1529. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उन स्थानों के औद्योगिक महत्व की तथा यात्री सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए वायुदूत सेवाएं शुरू करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : विमान क्षमता की कमी, संसाधनों की कमी और परिचालनों की अक्षमता के कारण वायुदूत मध्यप्रदेश में अपनी सेवाओं को पुन: प्रारम्भ करने में असमर्थ है। इन्हीं कारणों से वायुदूत का राजस्थान में नये स्टेशनों को हवाई सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भटनी-वाराणसी मार्ग पर रेलगाड़ियों का चलना

1530. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटनी-वाराणसी के बीच की रेल-लाइन में गेज परिवर्तन करने के बाद भी यात्री गाड़ियां बहुत धीमी गति से चल रही हैं;

(ख) क्या जनता ने रेलगाड़ियों की गेज-परिवर्तन से पूर्व की गति को पुन: स्थापित करने की मांग की है और इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) आमान परिवर्तन के बाद खंडीय रफ्तार नियमानुसार बढ़ा दी गयी है :—

खंड	मी०ला० पर पहले रफ्तार	ब०ला० पर वर्तमान रफ्तार
भटनी-औड़िहार जं०	75 मि०मी० प्र० घं०	100 कि०मी० प्र०घं०
औड़िहार जं०-वाराणसी	75 कि०मी० प्र० घं०	90 कि०मी० प्र० घं०

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सलेमपुर-बरहाज रेल लाइन को बदलना

1531. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेज परिवर्तन योजना में सलेमपुर-बरहाज रेल लाइन को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सलेमपुर-बरहाज गेज परिवर्तन योजना को कब से आरम्भ करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग). सलेमपुर-बरहाज बाजार मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 5.28 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है। यह कार्य 1991-92 में पूरा कर दिया जायेगा।

गोरखपुर के लिए विमान सेवा

1532. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर के लिए विमान-सेवा रद्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जनहित में इस विमान सेवा को पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). जी, हां। यात्रियों की कम मांग और ईंधन बचाने की आवश्यकता को देखते हुए इण्डियन एयरलाइंस ने 22.1.91 से दिल्ली और गोरखपुर के बीच सेवाएं रोक दी थीं।

(ग) इस समय इस सेवा को शुरू करने की इण्डियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेंटॉर होटलों का विक्रय

[अनुवाद]

1533. **श्री कमल नाथ** :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सेन्टॉर होटल समूह को बेचने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक होटल को प्रारम्भ से कुल कितनी हानि हुई;

(घ) इन होटलों के बन्द होने से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है और उन्हें देय मुआवजे की राशि क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). एअर इंडिया के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय किया है कि भारतीय होटल निगम को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की किसी ऐसी होटल श्रंखला से इक्विटी सहयोग प्राप्त करना चाहिए जो भारतीय होटल निगम के विपणन और प्रबंध को संभालने की इच्छुक हो। भारतीय होटल निगम को हुए अत्यधिक घाटे और मार्केट में होड़ का कारगर ढंग से सामना करने में असमर्थ रहने के कारण यह आवश्यक हो गया है।

(ग) से (ङ). प्रत्येक होटल यूनिट में कर्मचारियों की संख्या और घाटे/लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	कर्मचारियों की संख्या	31.3.90 तक हुआ लाभ/हानि
	1	2
सेन्टार होटल, बम्बई हवाई अड्डा	817	18.66 करोड़ रु० (लाभ)

1		2
सेन्टार होटल, दिल्ली हवाई अड्डा	800	12.79 करोड़ रु० (हानि)
सेन्टार लेक व्यू होटल, श्रीनगर	391	18,61 करोड़ रु० (हानि)
सेन्टॉर जूहु बीच, बम्बई	831	7.9 3करोड़ रु० (हानि)

विचाराधीन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान/वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं होगा ।

औषध मूल्य समकरण लेखे के अन्तर्गत वसूली

1534. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य समकरण लेखे के अन्तर्गत औषध कम्पनियों से कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) अब तक वास्तव में कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे मामलों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). विभिन्न कंपनियों के खिलाफ आज तक निर्धारित राशियां और प्रत्येक से अब तक वसूल की गई राशियां बताने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ग) उच्च न्यायालयों ने उन मामलों में स्थान/अन्तरिम स्थगन आदेश दिए हैं जो उनके समक्ष हैं। तथापि, सरकार द्वारा मामलों का विरोध किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ). बकाया राशियों का हिसाब लगाते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखा गया है ।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	अवधि	निर्धारित अस्थाई राशि	अब तक जमा की गई राशि (रु० लाख में)	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6
	1. सुप्रीम कोर्ट के मामले				
1.	मे० सिनामिड इंडिया लि०	दिस०83 तक	536.91	100.00	436.91
2.	मे० हैक्स्ट इंडिया लि०	दिस०83 तक	2491.05	312.10	7468.70
		जन०84 से	5289.75		
		अगस्त87 तक	———		
			7780.80		
			———		
3.	मे० मेरिण्ड	दिस०83 तक	781.58	—	2288.54
		जन०84 से	1506.96		
		87 तक	———		
			2288.54		
			———		
4.	मे० जान वैथ एण्ड ज्योफ्री मेनर्स	दिस०83 तक	177.67	45.00	161.0
			28.37		
			———		
			206.04		
			———		
5.	मे० फाइजर	दिस०83 तक	87.61	19.90	67.71
6.	मे० एस०जी० फार्मास्युटिकल्स	दिस०83 तक	205.36	—	205.36
7.	मे० तमिलनाडु ढाढ़ा फार्मा०	दिस०83 तक	37.97	—	37.97
8.	मे० फ्रेंको इंडिया एण्ड मे० ग्रिफोन लैन्स०	दिस०83 तक	14.02	0.43	13.59
9.	मे० अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स	दिस०83 तक	11.61	—	11.61
10.	मे० इथनार लि०	दिस०83 तक	10.19	10.19	—
		उप-योग	11179.05	487.62	10691.43

1	2	3	4	5	6
	II. गैर-सुप्रीम कोर्ट मामले				
	(क) रिफेम्पिसिन				
1.	मे० बायोकेम फार्मास्युटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	—	34.28
2.	मे० लायका लैब्स०	4/79 से 3/84	57.57	5.70	51.87
3.	मे० अस्ट्रा आईडीएल	82-83 से 5/85	24.11	2.41	21.70
4.	मे० माइक्रो लैब०	79-80 से 82/83	2.24	—	2.24
5.	मे० थेमिस केमिकल्स लि०	82-83 से 83-84	36.31	—	36.31
6.	मे० अलेम्बिक केम० लेब्स०	81-82 से 83-84	38.73	3.80	34.03
7.	मे० बोम्बे ड्रग हाउस	80-81 से 83-84	1.73	—	1.73
8.	मे० फार्मड प्रा० लि०	79-80 से 83-84	66.01	—	66.01
9.	मे० डलफिल लैब्स०	1979 से 1983	18.11	—	18.11
10.	मे० अल्बर्ट डेविड लि०	11/81 से 9/83	3.91	3.91	कुछ नहीं
11.	मे० फार्मा एण्ड केमिकल इंड०	80-81 से 82-83	87.99	—	87.99
12.	मे० केडिला लैब्स प्रा० लि०	79-80 से 83-84	76.52	7.50	69.02
13.	मे० साराभाई केमिकल्स	82-83 से 83-84	4.14	2.00	2.14
14.	मे० लूपिन लैब्स०	8/80 से 3/84	215.89	21.60	194.29
15.	मे० रेनबैक्सी लैब्स०	4/79 से 6/84	36.23	3.63	32.60
16.	मे० वेलेस फार्मा०	4/82 से 2/84	2.82	0.29	2.53
17.	मे० एथिको ड्रग एण्ड केम० मेग० कं०	5/82 से 3/84	140.98	—	140.98
18.	मे० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०	12/80 से 1/86	2.18	—	2.18
19.	मे० हिन्दुस्तान एंटि०	81-82 से 83-84	36.66	—	36.66
			886.41	50.84	835.57
	(ख) डिपाय रीडामोल				
1.	मे० जर्मन रेमेडीज	4/79 से 7/84	59.95	59.95	कुछ नहीं
	(ग) जेंटामाइसिन				
1.	मे० फुलफोर्ड आई लि०	79-80 से 2/84	194.62	50.00	144.62

1	2	3	4	5	6
2.	मे० बायोकेम फार्मा० लि०	79-80 से 3/84	33.88	—	33.88
3.	मे० लायक लैब्स० लि०	7/79 से 3/84	17.47	1.75	15.72
4.	मे० निकोलस लैब्स०	79-80 से 3/84	53.03	10.00	43.03
			299.00	61.75	237.25
	(घ) सालबुटामोल				
1.	मे० खण्डेलवाल लि०	79-80 से 81/82	0.15	—	0.15
2.	मे० बिडले स्वेयर प्रा० लि०	4/79 से 3/83	142.74	—	142.74
			142.89		142.89
	(ङ) क्लोफेजेमाइन				
1.	मे० एस०जी०फार्मा०	4/79 से 3/84	5.01	—	5.01
	(च) एम्पिसिलिन एण्ड एमोक्सिलिन				
1.	मे० बायोकेम फार्मा० लि०	79-80 से83-84	11.80	—	11.80
	(छ) आक्सीफिनाइल बुटाजोल				
1.	मे० टेबलैस्ट इंडिया लि०	79-80 से 83-84	9.49	—	9.49
	(ज) मेटानिडाजोल				
1.	मे० बूट्स कं० लि०	79-80 से 25.8.87	62.17	47.91	14.26
2.	मे० स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मा० लि०	79-80 से 83-84	7.82	—	7.82
3.	मे० केएसडीपीएल	79-80 से 83-84	5.50	—	5.50
4.	मे० खण्डेलवाल लैब्स०	79-80 से 3/84	1.34	—	1.34
5.	मे० आईडीपीएल	79-80 से 3/84	20.33	—	20.33
			97.16	47.91	49.25
	(झ) सल्फामेथोक्साजोल				
1.	मे० बोरो वेलकम	1979-80 से फरवरी 1984	441.27	—	441.27

1	2	3	4	5	6
(झ)	ट्रिमेथोप्रिम				
1.	मे० जर्मन रेमेडीज	2/82 से 5/86	8.25	8.25	कुछ नहीं
(ञ)	फलसिनोलोन एसिटोनाइड				
1.	मे० लायका लैब्स०	1979-80 से 25.8.87	678.73	—	678.73
III.	उच्च न्यायालय मामलों में वसूल की गई राशि				
1.	मे० साराभाई एम केमिकल्स	उ० नहीं	20 00	20.00	—
2.	मे० ग्लैक्सो	अगस्त, 1987 तक	7178.18	819.00	6359.18
(4)	अधिक वसूली के कारण बकाया राशि				
1.	मे० वार्नर हिन्दु० लि० (अब पार्क डेविस)	(इसोकिन)	106.36	55.49	50.87
2.	मे० बोहरिंगर नील लि०	(इयूग्लूकोन)	97.74	—	97.74
3.	मे० आईडीपीएल	(आयातित प्रपुंज औषधें)	336.45	कुछ नहीं	336.45
4.	मे० ए०पी० केमिकल्स	(पारासिटामोल)	25.43	कुछ नहीं	25.43
5.	मे० मालाडी ड्रग्स	(इफैड्रिन)	116.30	कुछ नहीं	116.30
6.	मे० आईडीपीएल	(सल्फाडीमिडाइन)	37.30	कुछ नहीं	37.30
7.	मे० रूपा ट्रेडर्स	(रिफेम्पिसिन)	20.48	कुछ नहीं	20.48
8.	मे० सेंडोज इंडिया लि०	(मल्टिविटामिनस)	74.68	कुछ नहीं	74.68
9.	मे० फाइजर इण्डिया लि०	(वही)	122.00	कुछ नहीं	122.00
10.	मे० लुपिन लैब्स०	(रिफेम्पिसिन)	3.72	कुछ नहीं	3.72
11.	मे० लुपिन लैब्स०	(इथाम्बुटोल)	17.31	कुछ नहीं	17.31
12.	केरूज	(कॉम्बीफलेम)	710.04	—	710.04
		उप-योग :	1668.01	55.49	1612.52
		कुल योग :	22685.20	1610.81	21074.39

नई बड़ी रेल लाइनें

[हिन्दी]

1535. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का किन स्थानों पर बड़ी रेल लाइनें बिछाने का विचार है;

(ख) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इन कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (ग). सरकार के विचाराधीन नई लाइन परियोजनाओं की सूची 1991-92 के बजट पर रेल मंत्री के भाषण के पैरा 17.7 में दी गयी है, जो अन्य बजट प्रलेखों के साथ 25.2.91 को अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्यों को दिया गया था।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

1536. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी गांवों को बिजली दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मार्च, 1989 के अन्त तक पारंपरिक/गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण किया जा चुका है। तथापि, 248 गैर-संभाव्य गांवों जोकि या तो उजड़ चुके हैं अथवा जलमग्न हैं, का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन

1537. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक गत 12 महीनों में माहवार कितना विद्युत उत्पादन हुआ; और

(ख) विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है और कम विद्युत उत्पादन के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 के दौरान महाराष्ट्र में कुल मिलाकर महीनेवार विद्युत के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :—

महीना	विद्युत उत्पादन मेगावाट आवर में	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1	2	3
जनवरी, 1990	3358	3337
फरवरी, 1990	2736	3018
मार्च, 1990	3234	3327
अप्रैल, 1990	2899	3302

1	2	3
मई, 1990	3101	3161
जून, 1990	2913	2901
जुलाई, 1990	2843	3028
अगस्त, 1990	2908	2887
सितम्बर, 1990	2917	2926
अक्तूबर, 1990	3161	2884
नवम्बर, 1990	2851	3140
दिसम्बर, 1990	2982	3548
जनवरी-दिसम्बर, 90	35903	37459

विद्युत का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है। तथापि विद्युत की कमी की पूर्ति के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं : नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कटौती करना, मांग, प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना तथा अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण किए जाने की व्यवस्था करना।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

1538. **श्री हरि शंकर महाले :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई की मात्रा में कमी की गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 में, विशेषकर उन राज्यों के लिए जिनमें अब तक पूर्ण विद्युतीकरण नहीं हुआ है, इस कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्ष, 1990-91 में सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों को एस०के०ओ० के आवंटन में वृद्धि की गई है और पिछले वर्ष की इसी अवधि में आपूर्ति में कोई कमी नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों को एस०के०ओ० का आवंटन, पिछले

वर्ष की इसी अवधि में किए गए आबंटन की तुलना में उपयुक्त वृद्धि करके किया जाता है। एस० के०ओ० कम मिलने वाला उत्पाद है और देश की जरूरत की एक तिहाई से भी अधिक की जरूरत आयात द्वारा पूरी की जाती है। वर्ष 1991-92 के लिए एस०के०ओ० के आवंटन का कार्य, एस० के०ओ० के आयात के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली विदेशी मुद्रा पर निर्भर करेगा।

विशाखापत्तनम में ताप विद्युत केन्द्र

[अनुवाद]

1539. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में प्रस्तावित तटीय ताप विद्युत केन्द्र, तालचेर कोयला खान से कोयले का उपयोग करेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्र से कोयले की ढुलाई सस्ती रहेगी और दक्षिण क्षेत्र को विद्युत की गंभीर कमी से बचायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम में प्रस्तावित समुद्रतटीय ताप विद्युत केन्द्र में ईब घाटी कोयलाखान, उड़ीसा के गोपालपुरा क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग किया जाएगा। ईब घाटी कोयलाखान से प्रस्तावित केन्द्र तक कोयले की ढुलाई रेलमार्ग से की जाएगी जिसे वर्तमान स्थिति में लाइन क्षमता के विस्तार हेतु अपेक्षित निवेश को ध्यान में रखते हुए 'न्यूनतम लागत वाला उपाय'' समझा गया है।

पनबिजली का उत्पादन

1540. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में, सकल विद्युत बिजली उत्पादन में पनबिजली और ताप विद्युत में प्रतिशतता की दृष्टि के कोई असंतुलन है;

(ख) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के समक्ष पनबिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिये आंध्र प्रदेश के पोलावरम और इवेनपल्ली जैसी बड़ी परियोजनाओं पर निर्माण-कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में इचामपल्ली परियोजना (600 मेगावाट) के क्रियान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया था, जोकि अन्वेषण संबंधी कार्य किए जाने और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है। तथापि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को बताया है कि गोदावरी जल विवाद पंचाट के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार इचामपल्ली परियोजना एक अन्तर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना होने की प्रस्तावना है, इसलिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए अन्य दोनों राज्यों की सहमति प्राप्त करना भी अपेक्षित है।

पोलावरम स्कीम के मामले में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत

[हिन्दी]

1541. **श्री ए० लरंग साय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकल उत्पादन का कुल कितना प्रतिशत डीजल कृषि उद्देश्यों के लिये काम में लाया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा कृषि हेतु आवंटित किये जा रहे डीजल का प्रतिशत क्या है; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) कृषि क्षेत्र द्वारा डीजल की खपत के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) सरकार कृषि के लिए डीजल का आबंटन नहीं करती है। इस समय समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच०एस०डी० की आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है। जिस स्तर पर पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई थी। नवम्बर, 1990 तथा फरवरी, 1991 में कृषि क्षेत्र के लिए एच०एस०डी० का विशेष आबंटन किया गया है।

(ग) तेल कम्पनियों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे राज्य सरकारों से परामर्श करके कृषि क्षेत्र की मांग पूरी करने को प्राथमिकता दें।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों को रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन

1542. **श्री ए० लरंग साय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सरगुजा, बस्तर, मांडला, छिंदवाड़ा, रायगढ़, बिलासपुर और सिद्धी जिलों के कितने आदिवासियों को रसोई गैस एजेंसियों, पेट्रोल/डीजल पम्पों का गत तीन वर्षों के दौरान आबंटन किया गया है;

(ख) क्या ये निर्धारित किये गये लक्ष्यानुसार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) वर्ष 1988-90 के दौरान अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें उक्त जिलों में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) दिये गये हैं, निम्नलिखित हैं :—

जिला	एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	खुदरा बिक्री केन्द्र
1	2	3
सरगुजा	शून्य	3

1	2	3
बस्तर	—	1
मनदाला	—	1
छिंदवाड़ा	—	—
रायगढ़	—	—
बिलासपुर	—	—
सिद्धी	—	—

(ख) से (घ). डीलरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्र देने के लिए अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों के संबंध में कोई जिलावार लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

1543. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री ए० विजय राघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिन मार्गों में अत्याधिक यातायात है उनमें शीघ्र विद्युतीकरण करने के लिए संसाधनों की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए रेलवे विद्युती कार्यक्रम में गैर सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युतीकरण तथा इलैक्ट्रानिकी के लिए रेलवे विकास परिषद स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का रेल मार्गों के तेजी से विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) जिन नई रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाना है उनका नाम-वार तथा जोन-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ)	खंड	मार्ग कि०मी०	रेलवे जोन
1.	दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना	314	उत्तर
2.	गुमिया-पतरातू	72	पूर्व
3.	सीतारामपुर-झाझा	154	पूर्व
4.	बोकारो-मुरी-हटिया बोंडामुंडा-बरसुआन-बिमलगढ़-किरिबुरू	398	दक्षिण पूर्व
5.	अहमदाबाद-गांधीनगर	28	पश्चिम

कृषि क्षेत्र के लिये डीजल दिया जाना

1544. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त डीजल दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उद्देश्यों के लिये प्रत्येक राज्य को आवंटित किये डीजल की मात्रा क्या है ;

(ग) क्या डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति से डीजल की मांग पर कोई असर पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). जी, हां । सरकार ने फरवरी, 1991 के दौरान, कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्यों को 42,600 मी० टन अतिरिक्त एच०एस०डी० आवंटित किया है। 17 राज्यों को दी गई मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ). फरवरी, 1991 में दिए गए अतिरिक्त डीजल से कृषि के क्षेत्र को पर्याप्त राहत मिलने की आशा है ।

विवरण

फरवरी 1991 में कृषि के क्षेत्र को दिया गया एच०एस०डी०

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

क्रम सं०	राज्य	मात्रा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2100
2.	असम	500
3.	बिहार	1800

1	2	3
4.	गुजरात	2000
5.	जम्मू व काश्मीर	200
6.	हिमाचल प्रदेश	300
7.	हरियाणा	2200
8.	कर्नाटक	1400
9.	केरला	1100
10.	मध्य प्रदेश	1600
11.	महाराष्ट्र	3200
12.	उड़ीसा	600
13.	पंजाब	4100
14.	राजस्थान	1800
15.	तमिलनाडु	2600
16.	उत्तर प्रदेश	12900
17.	पश्चिम बंगाल	4200
		42,600

दिल्ली आने वाली दक्षिण एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

1545. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री पी०एम० सईद :

श्री तारीक सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फरवरी, 1991 को दिल्ली आने वाली दक्षिण एक्सप्रेस जो कतिपय विस्फोट के कारण पटरी से उतर गयी थी, की दुर्घटना की प्रारंभिक जांच कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और जन-धन की हानि सहित तथा दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों और उनके परिवारों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो इसके सहित दुर्घटना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). 6.2.1991 को नयी दिल्ली की ओर आने वाली हैदराबाद-निजामुद्दीन एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन 13 सवारी डिब्बों सहित दक्षिण मध्य रेलवे के वेमपल्ली और सिरपुर टाउन स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया था।

अन्तर्विभागीय जांच समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गयी थी जो इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यह दुर्घटना कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रेल-पथ के नीचे रखे किसी उपकरण के विस्फोट के कारण हुई।

इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गये और 23 व्यक्ति घायल हुए थे। किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। तथापि मृतक व्यक्तियों के आश्रितों और घायल यात्रियों को अनुग्रह राशि के रूप में 22,250/-रुपये का भुगतान किया गया है। रेल सम्पत्ति को 57,88,096 रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति

[हिन्दी]

1546. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश पेट्रोल/डीजल पम्पों के मालिक तेल कम्पनियों से तेल अपने ही तेल वाहनों में लाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आचरण मिलावट और काला बाजारी को बढ़ावा देता है; और

(ग) यदि हां तो मार्ग में मिलावट को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्रों को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति तेल कम्पनियों के टैंकरों तथा साथ ही साथ डीलरों/अन्य पार्टियों के ठेके के टैंकरों द्वारा किये जाते हैं।

(ख) जी,, नहीं।

(ग) पेट्रोल और डीजल के मिलावट को रोकने के लिए विम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) आपूर्ति और प्राप्ति बिन्दुओं पर ताप/घनत्व जांच। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए एम एस और एच एस डी (आपूर्ति और वितरण में कदाचार को रोकना) आदेश, 1990 को जारी किया गया है।

(2) मिट्टी के तेल में फरफुरल को मिलाना।

(3) छनन पत्र द्वारा जांच।

(4) चलन्त प्रयोगशालाओं को शुरू करना।

(5) तेल कम्पनियों और राज्य के प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित/अचानक जांच।

श्रमजीवी एक्सप्रेस में पेन्ट्री कार

1547. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में पेन्ट्री कार का प्रबंध कब तक कर दिया जायेगा;

(ख) उक्त रेलगाड़ी में लखनऊ से पटना और पटना से लखनऊ तक के लिये आरक्षण सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी; और

(घ) दिल्ली में पटना से दिल्ली की यात्रा करने के लिये कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) अब 2401/2402 श्रमजीवी एक्सप्रेस में पेन्ट्री कार सेवा चालू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग). इस गाड़ी में लखनऊ तथा पटना के बीच आरक्षण सुविधा उपलब्ध है।

(घ) जून, 1991 तक इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की गई है।

विमानपत्तनों से राजस्व की प्राप्ति

[अनुवाद]

1548. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में विमानपत्तनों से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : वर्ष 1990-91 के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों की कुल राजस्व प्राप्ति 335.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत का विलय

1549. **श्री मोरेश्वर सावे** :

श्री हरीश रावत :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के बारे में कर्मचारियों/कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों द्वारा कोई विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत का पुनर्गठन

1550. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वायुदूत सेवाओं के पुनर्गठन और विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि निश्चित की गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में वायुदूत सेवा से जोड़े जाने वाले नये स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में वायुदूत सेवाओं का पुनर्गठन करने और विस्तार करने के लिए कोई धनराशि खर्च करने का विचार नहीं है।

(ख) वायुदूत अपने मार्ग नेटवर्क का युक्तिकरण कर रहा है ताकि वह अपनी अत्याधिक हानि को कम कर सके और अपने बेड़े का और अधिक कुशलता से उपयोग कर सके। इसके फलस्वरूप वायुदूत की निकट भविष्य में किसी नए स्टेशन को हवाई सम्पर्क से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

बल्क औषधियों की आवश्यकता

1551. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में बल्क औषधियों की आवश्यकता है;

(ख) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इसका देश में निर्माण किया जाता है तथा कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाता है और इसका मूल्य कितना है; और

(ग) औषधियों के स्वदेशी उत्पादन को, विशेष रूप से जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) देश में 1989-90 के दौरान प्रपुंज औषधों की आवश्यकता 1120 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

(ख) देश में स्वदेशी और आयातित दोनों ही स्रोतों से प्रपुंज औषधों को देश की सूत्रयोगों की मांग के अनुसार तैयार किया जाता है। आयात का सीआईएफ मूल्य देश में प्रपुंज औषधों के खपत के कुल मूल्य का लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् 1989-90 के दौरान लगभग 270 करोड़ रुपए है।

(ग) स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से औषध नीति के अन्तर्गत अनेक कदम उठाए गए हैं, अर्थात् यदि स्वदेशी अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रक्रिया विकसित की गई हो तो मूल्य नियन्त्रण से छूट, किसी यूनिट द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों के 70 प्रतिशत तक इसके अपने ही सूत्रयोगों का उत्पादन करने के लिए अनुमति देना, लाइसेंस देने की उदार नीति, ब्रांड-बैंडिंग, न्यूनतम आर्थिक क्षमता प्रदान करना और सीमाशुल्क को युक्तियुक्त बनाना आदि।

पेट्रोल पम्पों पर छापे

1552. **श्री डी०एम० पुट्टे गौड़ा :**

श्री आनन्द सिंह :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डीजल की कमी का मौके पर पता लगाने के लिए दिल्ली और दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पम्पों पर अचानक छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है जिन पर छापे मारे गए हैं;

(ग) क्या उन पेट्रोल पम्पों पर डीजल की सप्लाई अपर्याप्त पाई गई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) तेल कम्पनियां और स्थानीय अधिकारीगण कदाचारों की जांच के लिए आवधिक आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित, अचानक और संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हैं।

(ख) निम्नलिखित पेट्रोल/डीजल पम्पों का तेल कम्पनियों द्वारा हाल में निरीक्षण किया गया है।

माह	नियमित	अचानक	संयुक्त	कुल
जनवरी, 91	124	108	31	263
फरवरी, 91 (21 तारीख तक)	149	394	93	636

(ग) खाड़ी युद्ध के छिड़ने के कारण भयातुर होकर की गई भारी खरीदारी के कारण दिल्ली में डीजल की कमी होने की रिपोर्ट मिली थी।

(घ) कम्पनियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के परिणामस्वरूप विगत हाल में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना

[हिन्दी]

1553. **श्री आर०एन० राकेश :**

डा० चिन्ता मोहन :

श्री बी० राजरवि वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकी-आर्थिक संभावनाओं की जांच करने हेतु गठित अन्तर-मंत्रालयीन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस दल की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दक्षिणी गैस ग्रिड में किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह दल इस प्रस्ताव के विभिन्न जटिल पहलुओं पर विचार कर रहा है। इसे अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस का औद्योगिक उपयोग

[अनुवाद]

1554. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की अनेक औद्योगिक कम्पनियों ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से उन्हें पोषक-स्टाक के तौर पर प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने कितनी मात्रा में गैस सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ग) इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). महाराष्ट्र में स्थित इकाइयों से तथा महाराष्ट्र सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपलब्धता के आधार पर, राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए लगभग 18 एमएमएससीएमडी गैस की वचनबद्धता की गई है। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए आबंटन

उपभोक्ता	मात्रा (मिलियन घन मीटर प्रति दिन)
1	2
1. राष्ट्रीय कैमिकलस एण्ड फर्टीलाइजर ट्रोम्बे	1.80
2. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर थाल	3.00
3. हैव्वी वाटर प्रोजेक्ट, थाल	0.15

1		2
4.	दीपक फर्टीलाइजर एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० तलोजा	0.60
5.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन तलोजा	0.03
6.	टाटा इलैक्ट्रीक कम्पनी, ट्रोम्बे	1.50
7.	महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रसिटी बोर्ड, ऊरान	4.50
8.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	0.01
9.	महाराष्ट्र गैस ब्रेंकर काम्पलैक्स, नागोथाने	0.60
10.	भारत पेट्रोलियम कॉ० लि०/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.05
11.	सी2/सी3 प्रोजैक्ट (ओएनजीसी)	1.15
12.	एलपीजी (ओएनजीसी)	1.80
13.	बम्बई सिटी डिस्ट्रीब्यूशन	1.50
14.	हिन्दुस्तान औरगेनिक कैमिकल्स	0.15
15.	ग्रासीम	0.75
16.	मैटाडीस्ट	0.01
17.	कल्याणी स्टील	0.75
18.	निप्पन डैन्नरो	1.00
	कुल :	18.55

आठवीं पंचवर्षीय योजना में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

1555. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में गैस पर आधारित कुछ विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गैस पर आधारित ऐसे कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाएंगे और इन्हें किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित किए जाने संबंधी लक्ष्य को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आठवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से कुल मिलाकर लगभग 7485 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। आठवीं योजनावधि के दौरान जिन गैस आधारित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त होने की आशा है इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	8वीं योजना के दौरान के लाभ (मेगावाट)
1	2	3	4	5
1. केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना	गुजरात	4×100+ 2×100	600
2.	कठलगुड़ी जीपीपी	असम	6×30+ 3×30	270
3.	दादरी जीपीपी	यू०पी०	4×131.3+ 2×146.5	817.2
4.	अंता जीपीपी विस्तार	यू०पी०	3×100+ 3×10	430
5.	गंधार जीपीपी	गुजरात	650	650
6.	गोदावरी जीपीपी	आंध्र प्रदेश	800	800
7.	रोखिया जीपीपी	त्रिपुरा	10×8	80
8.	फरीदाबाद जीपीपी	हरियाणा	4×130+ 2×140	800
9.	त्रिपुरा जीपीपी	त्रिपुरा	500	500
			उपजोड़	4947.2
2. राज्य क्षेत्र				
1.	उरण अपशिष्ट ऊष्मा	महाराष्ट्र	3×120	360
2.	विज्जेश्वरम जीपीपी (यू-3)	आंध्र प्रदेश	3×33+1×33	33
3.	लकदा सोपान-2	असम	3×20	60
4.	लकदा अपशिष्ट ऊष्मा	असम	1×22	22
5.	रामगढ़	राजस्थान	1×3	3
6.	वतवा जीपीपी	गुजरात	2×33.5+ 1×35	102

1	2	3	4	5
7.	उतरान जीपीपी	गुजरात	3×30+ 1×45	135
8.	गंधार जीपीपी	गुजरात	600	600
9.	पीपावव जीपीपी	गुजरात	750	750
10.	करायकल जीपीपी	पांडिचेरी	3×5+ 1×7.5	22.5
11.	अमगुरू जीपीपी	असम	8×30+ 4×30	360
12.	डेसू अपशिष्ट ऊष्मा	दिल्ली	3×30	90
			उपजोड़	2537.5
			कुल जोड़ (1+2)	7484.7

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और शोधन क्षमता में अन्तर

1556. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोलियम पदार्थों की शोधन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पेट्रोलियम पदार्थों की मांग और उनकी शोधन क्षमता में भारी अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) **और (ख)**. देश में वर्तमान शोधन क्षमता 51.85 मि० टन प्रति वर्ष है (इसमें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० की बम्बई रिफाइनरी की स्विग क्षमता 2 मि० टन प्रति वर्ष शामिल है)। वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 55.2 मि० टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का अनुमान है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में शोधन क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार की मंगलौर, करनाल तथा असम में तीन ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है। सरकार ने अभी हाल ही में नरीमनम में 0.5 मि० टन प्रति वर्ष क्षमता वाली सिंपल क्रूड आसवन इकाई स्थापित करने के लिए मद्रास रिफाइनरीज लि० का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। इनके अतिरिक्त, देश में कुछ वर्तमान रिफाइनरियों के कम लागत पर विस्तार के लिए गतिरोध दूर करने संबंधी प्रस्ताव/योजनाएं हैं।

एयर इंडिया का गैर-सरकारीकरण

1557. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एयर इण्डिया की सेवाओं का गैर-सरकारीकरण किये जाने का

प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या एयर इण्डिया घाटे में चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिदिन अथवा मासिक घाटा कितना है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी क्षेत्र में पन-बिजली उत्पादन

1558. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र और विशेषकर राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मेगावाट पन-बिजली का उत्पादन हुआ;

(ख) राजस्थान में वर्ष 1990-91 में पन-बिजली की स्थापित क्षमता कितनी है; और

(ग) राजस्थान में वर्ष 1991-92 में पन-बिजली में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) और (ख). विगत के तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान तथा उत्तरी क्षेत्र में कुल मिलाकर जल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :—

वर्ष	उत्तरी क्षेत्र		राजस्थान	
	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	विद्युत उत्पादन (मि०यू०)	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	विद्युत उत्पादन (मि०यू०)
1987-88	5692.175	21072	330	1015
1988-89	6043.425	23749	375	964
1989-90	6097.39	25189	420.165	961
1990-91 (अप्रैल, 90 से जनवरी, 91)	6097.39	23244	420.165	648

(ग) 1991-92 के दौरान राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि से लाभ, मंगरोल (3×2 मेगावाट) तथा सूरतगढ़ (2×2 मेगावाट) विद्युत उत्पादन यूनिटों के स्थायी रूप से प्रचालन किए जाने पर प्राप्त होने की संभावना है, इन यूनिटों को शीघ्र ही चालू किए जाने की आशा है ।

रेल लाइनों के साथ बसी बस्तियां

[हिन्दी]

1559. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में रेल लाइनों के साथ-साथ रेलवे भूमि पर बसी हुई कालोनियों को हटाने एवं उनके पुनर्वास के लिए कोई विस्तृत नीति निर्धारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। बेदखल किये गये व्यक्तियों के पुनर्वास का विषय संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

1560. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर से जयनगर, लोखाबाजार, रक्सौल, निर्मली दरभंगा और जयनगर दरभंगा के बीच चलने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयी हैं;

(ख) क्या हावड़ा से जयनगर तक सामान की ढुलाई भी रोक दी गई है;

(ग) क्या कोयला खदानों से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि तक रेलगाड़ियों के न मिलने के कारण कई ईंटों के भट्टे बंद हो गये हैं;

(घ) क्या हावड़ा स्टेशन पर स्लीपर आरक्षण पाने वाले यात्रियों को रेलगाड़ियों में सीटें नहीं मिलतीं और उन्हें रेलगाड़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इन खामियों को तत्काल दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) कुछ गाड़ियों को कम लोकप्रिय होने के कारण अस्थाई तौर से चलाना बंद कर दिया गया है।

(ख) हावड़ा से जयनगर के लिए माल यातायात की ढुलाई नहीं रोकी गई है। लेकिन, यातायात के सामान्य विनियमन के अनुसार भीड़-भाड़ के कारण गड़हरा के रास्ते ढोया जा रहा यातायात अस्थाई तौर से नियंत्रित किया गया था तथा जिसकी अब ढुलाई हो रही है।

(ग) रेल मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश के कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

(ङ) गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए

बारंबार जांच की जाती हैं। इन सवारी डिब्बों में ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन पर चल टिकट परीक्षक तथा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी तैनात किया जाता है। इसके अलावा, नए रेल अधिनियम, 1989 में कानूनी उपबंधों को और अधिक कड़ा बना दिया गया है जिनके अनुसार जुर्माने की राशि 500 रुपये तक निर्धारित की गई है जबकि पूर्ववर्ती अधिनियम में यह राशि 20 रुपये थी।

सरकारी क्षेत्र में जेंटामाइसीन का उत्पादन

[अनुवाद]

1561. **श्री के०एस० चावड़ा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेंटामाइसीन का उत्पादन केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र में जेंटामाइसीन के उत्पादन को आरक्षित किए जाने के समय से अब तक इसके वर्षवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जो भी जानकारी उपलब्ध है वह संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

वर्ष	उत्पादन (किग्रा० में)
1981-82	99
1982-83	410
1983-84	402
1984-85	507
1985-86	200
1986-87	—
1987-88	347
1988-89	946
1989-90	1527
1990-91 (फरवरी, 1991 तक)	1684 (अनन्तिम)

रेलवे स्टेशन पर पर्ची प्रणाली

1562. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने गंतव्य स्थान के रास्ते में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए एक नई प्रणाली निकाली है जिसमें वे अपना स्थान सुनिश्चित करने के बाद अपने कोच और उसके बाद बर्थ नम्बर का पता लगा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रणाली को अन्य रेलवे क्षेत्रों में भी शुरू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). उत्तर रेलवे द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए यात्रियों को पर्चियां जारी करने की प्रणाली लागू की गयी है जिसमें यात्री का नाम, गाड़ी सं०, यात्रा की तारीख, दर्जा, डिब्बा सं०, शायिका/सीट सं०, इंजन से डिब्बे की स्थिति लिखी होती है।

(ग) यह प्रणाली प्रायोगिक उपाय के रूप में लागू की गई है और फिलहाल इसे अन्य रेलों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य निष्पादन लक्ष्य

1564. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें वर्ष 1990-91, के कार्य निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कार्य निष्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वर्ष 1990-91, 1989-90 और 1988-89 के वास्तविक कार्य निष्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 और 1989-90 के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के समझौता ज्ञापनों में प्राचलों से संबंधित वास्तविक कार्य निष्पादन को संलग्न विवरण-1 में दिखाया गया है। वर्ष 1990-91 अभी प्रगति पर है और वार्षिक समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के प्रति वास्तविक कार्य निष्पादन वर्ष के अंत में ही उपलब्ध होगा। वर्ष 1990-91 के लिए विभिन्न प्राचलों के संबंध में समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को संलग्न विवरण-2 में दिखाया गया है।

विवरण 1

प्राचलों के संबंध में 1988-89 और 1989-90 के कार्य-निष्पादन

प्राचल	यूनिट	1988-89		1989-90	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6
क. वास्तविक					
1. सर्वेक्षण					
(क) भूकंपीय तट पर					
विभागीय—2डी	एसएलके	19540	50166	28120	49523
—3डी	एसएसके	—	—	300	423
ठेके पर—2डी	जीएलके	17582	15946	6125	3771
—3डी	एसकेएम	—	—	50	8
अपतट पर	एलकेएम	35000	39707	35000	39271
(ख) चुंबकीय गुरुत्व	संख्या	9000	12376	7000	12503
(ग) भूवैज्ञानिक	वर्ग कि०मि०	9000	14213	9025	14870
2. अन्वेषण खुदाई					
(क) मीटर	000एम	537.97	503.8	703.80	605.8
(ख) कुओं की संख्या	संख्या	180	182	274	253
(ग) रिग वर्ष	रि०व०	83.46	76.44	102.13	84.44
3. विकास ड्रिलिंग					
(क) मीटर	000एम	493.78	485.3	684.02	718.0
(ख) कुओं की संख्या	संख्या	300	283	368	372
(ग) रिग वर्ष	रि०व०	36.23	44.78	44.87	48.11
4. चक्र गति	मी/आर एम				
(क) तटवर्ती		616	616	662	769
(ख) अपतटीय		1093	921	1073	1076
(ग) कुल (औसत)		718	681	—	—

1	2	3	4	5	6
5. उत्पादन					
(क) कच्चा तेल	मि०मि०ट०	29.28	29.64	31.61	32.0
(ख) एल पी जी	"000टन	595	673.9	700.00	717.6
(ग) एला जी एल	"000टन	374	385.6	—	—
6. प्राकृतिक गैस की आपूर्ति	मि०घ०मी०	7166	6977	8636	8622
ख. वित्तीय (करोड़ रुपए)					
(क) कुल राजस्व		6597	6973	—	—
(ख) प्रचालन व्यय		4021	4801	5981	6509
(ग) निवल लाभ		1883	1602	1802	1624
(घ) आंतरिक स्रोत उत्पादन (नकद आधार)		2250	2617	2861	2019
(ङ) योजना परिव्यय		2350	2304	2330	2921

विवरण 2

वर्ष 1990-91 के कार्य-निष्पादन के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

क. वास्तविक लक्ष्य

(क) भू-कंपीय सर्वेक्षण	61484 एस०एल०के०
(ख) ड्रिलिंग मीटर	1217970 मीटर
(ग) कुओं की संख्या	537
(घ) चक्र गति	670 मीटर/रिग माह
(ङ) क्रूड उत्पादन	33.00 मि०मि० टन
(च) एल पी जी उत्पादन	725000 टन
(छ) गैस सप्लाई	9920 एम सी एम

ख. वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रुपए)

(क) व्यय	7441
(ख) निवल लाभ	1608
(ग) कुल आंतरिक स्रोत उत्पादन	2981
(घ) योजना व्यय	2632

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

[हिन्दी]

1565. **श्री हरीश रावत :**

श्री एम०एस० पाल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियां आबंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के सभी प्रमुख शहरों को एल पी जी के विपणन के लिए गढ़वाल विकास मण्डल निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा कवर किया गया है। आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य और छोटे शहरों में एल०पी०जी० विस्तार केन्द्रों के जरिए दी गई है। चूंकि उत्पाद की कमी है, और नये नामांकन प्रतिबंधित कर दिये गये हैं, अत: अभी यह कहना कि और ऐसे विस्तार केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे, संभव नहीं है।

पंजाब को मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई

[अनुवाद]

1566. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाब के लिए इन उत्पादों के कोटे में वृद्धि करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पंजाब सरकार द्वारा की गई डीजल और मिट्टी के तेल की मांग का ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान माह-वार और वस्तु-वार केन्द्र सरकार द्वारा इनकी कितनी सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समूचे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच एस डी की आपूर्ति इस समय उसी स्तर पर की जा रही है जिस स्तर पर पिछले वर्ष की इसी अवधि में की गई थी। एस०के०ओ० के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के आधार पर, सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों के दौरान किए गए आबंटन की तुलना में कुछ वृद्धि करके किया जा रहा है।

पंजाब को एच०एस०डी० और एस०के०ओ० की आपूर्ति वर्तमान नीति के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) पंजाब सरकार से समय-समय पर एच०एस०डी० की अतिरिक्त मांग प्राप्त हुई है। पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब को एस०के०ओ० और एच०एस०डी० की की गई आपूर्ति का महीनेवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

मूल रूप से कृषि क्षेत्र के लिए पंजाब को नवम्बर, 1990 में 10,000 मी०टन एच०एस०डी० और फरवरी, 1991 में 4100 मी०टन एच०एस०डी० की अतिरिक्त आपूर्ति की गई है।

विवरण

जनवरी-दिसम्बर, 1990 के दौरान पंजाब में एस०के०ओ०/एच०एस०डी० की बिक्री का महीनेवार ब्यौरा

(टन)

माह	एस०के०ओ०	एच०एस०डी०
जनवरी, 90	28395	119000
फरवरी	28742	94000
मार्च	27139	77614
अप्रैल	25796	103666
मई	25326	144425
जून	26160	132673
जुलाई	30371	81177
अगस्त	37590	113562
सितम्बर	26259	61737
अक्तूबर	27474	102558
नवम्बर	26780	115312
दिसम्बर (अस्थाई)	26569	93377

उत्तर भारत को जाने वाली रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं

1567. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत को जाने वाली रेलगाड़ियों में उपलब्ध यात्री सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) और (ख). उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियों में मौजूदा मानकों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं का उन्नयन और सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही में गाड़ियों में जिन कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है उनमें दूसरे दर्जे के शयनयानों में गद्दियों की व्यवस्था प्रायोगिक उपाय के रूप में कुछ गाड़ियों में जल शीतक, वातानुकूलित शयनयानों में बिस्तरों की व्यवस्था, कुछ सुपर फास्ट गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकों का चलना, कुछ चुनिंदा गाड़ियों में चलते फिरते गाड़ी के सफाई कर्मचारी, बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों में पानी की टंकी की क्षमता 1272 लिटर से बढ़ाकर 1820 लिटर करना आदि शामिल हैं।

पंजाब में रेलवे स्टेशन

1568. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में, विशेष रूप से पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान जिन रेलवे स्टेशनों का नवीकरण/पुनिर्माण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर स्टेशन-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब में और अधिक रेलवे स्टेशनों का नवीकरण/पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) स्टेशनों का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण का काम एक सतत् प्रक्रिया है और इससे सम्बन्धित कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार आयु एवं हालात के आधार पर किए जाते हैं। जहां तक पंजाब का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 रेलवे स्टेशनों यथा भटिन्डा, पटियाला, अलाल, भाबसर, अमृतसर और जालन्धर सिटी का नवीनीकरण/आधुनिकीकरण किया गया है।

(ख) स्टेशन-वार किया गया खर्च नीचे दिया गया है :

स्टेशन	खर्च (लाख रुपयों में)
भटिन्डा	2.50
पटियाला	12.56
अलाल	0.17
भाबसर	0.75
अमृतसर	47.06
जालन्धर सिटी	43.03

(ग) जी हां।

(घ) चालू वर्ष के दौरान 105.87 लाख रुपये की लागत पर ब्यास, मुकेरियां, फिल्लौर, अमृतसर, पटियाला, जलालाबाद, फिरोजपुर कैन्ट, फिरोजपुर सिटी और जालन्धर सिटी स्टेशनों के नवीनीकरण का काम शुरू करने का पहले ही प्रस्ताव किया गया है। 1990-91 के लिए 26.97 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

पंजाब में रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची

1569. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के प्रत्येक जिले में रसोई-गैस उपभोक्ताओं की नगर-वार और कस्बा-वार संख्या क्या है; और

(ख) पंजाब में रसोई गैस के लिए प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त व्यक्तियों की महानगर-वार और कस्बा-वार अद्यतन संख्या क्या है और उन सभी को गैस कनेक्शनों की मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). 1.1.91 के अनुसार पंजाब में एल०पी०जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों और एल०पी०जी० उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में नगरवार/शहरवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। एल०पी०जी० चूंकि एक कमी वाला उत्पाद है अतः क्रेताओं का नया नामांकन सीमित है। तथापि देशी उत्पादन और आयात को बढ़ाकर उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है।

विवरण

(दिनांक 1.1.91 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	शहर/कस्बे का नाम	एल पी जी उपभोक्ताओं की संख्या	एल पी जी कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची के व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	अमृतसर	90396	36312
2.	पट्टी	3166	3765
3.	तरणतारण	4156	635
4.	ब्यास	845	—
5.	जंडियाला	807	4241
6.	भटिण्डा	23287	17809
7.	मौर	601	3375

1	2	3	4
8.	रामपुरापुल	3541	1763
9.	बुधाल्दा	1802	1850
10.	मानसा	3003	4627
11.	फरीदकोट	5333	3028
12.	जैतू	1928	2361
13.	मुक्तशर	5964	5061
14.	कोटक पुरा	7515	4267
15.	गिदरबाहा	3543	1451
16.	मोगा	11775	7609
17.	मलौट	2832	4395
18.	अभोर	8703	4678
19.	जलालाबाद	780	3250
20.	फाजिल्का	5038	3841
21.	फिरोजपुर	11656	8991
22.	गुरदासपुर	7395	2280
23.	बटाला	10717	3381
24.	पठानकोट	26927	11571
25.	शाहपुरकंडी	30	2039
26.	टिबरी	—	—
27.	होशियारपुर	15601	8077
28.	मुकेरियन	4257	2024
29.	तलवाड़ा	1586	1019
30.	उमरटांडा	4190	2386
31.	आदमपुर	1997	715
32.	बंगा	4295	556
33.	नवशहर	4432	2039
34.	नकोदर	1848	1899
35.	करतारपुर	886	2580
36.	जालन्धर	66850	34568

1	2	3	4
37.	फिल्लौर	1822	2327
38.	सुल्तानपुर लोधी	173	2253
39.	कपूरथला	11908	5642
40.	फगवाड़ा	10054	6496
41.	हुसैनपुर	1111	—
42.	हलवाड़ा	1826	434
43.	खन्ना	7433	7618
44.	लुधियाना	105263	62523
45.	रायकोट	1714	3356
46.	जगरांव	5482	1670
47.	बस्तीपठानां	3853	67
48.	मंडी गोविन्दगढ़	6603	2826
49.	राजपुरा	9036	3578
50.	समाना	3232	3650
51.	पटियाला	41985	31390
52.	नाभा	9509	3234
53.	सिरहिन्द	3761	2301
54.	महाली	11922	9377
55.	कुराली	1416	7262
56.	मंगल	8130	3101
57.	रोपड़	8717	4144
58.	धुरी	3412	2924
59.	संगरूर	9659	3405
60.	बरनाला	3244	4707
61.	सुनाम	2885	2382
62.	मलेरकोटला	3341	4113
63.	अहमदगढ़	900	2988

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं

1570. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक परियोजना पर कितना पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है, इनके चालू होने की संभावित तारीखें क्या हैं और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर इससे कितने किलोवाट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	क्षमता (मे०वा०)	चालू करने का सम्भावित कार्यक्रम
1	2	3	4	5
	ताप विद्युत			
1.	लाकवा जी०टी० फेज-2 (असम)	78.74	3 × 20 = 60	91-92
2.	लाकवा अपशिष्ट ऊष्मा संयंत्र (असम)	60.00	1 × 22 = 22	चूंकि मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर के लिए अभी आर्डर दिया जाना है, अतः चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रत्याशा कर पाना सम्भव नहीं है।
3.	बारगोलाई (असम)	90.00	2 × 30 = 60	स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की पुनरीक्षा की जा रही है।
4.	कठलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकिल परि० (असम)	203.17	6 × 30जी०टी० + 3 × 30एस०टी० = 270	चूंकि मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर के लिए अभी आर्डर दिया जाना है, अतः चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रत्याशा कर पाना सम्भव नहीं है।

1	2	3	4	5
	जल-विद्युत			
1.	टागो (अरुणाचल प्रदेश)	10.09	3×1.5=4.5	यूनिट-1 को रोटेट किया गया यूनिट-2 एवं 3—मार्च, 91.
2.	लिकिम-रो (नागालैण्ड)	33.84	3×8=24	1993-94
3.	उमियम उम्तरू चरण-4 (मेघालय)	104.88	2×30=60	1991-92
4.	ओअर बोरपानी (असम)	146.55	2×50=100	1992-93
5.	घनसिरी (असम)	45.51	15×1.33 =19.95	1992-93
6.	रंगानदी चरण-1 (अरुणाचल प्रदेश)	400.00	3×135 =405	9वीं योजना
7.	दोयांग (नागालैण्ड)	200.00	3×25=75	1994-96

(ख) जी, हां।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उन जल-विद्युत परियोजनाओं जिनका सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य चल रहा है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम और राज्य	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
1.	रंगानदी चरण-2 (अरुणाचल प्रदेश)	100
2.	दामवे (अरुणाचल प्रदेश)	1000
3.	डिकरोंग (अरुणाचल प्रदेश)	60
4.	कारबी (बोरपानी इन्ट०) (असम)	60
5.	आमरिंग (असम)	33
6.	कोपिली चरण-2 (असम)	25
7.	तुईरियाल (मिजोरम)	60
8.	तुईवाई (मिजोरम)	140
9.	तिजु जुंगी (800/2000) (नागालैण्ड)	800
10.	दिखु-तामला (नागालैण्ड)	45

1	2	3
11.	शिल्लोई चरण-1 (नागालैण्ड)	20
12.	माइंटडु 1 (मेघालय)	36
13.	माइंटडु 2 (मेघालय)	36
14.	उमियम उम्तरू 5 (मेघालय)	40
15.	उम्गोट (मेघालय)	36
16.	लोग्रर बाराक (मणिपुर)	90

इम्फाल में इंडियन एयरलाइन्स के लिये नया भवन

1571. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में इंडियन एयरलाइन्स एकक के लिये नये भवन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इम्फाल में इंडियन एयरलाइन्स भवन में बुकिंग और अन्य प्रयोजनों संबंधी वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नये भवन के निर्माण कार्य के पूरा होने में देरी न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) इम्फाल में नये सिटी बुकिंग कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन इसमें यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिये कुछ फेरबदल किये जाने हैं।

(ख) और (ग). जबकि इम्फाल में वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन नये भवन के शुरू हो जाने पर उसमें अपेक्षित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इम्फाल हवाई अड्डे पर सुविधाओं में सुधार

1572. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इम्फाल हवाई अड्डे पर (एक) खान-पान की बेहतर सेवा, (दो) आने और जाने वाले लोगों के लिये अलग-अलग शौचघर की व्यवस्था के साथ अधिक जगह वाले विश्राम गृह और (तीन) अति विशिष्ठ व्यक्तियों के लिये बड़े तथा अधिक सुसज्जित विश्राम गृह आदि से संबंधित सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : इम्फाल हवाई अड्डे पर एक साथ आने वाले 300 यात्रियों और प्रस्थान करने वाले 300 यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल भवन में विस्तार और फेर-बदल करने का प्रस्ताव है। इस योजना को 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1991-92 के दौरान शुरू करने का विचार है। नये डिजाइन में रेस्तरां स्नैक-बार, डाकघर और दुकानें, प्रस्थान नियन्त्रण क्षेत्र के वातानुकूलन, आराम-कक्ष, और खुले हुए पूर्णतया सुसज्जित अति विशिष्ट कमरों जैसी सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने पर ध्यान दिया गया है।

रूपसा बांगड़ी पोसी रेल लाइन को बदलना और इसका विस्तार करना

1573. **श्री समरेन्द्र कुन्डु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपसा बांगड़ी पोसी रेल लाइन जो इस समय छोटी लाइन है, को बड़ी लाइन में बदलने और इसका घलभूम तक विस्तार करने के लिये सर्वेक्षण हेतु हाल ही में आदेश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब पूरा होगा; और

(ग) उक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसका विस्तार करने का अनुमानित व्यय कितना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 1979-80 में किये गये सर्वेक्षण को अद्यतन करने के लिए दिसम्बर 1990 में आदेश दिए गए थे ।

(ख) सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम पूरा कर लिया गया है ।

(ग) अद्यतन सर्वेक्षण में आकलित की गई लागत नीचे दी गई हैं :—

रूपसा-बांगरीपोती छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (89 कि०मी०)	51.59 करोड़ रु०
रूपसा-बांगरीपोसी छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव तथा इसका घलभूमगढ़ तक विस्तार (131 कि०मी०)	85.47 करोड़ रु०

दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये एयर इंडिया की विमान सेवाएं

1574. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी युद्ध के कारण मध्य-पूर्व क्षेत्र से एयर इंडिया को होने वाले घाटे की पूर्ति के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया अर्थात् सिंगापुर और बैंकाक के लिए विमान सेवाओं में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए प्रति सप्ताह कितनी विमान सेवाएं हैं और इन सेवाओं की संख्या में कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के लिए विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि से एयर इंडिया की आय में होने वाली संभावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) से (ग). एयर इंडिया ने सिंगापुर के लिए दो अतिरिक्त ए-310 टर्मिनेटर सेवाएं शुरू की हैं । इससे सिंगापुर के लिए उड़ानों की कुल संख्या बढ़कर प्रति सप्ताह सात सेवाएं हो गई हैं। इस समय एयर इंडिया बैंकाक के लिए सप्ताह में चार सेवाओं का परिचालन कर रहा है और अप्रैल, 1991 से बैंकाक के लिए तीन अतिरिक्त ए-310 टर्मिनेटर सेवाओं को शुरू करने की जांच कर रहा है । सिंगापुर के लिए अतिरिक्त दो आवृत्तियों के माध्यम से एयर इंडिया को लगभग 30 लाख रुपए की अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है ।

पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करना

1575. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को अपनी क्षमता को बढ़ाकर चार लाख टन प्रतिवर्ष करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो लाभ प्राप्तकर्ताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसका विदेशी मुद्रा के निर्गमन पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ग). ओलीफिन काम्पलैक्सों के लिए न्यूनतम आर्थिक आकार प्रतिवर्ष इथाइलीन 3,00,000 से 4,00,000 टन इथाइलीन निर्धारित किया गया है।

विशिष्ट प्रस्तावों पर निर्णय जब भी वे प्राप्त होते हैं तो उसमें, विदेशी मुद्रा व्यय सहित, तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर लिए जाते हैं।

सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस और राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस को रद्द किया जाना

1576. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने "सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस" ट्रेन संख्या 9017/9018 और "राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस" ट्रेन संख्या 1269/1270 को रद्द करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त रैलगाड़ियों को हापा और अहमदाबाद के बीच वाष्प इंजिनों से और अहमदाबाद से आगे बिजली के इंजिनों से आसानी से चलाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों की असुविधा को देखते हुए इनको रद्द करने के आदेशों को वापस लेने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) से (घ). 9017/9018 बंबई-हापा सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस और 1269/1270 राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस गाड़ियों को खाड़ी संकट को ध्यान में रखते हुए, ईंधन की बचत के लिए 25.1.91 से चलाना बंद कर दिया गया था, बहरहाल, 9017/9018 एक्सप्रेस को 1.2.91 से बहाल कर दिया गया है, स्थिति में सुधार होते ही 1269/1270 को भी बहाल कर दिया जायेगा। इन गाड़ियों को भाप रेल इंजनों से चालाना परिचालनिक दृष्टि से न तो आसान होगा और न ही वांछनीय है।

रेलगाड़ियां रद्द किया जाना

1577. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने के संबंध में जाम नगर से 24 जनवरी, 1991 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) रद्द की गयी इन रेलगाड़ियों को पुन: कब से चलाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी हां।

(ख) 9017/9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस और 1269/1270 राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस को पुन: चलाने के संबंध में।

(ग) और (घ). 9017/9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस गाड़ी 1.2.1991 से पुन: चला दी गयी है, रेलों पर स्थिति सुधर जाने पर 1269/1270 राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी पुन: चला दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और अयोध्या में पेट्रोल/डीजल पम्पों का आबंटन

[हिन्दी]

1578. **श्री मित्रसेन यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की ओर से सरकार को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और अयोध्या में पेट्रोल/डीजल पम्पों और खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की स्थापना के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ये एजेंसियां कब तक कार्य शुरू कर देंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) फैजाबाद और अयोध्या में एल०पी०जी० की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप और पेट्रोल/डीजल के दो खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(ग) किसी भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू किये जाने से पूर्व की जाने वाली विभिन्न कार्यवाहियों को देखते हुए यह बताना कि कब तक वे कार्य करना शुरू कर देंगी, संभव नहीं है।

मद्रास में जनता हेतु परिवहन व्यवस्था

[अनुवाद]

1579. **श्री अन्बारासु इरा** :

श्री आर० जीवनरत्नम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में जनता रेल परिवहन व्यवस्था के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) उसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) 1. 31.1.91 तक किया गया खर्च = 50.32 करोड़ रुपये।

2. 31.1.91 तक वास्तविक प्रगति = 42 प्रतिशत।

(ख) यह निम्नलिखित पर निर्भर करेगा :—

1. आने वाले वर्षों में धन की उपलब्धता पर, और
2. तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा राधाकृष्णन सलाय से लुज तक शेष भूमि के सौंपे जाने पर।

मद्रास स्टेशन पर पुल

1580. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर 14 पैदल उपरिपुल बनाने के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ख) इस परियोजना पर अब तक इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ग) यह कब तक पूर्ण होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) निम्नलिखित दो स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत मद्रास सेन्ट्रल में ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है :

क्र०सं०	कार्य का नाम	लागत (लाख रुपयों में)
1.	मद्रास सेन्ट्रल-प्लेटफार्मों की बढ़ी हुई लम्बाई की व्यवस्था करने के लिए यार्ड के ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तन	407.22
2.	मद्रास सेन्ट्रल-प्रतीक्षाकक्ष तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।	178.68

(ख) इन योजनाओं पर 31.3.1991 तक 169.23 लाख रुपये की कुल राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

(ग) ऊपरी पैदल पुल का कार्य वर्ष 1992 में पूरा हो जाने की संभावना है।

ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के नाम में परिवर्तन

1581. **श्री अन्बारासु इरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का नाम बदलकर इन्दिरा गांधी एक्सप्रेस रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की भावी योजनाओं के लिए धनराशि में कटौती

1582. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की भावी योजनाओं के लिए आवंटित किये जाने वाले अनुमानित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे के विकास कार्यों में किन क्षेत्रों पर बल दिये जाने का विचार है;

(ग) क्या वित्तीय संकट को देखते हुए रेलवे परियोजनाओं के लिए पहले से ही स्वीकृत धनराशि में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) भावी योजनाओं के लिए परिव्यय योजना का पता योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही लगेगा।

(ख) परिचालनिक लागतों को कम करने के उद्देश्य से गतायु परिसम्पत्तियों के बदलाव/पुन: स्थापन, अतिरिक्त क्षमता का निर्माण, आधुनिकीकरण करने तथा विशेषतौर पर तकनीकी उन्नयन करने पर बल दिया जायेगा।

(ग) और (घ). 1991-92 के लिए योजना आबंटन 6,500 करोड़ रुपये की प्रक्षेपित आवश्यकता की तुलना में 4,820 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है क्योंकि योजना आबंटन कम होने से अलग-अलग परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन मूल्य आवश्यकता से कम हो जायेगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

1583. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** :

श्री पी०सी० थामस :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाए जाने से अब तक कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान मूल्य क्या है तथा खाड़ी युद्ध से पहले के मूल्य क्या थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) 25 प्रतिशत खाड़ी अधिभार के लगाये जाने से 22.2.91 तक लगभग 2100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग). जबकि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है, किन्तु 17.1.91 को खाड़ी में युद्ध के भड़कने से उत्पाद की कीमत में उतार-चढ़ाव आया है। प्लेट्स प्रकाशन के अनुसार 16.1.91 की यथास्थिति को कच्चे तेल, एस०के०ओ० और एच०एस०डी० की कीमतें, खाड़ी युद्ध के आरम्भ होने से पूर्व और 27.2.91 को निम्न प्रकार थी :

कच्चा तेल	16.1.1991	27.2.1991
(दुबई) डालर/बी०बी०एल	25.30	14.08
एस०के०ओ० (ए०जी०) डालर/एम०टी०	366.31	235.17
एच०एस०डी० (ए०जी०) डालर/एम०टी०	317.64	233.06

वायुदूत द्वारा हवाई पट्टियों को बन्द करना

[हिन्दी]

1584. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1991 के जनसत्ता में "अधर में लटका है वायुदूत का भविष्य" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान वायुदूत की कितनी हवाई पट्टियों को बन्द किया गया और कितनी हवाई पट्टियां पुनः चालू की गयीं;

(ग) इन हवाई पट्टियों को बन्द करने के कारण वायुदूत को कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) विशेष अवधि के लिए इन्हें बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख). सितम्बर, 1990 से ऐसे सात स्टेशनों में वायुदूत की सेवाएं बन्द कर दी गई थीं जहां केवल वायुदूत की सेवाएं परिचालित की जा रही थीं। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के 32 स्टेशनों में वायुदूत की सेवाएं बन्द कर दी गई थीं। गत छः महीनों के दौरान बन्द की गई ऐसी कोई सेवा पुनः शुरू नहीं की गई है।

(ग) और (घ). हालांकि जब इन विभिन्न स्टेशनों पर वायुदूत की सेवाएं परिचालित की जा रही थीं, उस समय भी इसकी सेवाएं अत्यधिक अनियमित, अविश्वसनीय और अलाभकारी होती थी। अलाभकारी परिचालनों और वायुदूत को अत्यधिक हानि होने के कारण इन सेवाओं को बन्द करना पड़ा था। वर्ष 1981 के प्रारम्भ से वायुदूत को 31 दिसम्बर, 1990 तक 120 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

वायुदूत के सचिवों और प्रबन्ध निदेशकों को हटाना

1585. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत के कितने सचिवों और प्रबन्ध निदेशकों को गत छः माह के दौरान उनके पदों से हटाया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान वायुदूत लिमिटेड के किसी भी सचिव या प्रबन्ध निदेशक को सेवा से हटाया नहीं गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस के बोइंग विमान के अपहरण का प्रयास

[अनुवाद]

1586. **कुमारी उमा भारती :**

श्री पी०एम० सईद :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता-अगरतला मार्ग पर इंडियन एयर-लाइंस के एक बोइंग विमान के तथा-कथित अपहरण का प्रयास इसके चालक दल ने विफल किया था;

(ख) क्या अपहरणकर्त्ता को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ की गयी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपहरण के ऐसे प्रयास जनवरी, 1991 के दौरान किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क), (ख) और (घ). एक शस्त्ररहित यात्री ने संबंधित उड़ान पर असामान्य रूप से व्यवहार किया और उसने उड़ान को कलकत्ता वापस ले जाने के लिए कहा । तथापि, उस पर काबू पा लिया गया और अगरतला में उड़ान के उतरने पर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। विमान से गैर-कानूनी हस्तक्षेप को रोकने के लिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा टेट्रासायक्लीन की खरीद

1587. **डा० असीम बाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने देश में "टेट्रासायक्लीन" के निर्माण की सभी सुविधाएं एवं प्रचुर क्षमता विद्यमान होने के बावजूद जुलाई/अगस्त, 1989 में चीन में निर्मित इस औषधि को पश्चिमी जर्मनी से आयात किया था;

(ख) क्या इस मद की खरीद हेतु विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनसे पूछताछ की गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो पश्चिम जर्मनी के इस प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप के प्रस्ताव को किस प्रकार स्वीकार किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) उद्योग से दबाव और अल्पकालिक भारी मांग को पूरा करने हेतु आई०डी०पी०एल० ने जुलाई/अगस्त, 1989 के दौरान पश्चिमी जर्मनी से चीन द्वारा निर्मित 20 टन टेट्रासाइक्लिन का आयात किया है। आई०डी०पी०एल० के पास इसके विनिर्माण और सप्लाई करने के लिए अवस्थापना सुविधाएं और क्षमता थी बशर्ते मांग समानरूप से होती ।

(ख) से (घ). आई०डी०पी०एल० की क्रय प्रक्रिया के अनुरूप चीन, हांगकांग, इटली, पश्चिमी जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि सहित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टेट्रासाइक्लिन, हाइड्रोक्लोराइड की सप्लाई के 19 जाने माने प्रमुख स्त्रोतों की सीमित निविदा जांच जारी की गई थी। जिन पार्टियों से निविदा पूछताछ की गयी थी उनकी सूची संलग्न विवरण में दी जाती है। मूल्य, साख शर्तों आदि के संदर्भ में तुलनात्मक प्रस्तावों का मूल्यांकन करके प्रतियोगी स्वरूप का निर्धारण किया गया था।

विवरण

1. चाईना नेशनल केमिकल्स,
इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कोरपो०,
इर-लि-कू, हसी चिआऊ,
पीकिंग, पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना,
चीन।

2. फामाचिम,
लियंसको चाउसी 16, सोफिया,
बल्गारिया।

3. चेम्पोल लि०,
कोर्डेसका 46,
10010 प्रेग 10,
चेकोस्लोवाकिया।

4. हैक्स्ट ए० जी०,
पोस्टफेक्ट 800 32 सी,
6230 फ्रैंकफर्ट मेन 80,
जर्मनी।

5. सोसाइटा प्रोडोसी एंटिबायोटिकल एस०पी०ए०,
8, वाया बिला, 20143 मिलानो,
इटली।

6. सिनामिड इटेलिया एस०पी०ए०
एक्स०वी० स्ट्राडा, जोना इंडस्ट्रियल,
950 30 केन्टानिया, **इटली।**

7. सियक,
पो० बोक्स 271,
00950, वार्सा, पोलेण्ड

8. मेडिम पैक्स,
बुडापेस्ट, हंगरी

9. हेल्म एजी,
नौरडावनल स्ट्रासी 23,
डी-200 सी हमबर्ग-1,
पश्चिमी जर्मनी।

10. सिमाग्लस एण्ड सौन,
हमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी।

11. ग्लोस फोरचुन,
हांगकांग।

12. ए०पी०सी० फार्मास्युटिकल्स एण्ड केमिकल्स,
हांगकांग।

13. नी मेंगू ओटोनोमस रिजन मेडिसन्स एण्ड हैल्थ प्रोडक्ट्स,
इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कोरपोरेशन, वेस्ट हुहोत, चीन।

14. आइपोर्ग,
एल्मसोर्न, पश्चिमी जर्मनी।

15. मेटालगसेयसेफ्ट इंडिया लि०,
नई दिल्ली।

16. चिपान,
पुर्तगाल।

17. एच०एन० डब्ल्यू० (चीन) इंटरप्राइजिज,
हांगकांग।

18. ग्लोव केमिकल्स,
हमबर्ग।

19. मेडेक्सपर्ट,
काखोरा 31, पोर्ट 2,
113461 मास्को यू०एस०एस०आर०,
सी०ए० मेडेक्सपोर्ट।

ऊर्जा की कम खपत करने वाले बल्ब विकसित करना

1588. **श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शेनेक्टेडले, न्यूयार्क स्थित जनरल इलेक्ट्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने ऐसा बल्ब विकसित किया है जिसमें केवल 60 प्रतिशत ऊर्जा खर्च होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका में इन बल्बों का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया जा चुका है;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिक द्वारा भी इस दिशा में कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बबनराव ढाकणे) : (क) से (ङ). ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि शेनेक्टेडले, न्यूयार्क स्थित जनरल इलेक्ट्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने ऊर्जा की बचत करने वाले एक बल्ब का विकास किया है जोकि इन्फरा रैड किरणों को पुनः फिलामैंट की ओर परावर्तन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इस लैम्प से 60% ऊर्जा की बचत होती है और यह प्रभामण्डल का सुस्पष्ट रंगहीन प्रकाश देता है जिसकी किरणें सामान्य इन्कडेसेन्ट बल्ब की किरणों से 33.3% अधिक शीतल होती हैं। ऐसा पता चला है कि इन लैम्पों की वाणिज्यिक उत्पादन की हाल ही में यू०एस०ए० में शुरूआत की गई है। भारत में इस प्रोद्यौगिकी को लागू किए जाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि कार्यों में उपयोग के लिए डीजल

1589. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल चालित कृषि कार्यों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पम्पसेटों को डीजल के उपयोग पर लगायी जाने वाली कटौती से मुक्त रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को लाखों अकुशल पम्पसेटों द्वारा ऊर्जा की बर्बादी के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो डीजल की बर्बादी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख). तेल कम्पनियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता के आधार पर कृषि के क्षेत्र की डीजल की जरूरतें पूरी करें। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने स्थानीय स्तर पर अलग-अलग उपाय अपनाए हैं। इस उद्देश्य के लिए, कुछ राज्यों/जिला प्राधिकारियों द्वारा परमिट प्रणाली लागू की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ और अन्य अनेक संगठनों से पहले ही ऐसे लगभग 5000 पम्प सेटों में पूरी तरह से आंशिक संशोधन किया है। यह कार्य चालू है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अकुशल फुट वाल्वों के स्थान पर आई०एस०आई० चिह्न वाले ऐसे कुशल फुट वाल्वों को लगाने की योजना है जो सबसे अधिक लागत-प्रभावी विकल्प हैं, और जिसमें इंधन की खपत में लगभग 10% की बचत की सम्भावना है।

2.33 म०प०

लोक सभा 2.33 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1991 और वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1991 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन): मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1991, जो 3 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 7 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 58(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2195/91]

रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं श्री भक्त चरण दास (रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रेल रैड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1990 जो 14 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 947(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2196/91]

(दो) रेल रैड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1991 जो 8 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-

लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2197/91]

2.34 म०प०

याचिका

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत नियुक्त आंगनवाड़ी महिला कर्मकारों की मांगों तथा शिकायतों के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी महिला कर्मकारों की मांगों तथा शिकायतों के बारे में उक्त योजना के अंतर्गत कार्यरत नीलिमा मैद्रा तथा अन्य महिला आंगनवाड़ी कर्मकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 2198/91]

2.34½ म०प०

पंजाब बजट 1991-92

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1991-92 के लिए पंजाब राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2199/91]

2.35 म०प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91 के लिए पंजाब राज्य के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2200/91]

2.35½ म०प०

जम्मू-कश्मीर बजट 1991-92

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1991-92 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[पंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2201/91]

2.36 म०प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर) 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91) के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[पंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2202/91]

2.36½ म०प०

असम बजट 1991-92

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1991-92 के लिए असम राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

[पंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2203/91]

2.36¾ म०प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम) 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91 के लिए असम राज्य के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[पंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2204/91]

2.37 म०प०

तमिलनाडु बजट 1991-92

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1991-92 के लिए तमिलनाडु राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2205/91]

2.37½ म०प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु) 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91 के लिए तमिलनाडु राज्य के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2206/91]

2.38 म०प०

पांडिचेरी बजट 1991-92

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1991-92 के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[पंचालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2207/91]

2.38½ म०प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91 के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं। **(व्यवधान)**

[पंचालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2208/91]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय भारत में कई अन्य राज्य हैं। उनका क्या होगा ? **(व्यवधान)**

2.39 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत गांवों में कुएं खुदवाने और पाइप लाइन डलवाने हेतु बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की राशि बढ़ाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : गांवों में विशेष घटक योजना के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों को पाइप लाइन डालने हेतु कुएं खुदवाने हेतु कर्ज दिया जाता है। जैसे कुआं खुदवाने हेतु 18,000/- रुपये व पाइप लाइन डलवाने हेतु प्रति एकड़ 4000/-, ये निर्देश "नाबार्ड" द्वारा दिए गए हैं। किन्तु आजकल की महंगाई को देखते हुए यह रकम काफी कम है। इसमें पूरा काम नहीं होता व लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। उन्हें कहीं से और कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह से दोनों तरफ से कर्ज में डूब जाते हैं। अत: यह राशि कुएं के लिए 40,000/- रुपए व पाइप लाइन हेतु प्रति एकड़ 10,000/- रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पर तत्काल अमल करने हेतु संबंधित मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

(दो) राजस्थान के गंगा नगर और बीकानेर जिलों को सिंचाई के लिए भाखड़ा और गंग नहरों से पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : राजस्थान के गंगानगर व बीकानेर जिले की करीब 30 लाख एकड़ भूमि पंजाब से बहकर आने वाली नदियों से गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल वह इन्द्रा गांधी कैनाल सिस्टम से आबपाश हो रही है। इन नहरों के निर्माण तथा इस क्षेत्र को विकसित करने में राजस्थान सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया है। हरियाणा व राजस्थान को आबपाश करने वाली इन नहरों के हेड वर्क्स के संचालन के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए भाखड़ा प्रबंध बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए था मगर आज तक इन हेड वर्क्स का संचालन भाखडा प्रबंध बोर्ड को नहीं सौंपा गया है तथा इन हेडवर्क्स का तमाम इंतजाम पंजाब के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास है।

पंजाब में उग्रवादियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण पंजाब के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बीकानेर तथा गंगानगर जिले के लाखों किसानों के सामने एक विकट समस्या पैदा कर दी है जिसके कारण भाखड़ा तथा गंगनहर क्षेत्र में उसके हिस्से का पानी देना तो दूर बल्कि गंगा नहर के पुनर्निर्माण के लिए बनने वाली लिंक चैनल को बनाने के लिए 15 रोज की बड़ी सरहिन्द फिडर में देने के लिए भी तैयार नहीं।

भाखड़ा डैम अब उग्रवादियों की हरकतों के कारण 10 फीट वर्षा के मौसम में खाली रखा जायेगा। इसका स्पष्ट असर यह होगा कि भाखड़ा क्षेत्र में खरीफ व रबी के मौसम में किसानों को कम पानी मिलेगा। समय जहां कपास, गन्ना व धान की खेती मुख्य फसल हो गई है वहां मात्र ग्वार व बाजरा की फसल ही बोई जा सकेगी। सतलुज नदी का पानी भविष्य में हमारी नहरों में न देकर पाकिस्तान में बहा करेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाए जाएं।

(तीन) 1981 में जारी किये गये वाहक बन्ध पत्रों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1981 में बाजार से काला धन एकत्र करने के लिए 10,000/- रुपये अंकित मूल्य के वाहक बन्ध पत्रों को जारी किया जो दस वर्ष की अवधि के बाद 12,000/- रुपये प्रति बन्ध पत्र पर परिशोध्य थे। यद्यपि, शुरू में इसे लेने वालों की संख्या बहुत कम थी, यह बन्ध पत्र तभी प्रचलित हो पाए जब सरकार ने यह आश्वासन दिया कि बन्ध पत्रों को खरीदने वालों को न तो परेशान किया जाएगा और न ही उनसे आय के स्रोत के बारे में कुछ पूछा जाएगा। इस प्रकार सरकार ने करीब 950 करोड़ रुपये जुटाए।

इन बन्ध पत्रों की पहली किश्त लौटाने का समय पूरा हो गया है और बन्ध पत्रों की अंधाधुंध कालाबाजारी चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बन्ध पत्र धारकों से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है और अब वास्तविक अदायगी जल्द ही शुरू होने वाली है।

पता चला है कि बन्ध पत्र धारकों ने गंभीर घोटाला किया है—इन बन्ध पत्रों पर निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त कलकत्ता में 10,000 से 12,000 रुपये के बीच लाभ लिया जा रहा है। यह लाभ दिल्ली और मुम्बई में और अधिक भी हो सकता है।

इन बन्ध पत्रों के कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने का यह उपयुक्त समय है।

(चार) नैनीताल (उत्तर प्रदेश) में जसपुर विकास खंड के मोगपुर और तुमडिया के ग्रामवासियों के नाम पर भूमि को नियमित किये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री एम०एस० पाल (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड जसपुर में स्थित मोगपुर डाम, तुमडिया डाम में बसे बहुत से ग्रामवासी पिछले 40-45 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, परन्तु अभी तक उक्त भूमि का नियमीकरण नहीं किया गया है, जिससे मोगपुर डाम व तुमडिया डाक के वासी कृषि उत्पादन सम्बन्धी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

अतः मोगपुर डाम व तुमडिया डाम में बसे ग्राम-वासियों के नाम भूमि धरी (नियमीकरण) कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्पूर्ण सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

2.43 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री कपिल देव शास्त्री द्वारा 27 फरवरी, 1991 को पेश किये गये और श्री बृज भूषण तिवारी द्वारा 4 मार्च, 1991 को समर्पित निम्नलिखित प्रस्ताव पर

[उपाध्यक्ष महोदय]

आगे चर्चा होगी :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—
'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 21 फरवरी, 1991 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में न तो कहीं किसानों का जिक्र किया गया है, न मजदूरों का जिक्र किया गया है, न बेरोजगार नौजवानों का जिक्र आया है और इस अभिभाषण को देखने से ऐसा लगता है कि इसमें कोई तथ्य की चीज ही नहीं है। इससे पूर्व मैंने देश की ज्वलंत समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था, यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाये तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। आदेश सरकार का होता है, आदेश होते रहते हैं परन्तु कोई काम नहीं हो पाता। हम लोग मंत्री जी को पत्र लिखते हैं, उनका जवाब भी हमारे पास आता है परन्तु कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इस सरकार की स्थिति बड़ी डांवाडोल सी बन गई है। आज हाउस में भी हमें यही देखने को मिला कि कोरम के अभाव में, सदन की कार्यवाही तक यह सरकार नहीं चला सकी। इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है कि यह सरकार इस देश का कोई भी काम व्यवस्थित ढंग से चला सके, इसमें सक्षम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं और कहता हूं कि प्रधान मंत्री जी को आज ही इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस देश में करोड़ों लोग बसते हैं, लेकिन देश की जनता का कोई भविष्य नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार बिहार में फ्लड रिलीफ देने के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन इससे वहां के उजड़े किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। बिहार में आज 48 वर्षों में कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया है जब कि प्रति वर्ष भारत सरकार 100 करोड़, सिर्फ फ्लड रिलीफ पर खर्च करती रही है। इस प्रकार से देखा जाए, तो अरबों-खरबों रुपया भारत सरकार बिहार में खर्च कर चुकी है, लेकिन बिहार की कोई उन्नति नहीं हो सकी है। यदि इतना पैसा ईमानदारी से खर्च किया गया होता, तो अकेला बिहार ही पूरे देश को अन्न खिला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिहार में किसानों की उपेक्षा की गयी है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में आज मजदूरों की समस्या बहुत जटिल हो गयी है। खासकर दिल्ली में बिहार से आए मजदूरों की समस्यायें बहुत जटिल हैं। बिहार में लाखों की संख्या में मजदूर आये हैं। बिहार के अलावा भी देश के कोने-कोने से यहां लाखों की संख्या में मजदूर आकर रह रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज तक कोई कारंवाई नहीं की गयी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है जिससे पता चले कि देश की इस महानगरी में इन मजदूरों के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। बेरोजगारी का सवाल आज देश में बहुत उठ रहा है। करोड़ों लोग इस देश में बेकार पड़े हैं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय,

मैं मांग करता हूं कि इस सरकार को और प्रधान मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए०एन० सिंह देव (आस्का) : महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और मित्रों द्वारा उठाए गए खाड़ी के मुद्दे पर विशेष रूप से दो शब्द कहूंगा। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दूसरे पक्ष के मित्रों ने यह आभास दिया कि मानो भारत के कंधों पर ही पूरे विश्व का भार है। उन्होंने सरकार की इस बात के लिए निन्दा की कि जब इराक जल रहा था तो यह खामोश रही। मैं दूसरे पक्ष के अपने मित्रों से यह पूछना चाहता हूं कि अन्य देश इस संबंध में क्या कर रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब रूस में वर्षा होती थी तो हमारे साथी भारत में छाता तान लेते थे। अब जबकि रूस ने स्पष्ट तौर पर इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का समर्थन किया था, जब न केवल अमरीका, इंगलैंड या फ्रांस बल्कि कई अरब देशों ने भी कुवैत पर इराकी कब्जे की स्पष्ट रूप से निंदा की और हमारे मित्र कहना चाहते हैं कि जब इराक युद्ध की विभीषिका में जल रहा था तो भारत चुप्पी साधे था। यह बहुत ही विचित्र दृष्टिकोण है।

वे प्रधान मंत्री पर मुम्बई में अमरीकी विमानों को ईंधन की सुविधा देने का आरोप लगाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है या अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकता है कि जब एक देश का विमान दूसरे देश से गुजरता है तो उन्हें ईंधन लेने की अनुमति दी जाती है अन्यथा हम यह कैसे जान पाएंगे कि विमान में क्या ले जाया जा रहा है। यह साफ-साफ बता दिया गया है कि विमानों में अग्नेयास्त्र या युद्ध में काम आने वाले यंत्र नहीं ढोए जाएंगे। इसके बावजूद हमारे मित्र प्रधान मंत्री पर आरोप लगाना चाहते हैं। हमारे जिन मित्रों ने स्पष्ट शब्दों में इराक का समर्थन करने की बात कही है, वह इराक को पूरा अरब विश्व मानते हैं। यह बहुत हैरानी की बात है। एक अरब देश को पूरा अरब विश्व माना जा रहा है। साउदी अरब, कुवैत, मिस्र और तुर्की के बारे में आपकी क्या राय है ? क्या वह मुस्लिम देश नहीं हैं ? क्या वह इराक के विरुद्ध नहीं हैं ? ऐसा क्यों हो कि अमरीका द्वारा आक्रमण का विरोध करने के लिए केवल भारत, माननीय प्रधान मंत्री और इस सरकार पर ही आरोप लगाए जाएं ?

महोदय, हम अवश्य यह अनुभव करें कि इस विश्व में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विश्व में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जो गुट-निरपेक्षता की नीति 20 वर्ष, 15 वर्ष अथवा 10 वर्ष पहले थी, वह अब बिल्कुल बदल गई है। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है तब गुट-निरपेक्षता का कोई महत्व नहीं रहा। हमें इस नए ढांचे के अनुरूप अपने-आप को तैयार करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा पक्ष लें। यह तो ठीक है कि हम अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति को नहीं छोड़ेंगे लेकिन, इस वर्तमान संदर्भ में गुट-निरपेक्षता की नीति का महत्व नहीं रहा है। हमें यह बात समझनी चाहिए। जब किसी बात का महत्व नहीं रहता, तब उसके पक्ष में होने अथवा गुट-निरपेक्षता करने की बात करने का कोई लाभ नहीं है। रूस और अमरीका जैसे देशों ने आपसी शीत युद्ध समाप्त कर दिया है और वे नई विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मित्र श्री गोर्बाचोव ने कहा है कि अमरीका और रूस नई विश्व व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। इस नई विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका होगी ? 20 अथवा 10 वर्ष पुराने सिद्धांतों और नीतियों की बात करने का कोई लाभ नहीं है। दुर्भाग्यवश वामपंथी दलों के हमारे मित्र

[श्री ए०एन० सिंह देव]

दूरदर्शिता से काम लेना नहीं जानते। मेरा कहना है कि वे दूरदृष्टि का उपयोग करें। वे पुराने सिद्धांतों की बात करने की बजाय भविष्य की ओर देखें। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और विश्व में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उन्हें इस बात को अनुभव करना चाहिए। भारत को स्वयं को बदलना चाहिए। भारत को अपना रवैया और नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूं। वास्तव में हमें गुट-निरपेक्ष ही रहना चाहिए लेकिन, गुट-निरपेक्षता के मुद्दे का महत्व अब नहीं रहा है। इसलिए, इस सरकार की आलोचना करने से पहले हमें देखना चाहिए कि विश्व में वर्तमान संदर्भ में कौन सी नीति व्यावहारिक है। इस मुद्दे के इस पहलू पर बोलते हुए मैं अभिभाषण देने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को विश्व की वर्तमान स्थिति के प्रति उपयुक्त रवैया अपनाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस बहस को समाप्त करने के लिए मैंने नियम 362 के अंतर्गत एक सूचना दी थी। मुझे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया था कि धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे चर्चा की जाएगी। अभी तक हमने केवल 4 घंटे चर्चा की है। अभी आठ घंटे शेष हैं। आज आठ घंटे तक चर्चा करना संभव नहीं है। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। जो सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, और मतदान करना चाहते हैं, उन्हें कल बोलने और मतदान करने का अधिकार है। हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम ऐसा निर्णय लें और आपको इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें। कार्य मंत्रणा समिति में इस बारे में निर्णय लिया गया था। वह प्रतिवेदन सभा में भी प्रस्तुत किया गया था। सभा ने भी उस प्रतिवेदन को स्वीकार किया था। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए निर्धारित किया गया समय अभी शेष है।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा सर्वोच्च है। वह निर्णय ले सकती है। आप सभा की भावना जान लें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप अपने स्वविवेकाधिकार से इस प्रकार के प्रस्ताव को अनुमति न दें। इस बारे में उचित और पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए। यह निर्णय लेना आप पर निर्भर करता है कि क्या उचित चर्चा हो चुकी है। अभी उचित और पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। चूंकि हम अपने विचार प्रकट करने के लिए यहां उपस्थित हैं, इसलिए आप हमें बोलने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे निर्णय लेने का समय तो दीजिए। मैं निर्णय ले रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप अपने स्वविवेकाधिकार से इसे अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि अभी तक पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वही तो कर रहा हूं।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, जिसका आपने

उल्लेख किया है, के बाद अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं ने ऐसा गंभीर रूप ले लिया है कि हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारा विचार है कि जो बहस की जा रही है, वह बेकार है। परिस्थितियां उस परिधि से बाहर हो चुकी हैं जबकि कार्य मंत्रणा समिति ने आपको यही सिफारिश की है फिर भी हमारा सुझाव है कि निर्णय करने का अधिकार सभा को है। हम आपके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और यह निर्णय करना सभा का अधिकार है कि प्रस्ताव को स्वीकृति दे या नहीं। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको स्वविवेकाधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय दे रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप अपना विनिर्णय कैसे देंगे। कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निराश नहीं होंगे। मैं नियम 362 के प्रावधान पढ़ रहा हूं। इसके अनुसार :

> "किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा : 'कि अब प्रश्न रखा जाए' और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद अधिकार का उल्लघंन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा : 'कि अब प्रश्न रखा जाए'।"

मेरे विचार में चर्चा को इस समय समाप्त करने से, हम उन सदस्यों को अवसर नहीं दे रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं और मैं इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप सभा की भावनाओं को समझें।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि कितने वक्ता रह गए हैं और वे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कितना समय लेंगे ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकते। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैंने नियम का भी उल्लेख किया है। यह पीठासीन अधिकारी की मर्जी पर होता है कि वह इस प्रकार के प्रस्ताव की अनुमति दे या नहीं। यदि मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं कि इससे एक उचित विषय पर बहस रुक जाती है, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा और मैं नहीं समझता कि मुझे इस प्रकार के प्रस्ताव को अनुमति नहीं देनी चाहिए इस से सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के अवसर से वंचित रह जायेंगे।

डा० बिप्लव दासगुप्त : पीठासीन अधिकारी के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? आप इसे विशेषाधिकार की अवमानना क्यों समझते हैं ? **(व्यवधान)** कितने वक्ता बच गए हैं ? इस लम्बी बहस को जारी रखने से क्या लाभ हैं ? क्या आप नहीं देख सकते कि अब राजनैतिक आपसी सम्बन्ध बदल गए हैं ? ठीक आधा घण्टा पहले सभी सदस्य बाहर खड़े हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मेरे सामने नहीं हो रहा है मुझे उसके बारे में कैसे जानकारी हो सकती है।

डा० विप्लव दासगुप्त : क्या इस बहस से कोई फायदा होगा ?

श्री वसुदेव आचार्य : वक्ता उपस्थित हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई वक्ता नहीं है ? स्वयं मुझे 12 घण्टे लगेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : यदि वक्ता बोलने के लिए तैयार हैं और उनकी संख्या समाप्त हो जाती है और बोलने के लिए कोई सदस्य नहीं रह जाता है और प्रस्ताव आपके सामने है तो आप मतदान के लिए प्रश्न रख सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। आप अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह एक विद्वेषपूर्ण प्रस्ताव था। **(व्यवधान)**

3.00 म०प०

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : महोदय, विद्वेषपूर्ण प्रस्ताव क्या होता है ?

डा० विप्लव दासगुप्त : इसके बारे में विद्वेषपूर्ण क्या है ? महोदय, अवमानना कहां हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

डा० विप्लव दासगुप्त : हमारी भावना है कि राजनैतिक वास्तविकता पूरी तरह से बदल गई है। महोदय, यदि आप चाहें तो, चर्चा को जारी रख सकते हैं...**(व्यवधान)** किन्तु, हमें इस विषय को पुनः उठाने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु हम समापन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि आप विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकते।.....

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम महसूस करते हैं कि इस बहस को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : ..... आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाय और चर्चा आगे चलाई जाय क्योंकि इसमें प्रधान मंत्री जी को भी उत्तर देना है, प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे लेकिन, आज प्रधान मंत्री जी.....**(व्यवधान)**.....

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री जी आ जायें और उत्तर दे दें, इसमें क्या है ?..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० बिप्लव दासगुप्त : यदि कोई वक्ता उपस्थित है, तो हम उन्हें बोलने से नहीं रोकना चाहते; किन्तु, हमें इस प्रश्न को पुनः उठाने का अधिकार प्राप्त है·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय . आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उन्होंने विनिर्णय दे दिया है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

(**व्यवधान**)

डा० बिप्लव दासगुप्त : आपके विनिर्णय के विरुद्ध कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे तुरन्त उठाएंगे अर्थात् एक मिनट के पश्चात् ?

डा० बिप्लव दासगुप्त : नहीं; जो बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि चर्चा आज ही समाप्त होनी होती और यदि केवल दो घण्टे दिए गए होते और यदि आज सभा में और कोई वक्ता न होता, तो यह जानने के बाद कि कोई भी वक्ता नहीं है, मैं तुरन्त प्रश्न को मतदान के लिए रख देता; किन्तु, केवल 12 घण्टों का समय दिया गया है और यह समय कल तक भी बढ़ाया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या कल सदस्य सदन में आने वाले हैं या नहीं। मतदान बारह घण्टों के बाद किया जाना है। यह एक प्रकार की परिकल्पना है·····

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : बशर्ते आपकी सूची में वक्ता हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास वक्ता हैं; बहुत अधिक वक्ता हैं। मेरे पास 50 से अधिक वक्ता हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : दलों को दिए गए समय के भीतर·····(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आप जितना समय चाहें नहीं दे सकते। क्या आप जनता दल(एस) को जितना समय चाहें दे सकते हैं ?·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : आप नहीं दे सकते। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें और अधिक समय नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आप उन्हें जितना समय चाहें नहीं दे सकते। उनके पास सीमित समय है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें और एक-एक कर बोलें।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने जनता दल(एस) को कितना समय दिया है? उनके लिए भी समय-सीमा है। (**व्यवधान**) आप उन्हें जितना चाहें समय नहीं दे सकते और न ही असीमित संख्या में वक्ताओं को बोलने की अनुमति दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

डा० विप्लव दासगुप्त : हम इसके विरोध में बहिष्कार कर रहे हैं।

इस समय डा० विप्लव दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब स० अतिन्दर पाल सिंघ।

सिंघ साहब, क्या आप बोलने के इच्छुक हैं?

(**व्यवधान**)

स० अतिन्दर पाल सिंघ (पटियाला) : जी हां, महोदय, मैं बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है। मैं गणपूर्ति के लिए आग्रह कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह हक है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इस सभा में गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति की घण्टी बजाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि बार-बार घण्टी बजाए जाने के बावजूद सभा में कोरम पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए, अब सभा कल ग्यारह बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

3.12 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 मार्च, 1991/15 फाल्गुन, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867, चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006